राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

गौरवशाली भारत

दिल्ली से प्रकाशित

R.N.I. NO. DELHIN/2011/38334 वर्ष- 10, अंक- 327 पृष्ठ - 08, नई दिल्ली, शुक्रवार, 04 जून 2021, मूल्य रु. 1.50

वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से की बात, भारत आने का दिया न्योता

नई दिल्ली, एजेंसी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से बात की और भारत को वैक्सीन आपूर्ति का आश्वासन देने के लिए अमेरिका की सराहना की। अमेरिका ने वैश्विक टीका साझेदारी के तहत भारत को भी वैक्सीन देने का आश्वासन दिया है। इसके तहत भारत को इस माह के अंत तक वैक्सीन की खेप मिलने की उम्मीद है। एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री ने अमेरिकी सरकार, कारोबारियों और प्रवासी भारतीयों से मिले सहयोग और एकजुटता के लिए भी कमला हैरिस का शुक्रिया अदा किया।

उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा, भारत-अमेरिका के बीच टीका साझेदारी को और मजबूत करने के लिए जारी प्रयासों तथा कोविड-19 के बाद स्वास्थ्य व आर्थिक क्षेत्र के सुधार में योगदान देने की दोनों देशों की साझेदारी की संभावनाओं पर भी हमने चर्चा की।

अमेरिकी दूतावास ने भी हैरिस के वरिष्ठ सलाहकार और मुख्य प्रवक्ता का बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी समेत चार देशों के नेताओं के साथ उनकी बातचीत का जिक्र किया। इस बातचीत में इस माह के अंत तक भारत और अन्य देशों को वैक्सीन आपूर्ति की योजना पर चर्चा हुई।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक स्वास्थ्य स्थिति के सामान्य होने के तुरंत बाद भारत में अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैरिस के स्वागत की उम्मीद जताई है।

नेताओं ने वैक्सीन निर्माण के क्षेत्र में अमेरिका और भारत सहित स्वास्थ्य आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए चल रहे प्रयासों पर चर्चा की। उन्होंने महामारी के दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभाव को संबोधित करने में क्वाड के तहत भारत-अमेरिका साझेदारी के साथ-साथ वैक्सीन पहल की क्षमता पर प्रकाश डाला। क

पिछले दिनों अमेरिकी दौरे के अंत में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया था कि कोरोना को लेकर कई मोर्चों पर दोनों देशों के बीच सहयोग की राह खुलेगी। जयशंकर ने कहा, कोशिश है कि अमेरिका की मदद से भारत में वैक्सीन निर्माण का काम तेज किया जाए। वैक्सीन निर्माण को लेकर अमेरिका से भारत की एक तो सीधे तौर पर बात हो रही है और दूसरा क्वाड के तहत निर्माण को लेकर भी अलग से बात हो रही है।

जयशंकर ने इसे द्विपक्षीय वार्ताओं का सबसे महत्वपूर्ण विषय करार दिया। उन्होंने यह भी कहा कि जहां तक वैक्सीन निर्माण बढ़ाने का सवाल है तो यह अमेरिका से जुड़ा हुआ है। इसको उन्होंने स्पष्ट तो नहीं किया, लेकिन संभवतः उनका इशारा अमेरिका से कच्चे माल की आपूर्ति को लेकर था।

एक नज़र...

हाईकोर्ट ने गौतम गंभीर फाउंडेशन को पाया दोषी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली हाईकोर्ट ने नामी हस्तियों और नेताओं द्वारा कोरोना की दवाओं की जमाखोरी को लेकर डाली गई याचिका पर सुनवाई करते हुए गौतम गंभीर फाउंडेशन को फैबिफ्लू की जमाखोरी का दोषी पाया है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के ड्रग्स कंट्रोलर ने हाईकोर्ट को बताया कि गौतम गंभीर फाउंडेशन कोविड-19 मरीजों के उपचार में उपयोगी दवाई फैबिफ्लू की अनधिकृत तरीके से जमाखोरी, खरीदने और उसका वितरण करने का दोषी पाया गया है। ड्रग्स कंट्रोलर ने अदालत में कहा कि फाउंडेशन और दवा डीलरों के खिलाफ बिना किसी देरी के कार्रवाई की जाए।

योगगुरु बाबा रामदेव को समन जारी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। एलोपैथी बनाम आयुर्वेद विवाद में लगातार आ रहे बाबा रामदेव के आपत्तिजनक बयानों को लेकर अब दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन (डीएमए) हाईकोर्ट पहुंच गया है। डीएमए ने दिल्ली हाईकोर्ट में रामदेव के खिलाफ केस दायर कर उन्हें कोरोनिल टेबलेट को लेकर झूठे दावे और गलत बयानबाजी करने से रोकने की अपील की है। हाईकोर्ट ने योग गुरु रामदेव को, पतंजलि की 'कोरोनिल किट' के कोविड-19 के उपचार के लिए कारगर होने की झूठी जानकारी देने से रोकने डीएमए की ओर से दायर वाद पर योग गुरु को समन जारी किया।

नशे के खिलाफ मुहिम में 450 लोग गिरफ्तार

गुवाहाटी, (एजेंसी)। असम पुलिस ने नशे के खिलाफ शुरू की गई मुहिम के तहत बीते 24 दिनों में 450 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। 10 से 31 मई के दौरान 264 मामले दर्ज किए गए और 441 लोगों को गिरफ्तार किया। विभिन्न जिलों में रोज गिरफ्तारियां हो रही हैं। हिमंत बिस्व सरमा ने 10 मई को मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद नशीले पदार्थों के विक्रेताओं पर कार्रवाई का आदेश दिया था। सरमा ने हाल में कहा था कि राज्य सरकारों का लक्ष्य नशीले पदार्थों से मुक्त समाज बनाना है और असम पुलिस नशीली दवाओं की खरीद-बिक्री पर कड़ा रुख अपनाएगी।

असमिया साहित्यकार लक्ष्मीनंदन का निधन

गुवाहाटी, (एजेंसी)। असम के जाने-माने साहित्यकार लक्ष्मीनंदन बोरा का गुरुवार को निधन हो गया। कोविड के बाद उत्पन्न स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के चलते वे गुवाहाटी के एक निजी अस्पताल में भर्ती थे। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने बोरा के निधन पर शोक जताया। उन्होंने कहा कि साहित्यकार की अंत्येष्टि पूरे राजकीय सम्मान के साथ की जाएगी। बोरा 89 वर्ष के थे। उनके परिवार में पत्नी, दो बेटे और एक बेटी है।

सीबीएसई-सीआईएससीई से दो हफ्ते में मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने की सुनवाई: पूछा किस आधार पर तय करेंगे 12वीं का रिजल्ट?

नई दिल्ली ■ एजेंसी

सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द करने और मूल्यांकन मानदंड की मांग वाली याचिका की सुनवाई दो हफ्ते के लिए स्थगित कर दी है। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने सीबीएसई और सीआईएससीई को छात्रों का आकलन करने वैकल्पिक मूल्यांकन मानदंड के साथ आने दो हफ्ते दिए हैं, यानी दो हफ्तों में सीबीएसई और सीआईएससीई को वह विकल्प बताना होगा, जिसके आधार पर वे रिजल्ट तैयार करने वाले हैं।

केंद्र ने पहले ही सीबीएसई 12वीं परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जानना चाहता है कि रिजल्ट तैयार करने मूल्यांकन मानदंड क्या होंगे। वहीं अधिवक्ता अनुभा श्रीवास्तव ने एक नई याचिका दायर की है, इसमें 26 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को अपने-अपने बोर्डों को 12वीं बोर्ड परीक्षा रद्द करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

सीबीएसई तीन सप्ताह में मूल्यांकन पर लेगा निर्णय

गुरुवार की सुनवाई में, अटॉर्नी जनरल ने बताया कि सीबीएसई तीन सप्ताह में मूल्यांकन मानदंड पर निर्णय लेगा। आईसीएसई के वकील ने यह भी सूचित किया है कि उनके पास विशेषज्ञों की एक समिति है, जो जल्द मानदंड पर निर्णय लेगी। मानदंड का चुनाव करने के लिए दोनों पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कुछ समय देने का अनुरोध किया। हालांकि सीबीएसई और सीआईएससीई ने जवाब देने के लिए चार हफ्ते का वक्त मांगा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो छात्र विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए देर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि दो हफ्ते का वक्त पर्याप्त है।

बोर्डों को प्रक्रिया में तेजी लाने की जरूरत- एडवोकेट ममता शर्मा ने चिंता जताई कि बोर्डों को प्रक्रिया में तेजी लाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पिछले साल यह प्रक्रिया 15 जुलाई, 2021 से पहले आयोजित की गई थी।

सीबीएसई 12वीं के छात्रों और अभिभावकों के साथ बैठक में अचानक शामिल हुए पीएम

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीबीएसई 12वीं के छात्रों और अभिभावकों के साथ हो रही वर्चुअली बैठक में अचानक गुरुवार को शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने छात्रों और उनके पैरेंट्स से बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों से कहा कि उन्हें परीक्षाओं के बारे में कभी चिंता नहीं करना चाहिए। परीक्षा रद्द करने का यह फैसला उनके हितों में लिया गया है। स्वास्थ्य ही धन है और वे शारीरिक तौर पर फिट रहने जो करना है वो करें, इसके साथ ही, पीएम ने छात्रों से पूछा कि वे अब आगे अपना कैसे व्यतीत करेंगे? क्या वे आईपीएल देखेंगे, चैंपियन लीग या फिर ओलंपिक का इंतजार करेंगे? इसके जवाब में छात्रों ने बताया कि जैसे ही परीक्षा रद्द हो गई उनका तनाव खत्म हो गया। अब हम पूरा फोकस प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं पर करेंगे और उसकी तैयारियों में जुट जाएंगे।

बंगाल हिंसा को लेकर 100 से अधिक शिक्षाविदों ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र,एससी/एसटी के लिए सुरक्षा की मांग

नई दिल्ली। विधानसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल कई हिंसा का गवाह बना। हिंसा दो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच हुई। इसको लेकर बंगाल के सामाजिक विकास केंद्र और 100 से अधिक शिक्षाविदों ने राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद को पत्र लिखकर चुनाव के बाद हुई हिंसा के बाद एससी और एसटी समुदायों की सुरक्षा के लिए तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राज्य पुलिस के सहयोग से एससी/एसटी समुदाय को निशाना बनाया है और उनकी हत्या, लूटपाट, बलात्कार और भूमि कब्जा करने के लिए हिंसा फैलाई है। ज्ञापन में कहा गया है, 11,000 से अधिक लोग, जिनमें से अधिकांश एससी और एसटी समुदाय से हैं, बेघर हो गए हैं और 40,000 से अधिक लोग क्रूर हमलों की लगभग 1627 घटनाओं में प्रभावित हुए हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि 5,000 से अधिक घरों को ध्वस्त किया गया और 142 महिलाओं के साथ अमानवीय अत्याचार और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति समुदाय के 26 लोगों की मौत रजिस्टर की गई है। इन्होंने आरोप लगाया है कि एससी और एसटी समुदाय के घरों, उनकी छोटी दुकानों को ध्वस्त और जला दिया गया और उन्हें फिर से अपने घरों में नहीं आने की धमकी दी गई। ज्ञापन में कहा गया, हिंसा के परिणामस्वरूप, असम, ओडिशा और झारखंड में 2,000 से अधिक लोग आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों के रूप में शरणार्थी बन गए। इसमें कहा गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय को जंगली हिंसा का सामना करना पड़ा है और उन्हें अपने घरों के पुनर्निर्माण में सक्षम होने और उचित सुरक्षा और चिकित्सा और अन्य सुविधाओं के आश्वासन की आवश्यकता है। ज्ञापन में कहा गया है, हम आपसे तत्काल हस्तक्षेप करने और एससी और एसटी समुदाय को बचाने और पश्चिम बंगाल में सामाजिक सुरक्षा का आश्वासन देने का आग्रह करते हैं। हस्ताक्षर करने वालों में राजस्थान के लालोस्ट के राजेश पायलट गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर सुभाष पहाड़िया के अनुसार, कोई भी चुनाव जीत सकता है, लेकिन प्रतिद्वंद्वी पार्टी का समर्थन करने वालों के खिलाफ अत्याचार करना गलत है। उन्होंने कहा, मीडिया रिपोर्टों का संज्ञान लेते हुए, हमने चुनाव परिणामों के बाद सत्तारूढ़ दल द्वारा पश्चिम बंगाल में एससी, एसटी समुदाय के खिलाफ किए जा रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

नीति आयोग ने जारी की एसडीजी 2020-21 रिपोर्ट, केरल फिर अव्वल और बिहार फिर फिसड्डी

नई दिल्ली। नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डेशबोर्ड 2020-21 के तीसरे संस्करण को जारी कर दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक केरल एक बार फिर से इसमें नंबर वन के स्थान पर काबिज है। वहीं बिहार पहले की ही तरह इस सूची में सबसे नीचे है। इसका सीधा सा अर्थ है कि बिहार की प्रोग्रेस रिपोर्ट और उसका प्रदर्शन बेहद खराब है। ये रिपोर्ट राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की आर्थिक और पर्यावरण का आंकलन करते हुए तैयार की गई है। इस रिपोर्ट में केरल को 75 अंक हासिल हुए हैं। जबकि हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु को एक समान 74 अंक हासिल हुए हैं और ये दूसरे नंबर पर काबिज हैं। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों की बात करें तो इसमें केवल बिहार ही शामिल नहीं है बल्कि असम और झारखंड भी है।

आपको बता दें कि वर्ष 2018-19 की रिपोर्ट में 13 गोल, 39 टार्गेट, 62 इंडीकेटर्स शामिल थे जबकि 2019-20 में 17 गोल, 54 टार्गेट, और 100 इंडीकेटर्स को इसका मापक बनाया गया था। इसी तरह से मौजूदा रिपोर्ट में 17 गोल, 70 टार्गेट और 115 इंडीकेटर्स को किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की तरक्की का पैमाना बनाया गया था। इसी तरह 2030 के लिए 17 गोल और 169 संबंधित लक्ष्य का पैमाना राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए रखा गया है।

इसकी शुरुआत पहली बार 2018 में की गई थी और अब ये तीसरे वर्ष में प्रवेश कर गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इन लक्ष्यों की प्राप्ति के आधार पर रेंकिंग भी दी गई है।

वायुसेना के शीर्ष अधिकारियों में बड़ा बदलाव, एयर मार्शल वीआर चौधरी होंगे अगले वाइस चीफ

नई दिल्ली । वायुसेना के शीर्ष अधिकारियों में बड़ा बदलाव किया गया है। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को वायु सेना मुख्यालय में अगले वायु सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। 30 जून को वह अपना पदभार ग्रहण करेंगे। बता दें कि वर्तमान में चौधरी वेस्टर्न एयर कमांड की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। पिछले साल अगस्त में भारतीय वायुसेना के वेस्टर्न एयर कमांड के एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के तौर पर उन्होंने पदभार संभाला था।

नेशनल डिफेंस एकेडमी के पूर्व छात्र एयर मार्शल वीआर चौधरी को वायुसेना में फाइटर पायलट के तौर पर 29 दिसंबर 1982 में शामिल किया गया था। वह अब तक कई मुख्य पदों का कार्यभार संभाल चुके हैं। बता दें कि इंडियन एयरफोर्स की स्2श्हस्त्ऱ्हद्ध के रूप में जाने जाने वाली वेस्टर्न एयर कमांड लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में चीन और पाकिस्तान दोनों से लगी भारत की सीमाओं की निगरानी करती है। बता दें कि वेस्टर्न एयर कमांड के चीफ के तौर पर एयर मार्शल विवेक चौधरी की पोस्टिंग ऐसे समय पर हुई थी, जब पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (एलएसी) पर भारत और चीन के बीच सीमा पर काफी विवाद बढ़ गया था। इसके अलावा पाकिस्तान लगातार बॉर्डर पर अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा था।

एयर मार्शल विवेक चौधरी को सैन्य पुरस्कार 'अति विशिष्ट सेवा मेडल' देकर सम्मानित किया जा चुका है। बता दें कि यह पुरस्कार 'उत्तम युद्ध सेवा मेडल' के बराबर है। वर्ष 1982 में कमीशंड होने के बाद विवेक चौधरी 1993 में स्क्वाड्रन लीडर बने।

अमेरिका से हंटर ड्रोन खरीदने नौसेना ने किया केंद्र सरकार से संपर्क

नई दिल्ली, (एजेंसी)। हाल में चीन ने एलएसी के नजदीक कुछ ऐसी गतिविधियां की हैं, इसके बाद भारत चौंकन्ना हो गया है। भारतीय नौसेना ने देश को और मजबूत करने रक्षा मंत्रालय से संपर्क किया है और अमेरिका से 30 प्रीडेटर ड्रोन्स को खरीदने के लिए कहा है।

चीन की गतिविधियों से भारत चौंकन्ना

इन ड्रोन्स के मिलने के बाद ये चीन के विंग लूंग II से आसानी से टक्कर ले सकेंगे और जरूरत पड़ने पर ड्रैगन समेत अन्य देशों पर भारी पड़ेंगे। चीनी हथियार वाले ड्रोन पाक ने खरीदा है व मूल निर्माता चेंगदू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ संयुक्त रूप से इसका प्रोडक्शन करने की योजना है। भारतीय नौसेना, जिसे एमक्यू-9 ड्रोन की खरीद के लिए सेना और वायु सेना दोनों के नेतृत्व के रूप में नॉमिनेट किया है, ने रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार की अध्यक्षता में रक्षा खरीद बोर्ड की बैठक जल्द बुलाने कहा है, इसके बाद परियोजना को मंजूरी दी जा सके। एक बार जब डीपीजी परियोजना को मंजूरी दे देता है, तो नौसेना खरीद की आवश्यकता की स्वीकृति के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद का रुख करेगी, जो सरकार के तहत अमेरिकी विदेशी सैन्य बिक्री मार्ग के जरिए सरकारी योजना के लिए किया जाएगा।

आरजेडी सांसद अमरेंद्र धारी सिंह को ईडी ने किया गिरफ्तार

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने विदेशों से आने वाली फर्टिलाइजर में 800 करोड़ की कमीशनखोरी को लेकर दर्ज मामले में आरजेडी सांसद एडी सिंह को गिरफ्तार किया है। कमीशनखोरी के मामले में इफको और इंडियन पोटाश लिमिटेड के प्रबंध निदेशकों समेत अगस्ता वेस्टलैंड मामले का आरोपी राजीव सक्सेना भी शामिल है।

राष्ट्रीय जनता दल से राज्यसभा के सांसद अमरेंद्र धारी सिंह के बारे में बताया जाता है कि जब वे राज्यसभा सांसद उम्मीदवार के तौर पर सामने आए तो आरजेडी के ही लोग इन्हें नहीं जानते थे। अब ईडी ने अमरेंद्र को विदेशों से आने वाली खाद में दलाली व मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि अमरेंद्र धारी सिंह और उनके सहयोगियों ने इंडियन पोटाश लिमिटेड और इफको के बड़े अधिकारियों के साथ मिलकर विदेशों से आने वाली खाद को बढ़े हुए मूल्यों पर खरीदा दिखाया और इस बारे में दलाली के पैसे को विभिन्न कंपनियों में मनी लॉन्ड्रिंग भी किया।

फर्टिलाइजर घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप

विदेश मंत्रालय ने कहा, मेहुल चोकसी को भारत वापस लाकर रहेंगे, डोमिनिका में पूरी की जा रही हैं कानूनी प्रक्रियाएं

नई दिल्ली । विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि भारत अपने इस संकल्प पर कायम है कि भगोड़ों को देश वापस लाया जाए और धोखाधड़ी के मामले में वांछित मेहुल चोकसी को वापस लाने के लिए सारी कोशिशें जारी रखी जाएंगी।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने डिजिटल माध्यम से साप्ताहिक प्रेस वार्ता में कहा, वह (चोकसी) अभी डोमिनिका में हिरासत में है जहां कुछ कानूनी प्रक्रियाएं चल रही हैं। हम सारी कोशिशें जारी रखेंगे ताकि उसे (चोकसी) भारत वापस लाया जाए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से चोकसी के प्रत्यर्पण को लेकर सवाल पूछा गया था जो अभी डोमिनिका में हिरासत में है।

चोकसी हाल ही में एंटीगुआ एवं बारबुडा से फरार हो गया था और उसे कैरिबियाई देश में कथित तौर पर अवैध रूप से प्रवेश करने के आरोप में 23 मई को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके खिलाफ डोमिनिका में कानूनी प्रक्रिया चल रही है। चोकसी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में 13,500 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में वांछित है।

उधर वरिष्ठ वकील और प्रत्यर्पण मामलों के विशेषज्ञ उज्ज्वल निकम ने भी चोकसी को शीघ्र भारत लाए जाने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि डोमिनिका की अदालत में अभी जो प्रक्रिया चल रही है उसमें कुछ समय लगेगा। जैसे ही यह प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी उसे भारत लाने का रास्ता साफ हो जाएगा।

चोकसी को नहीं मिली जमानत

डोमिनिका के एक मजिस्ट्रेट ने मेहुल चोकसी को जमानत देने से इनकार कर दिया। स्थानीय मीडिया में यह जानकारी दी गई है। चोकसी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर रहे डोमिनिका हाई कोर्ट ने अवैध प्रवेश के आरोपों का सामना करने के लिए उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने का आदेश दिया। गुरुवार को चोकसी व्हीलचेयर पर मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुआ जहां उसे जमानत नहीं मिली। मजिस्ट्रेट को बताया गया कि चोकसी के खिलाफ भारत में धोखाधड़ी के 11 मामले चल रहे हैं। एंटीगुआ में प्रत्यर्पण की कार्यवाही चल रही है। साथ ही उसकी तलाश में इंटरपोल ने रेडकार्नर नोटिस जारी कर रखा है। इसके बाद मजिस्ट्रेट ने जमानत देने से इन्कार करते हुए मामले की सुनवाई 14 जून तक टाल दी।

मंत्रियों की भूमिका बदलेगी, नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा

दिल्ली में तैयार होगा ऑपरेशन यूपी का ब्लू प्रिंट

लखनऊ ■ एजेंसी

भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) बीएल संतोष तीन दिन के यूपी दौरे के बाद बुधवार दिल्ली लौट गए। इस दौरे में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर संगठन और सरकार के प्रमुख लोगों से बातचीत की। कुछ मंत्रियों की सुनी और उनकी क्षमता व योजना दृष्टि की थाह नापी। बैठकों में कोरोना में ऑक्सीजन एवं बेड की कमी और इस कारण बड़ी संख्या में हुई मौतों को लेकर गैरों के साथ भाजपा के लोगों की मुखर हुई नाराजगी की नब्ज टटोली गई। संतोष ने सरकार के प्रबंधन एवं तैयारियों के दावों की सच्चाई समझी, पंचायत चुनाव के भाजपा के पक्ष में अपेक्षित नतीजे न आने की वजहें जानने की कोशिश की। सरकार एवं संगठन की नब्ज पर हाथ रखकर बीमारियां समझीं और लौट गए। अब दिल्ली में ऑपरेशन यूपी 2022 का ब्लू प्रिंट तैयार होगा। इसमें पूरा जोर कोरोना महामारी से हुए नुकसान की भरपाई पर रहेगा। इसके तहत मंत्रिमंडल में कुछ बदलाव के साथ विस्तार एवं अधिकारियों की चुनाव तक नए सिरे से तैनाती हो सकती है। इस ब्लू प्रिंट का प्रभाव प्रदेश में बदलाव के रूप में तो सामने जरूर आएगा, लेकिन इसके कुछ मंत्रियों की भूमिका बदलने तथा नौकरशाही के कुछ चेहरों की काट-छांट तक ही सीमित रहने के आसार है।

पंचायत चुनाव ने बढ़ाई चिंता

प्रदेश की नौकरशाही को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं, सांसदों एवं विधायकों की शिकवा-शिकायतें शुरू से ही मुखर होती रही हैं। पर, कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भाजपा के ही लोगों का व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े करना और उसी बीच पंचायत चुनाव के नतीजे भाजपा की उम्मीदों के अनुसार न आना, संघ से लेकर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक की चिंता को बढ़ा गए हैं। भले ही संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले और भाजपा के बीएल संतोष के दौरे पूर्व निर्धारित थे, लेकिन दोनों ने अपने दौरे का एजेंडा बदलकर जिस तरह 2022 की चुनावी चुनौतियों के समाधान पर केंद्रित कर दिया, उससे इस चिंता को समझा जा सकता है।

भारत की वैक्सीन कंपनियों पर बढ़ा दुनिया का भरोसा, साथ काम करने को इच्छुक विदेशी कंपनियां

नई दिल्ली । भारत में कोरोना महामारी के खिलाफ वैक्सीन देने की प्रक्रिया भले ही अभी सुस्त हो, लेकिन भारत की वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के प्रति दुनिया का भरोसा लगातार बढ़ता जा रहा है। रूस की स्पुतनिक का निर्माण भारत में शुरू हो चुका है और अमेरिका की जानसन एंड जानसन को लेकर बातचीत काफी सही दिशा में बढ़ रही है। इस क्रम में अमेरिका की दिग्गज वैक्सीन निर्माता कंपनियों फाइजर व माडर्ना का नाम भी जल्द जुड़ने की संभावना है। यही नहीं वैक्सीन शोध में जुटीं कम से कम छह और अंतरराष्ट्रीय कंपनियां भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनियों के संपर्क में हैं। इनमें अमेरिका, कनाडा, यूरोप और जापान की कंपनियां शामिल हैं। हालांकि, अभी इस वार्ता के वैक्सीन निर्माण में बदलने में कुछ महीनों का समय लगेगा। सीरम इंस्टीट्यूट (एसआइआइ) के अलावा ये कंपनियां बायोलाजिकल ई, पैनेसिया जैसी बड़ी कंपनियों से बात कर रही हैं। जबकि भारत बायोटेक, जाइडस कैडिला और बायोलाजिक ई की एक वैक्सीन स्वदेशी है।

फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के सूत्रों ने बताया है कि यूरोप व अमेरिका स्थित जितनी वैक्सीन निर्माण से जुड़ी कंपनियां हैं, वह अब ज्यादा आर्डर लेने की स्थिति में नहीं हैं। इन कंपनियों की क्षमता विस्तार में कम से कम एक से दो साल का वक्त लगेगा। दूसरी तरफ भारत के पास अब भी कई विश्वस्तरीय वैक्सीन निर्माता कंपनियों के पास काफी अतिरिक्त क्षमता है।

अमेरिका, जापान व कुछ यूरोपीय देशों की कंपनियां वैक्सीन विकसित करने के अंतिम चरण में हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की अनुमति से इन कंपनियों को वैक्सीन शोध कार्य को आगे बढ़ाने की अनुमति मिली है। ये कंपनियां भारतीय कंपनियों से बात कर रही हैं ताकि डब्ल्यूएचओ से आपातकालीन परिस्थितियों में इस्तेमाल की अनुमति मिलने पर वे यहां निर्माण शुरू कर सकें। सनद रहे कि भारत को वैक्सीन निर्माण में दुनिया की राजधानी के तौर पर जाना जाता है। यहां दुनिया की कुल वैक्सीन की 60 फीसद बनाई जाती है। विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने गुरुवार को बताया भी कि भारत में कोविड-19 की वैक्सीन बनाने के लिए कई वैश्विक कंपनियों से बात चल रही है। भारत ना सिर्फ अपने यहां वैक्सीन बनाने के लिए विदेश से कच्चे माल का आयात करने के लिए बात कर रहा है, बल्कि पूरी वैक्सीन यहां बनाने के लिए भी विदेशी कंपनियों को आमंत्रित कर रहा है।

विदेश सचिव का इशारा संभवत अमेरिकी कंपनी फाइजर व माडर्ना को लेकर है, जिनके प्रतिनिधियों के साथ हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर की अमेरिका में बात हुई है। माना जा रहा है कि शुरुआत में ये दोनों कंपनियां पूरी वैक्सीन भारत को देंगी, लेकिन बाद में यहां निर्माण भी करेंगी। एक अन्य वैक्सीन कंपनी जानसन एंड जानसन की बात बायोलाजिकल ई से हो रही है। बायोलाजिकल ई अपनी वैक्सीन भी विकसित कर रही है और वह दूसरी कंपनियों की वैक्सीन भी बनाने को तैयार है।

वैक्सीन निर्यात अभी नहीं करेगा भारत- दुनिया के बढ़ते भरोसे के बावजूद भारत अभी दूसरे देशों को वैक्सीन निर्माण को लेकर कोई वादा नहीं करना चाहता। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि भारत की तरफ से वैक्सीन निर्यात पर प्रतिबंध लगाए जाने से 91 देशों को वैक्सीन आपूर्ति बाधित होने का खतरा है।

इस बारे में पूछे जाने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने साफ तौर पर कहा कि भारत के लिए अभी वैक्सीन की घरेलू जरूरत को पूरा करना वरीयता में है। ऐसे में दूसरे देशों को वैक्सीन आपूर्ति में मदद देने पर बात करना सही नहीं होगा। सनद रहे कि घरेलू स्तर पर वैक्सीन की कमी को दूर करने के लिए अप्रैल महीने में भारत ने देश से वैक्सीन निर्यात पर रोक लगा दी है।

चमगादड़ों से इंसानों में नए कोरोना वायरस के फैलने का खतरा ज्यादा, शोधकर्ताओं ने बताए ऐसे ग्लोबल हॉटस्पॉट

वाशिंगटन। वैश्विक महामारी कोरोना के प्रभाव और उससे बचाव को लेकर कई तरह के शोध किए जा रहे है। दरअसल, दुनियाभर के कई देशों में कोरोना वायरस के बदलते स्वरूप को लेकर खतरा बना हुआ है। वहीं, आने वाले दिनों में भारत समेत अन्य देशों में तीसरे और चौथे लहर से प्रभावित होने की बात सामने आ रही है। इन सबके बीच, अमेरिकी शोधकर्ताओं ने ऐसे हॉटस्पॉट बताए हैं, जहां न्यू कोरोना वायरस के फैलने की संभावना ज्यादा है। न्यू स्टडी में रिमोट सेंसिंग के इस्तेमाल जरिए चमगादड़ों की उपस्थिति की पहचान की गयी है।

बर्कले स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के शोधकर्ताओं के द्वारा यह स्टडी किया गया है। इसमें पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान और मैसी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूजीलैंड के शोधकर्ता भी शामिल थे। स्टडी पश्चिमी यूरोप से दक्षिण-पूर्व एशिया तक की रेंज में की गयी है। स्टडी में शोधकर्ताओं ने खुलासा करते हुए बताया है कि किन जगहों पर चमगादड़ों से नए कोरोना वायरस के इंसानों में फैलने का खतरा ज्यादा हो सकता है। खास बात यह है कि रिसर्च में जिन हॉटस्पॉट को चिन्हित किया गया है, उनमें से ज्यादातर इलाके चीन में हो सकते हैं।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, स्टडी में कोरोना वायरस के सक्रिय होने से जुड़ी जानकारी का उजागर करने पर ज्यादा फोकस किया गया है। स्टडी में जापान, उत्तरी फिलिपीन्स के कुछ हिस्सों को शामिल किया गया है। शोधकर्ता मारिया क्रिस्टिना ने इस स्टडी का उद्देश्य के बारे में बताते हुए कहा कि कि हम इस बारे में जानकारी एकत्रित कर रहे थे कि भविष्य में कोरोना वायरस कहां से पनप सकते हैं। उन्होंने बताया कि चमगादड़ के शरीर में वायरस की संख्या पंद्रह हजार तक हो सकती है।

तानाशाह किम ने किया बड़ा फेरबदल, कौन होगा उनका सेकेंड इन कमांड, संशय बरकरार

सियोल। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने बड़ा फेर-बदल करते हुए अपना नया सेकेंड-इन-कमांड का पद बनाया है। सीएनएन के मुताबिक सरकारी दस्तावेजों में ये नई पॉजीशन को जनवरी में बनाया गया था। इसका मकसद वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया के नियमों की समीक्षा करना है। हालांकि अभी इस बात का पता नहीं चला है कि इस पद पर किसको बिठाया गया है।

जानकारों का मानना है कि ये पद यो योंग वोन और किम टॉक हुन के हटने से खाली हुआ है, जो कि देश में और सरकार में दूसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। 60 वर्षीय जो उत्तर कोरिया में किम जोंग उन के सबसे अधिक विश्वासपात्र हैं और वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया की केंद्रीय कमेटी के सचिव भी रह चुके हैं। किम टोक हुन उत्तर कोरिया सरकार के प्रीमियर भी हैं। उत्तर कोरिया की स्थानीय मीडिया के मुताबिक जो और किम ने बैठक की अध्यक्षता की और इस वर्ष देश का दौरा भी किया है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया की पॉलिटब्यूरो स्टेंडिंग कमेटी का कोई वरिष्ठ सदस्य ही इस पद के लिए सही होगा। क्यूंग्नाम यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट स्कूल ऑफ नॉर्थ कोरियन स्टडीज के प्रोफेसर लिम उल चुल के मुताबिक इसका एक अर्थ ये भी है कि किम की बहन किम यो जोंग इस पद के लिए सही उम्मीद्वार नहीं हैं। जानकारों के मुताबिक किम का प्रभाव देश के सेकेंड इन कमांड के मुकाबले अधिक है। इसलिए वो इस पद पर काबिज नहीं होंगी।

अब पाकिस्तान सरकार की मिल्कियत हैं पेशावर स्थित राजकपूर और दिलीप कुमार की हवेली

पेशावर। हिंदी फिल्मों के लीजेंड शोमैन राजकपूर और ट्रेजडी किंग दिलीप कुमार के पेशावर स्थित पुश्तैनी हवेलियों को खैबर पख्तूंख्वां के डायरेक्टरेट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम ने अपने कब्जे में ले लिया है।

इस संबंध में पेशावर के डिप्टी कमिश्नर ने एक अधिसूचना भी जारी कर दी है जिसमें इसके मालिकाना हक में हुए बदलाव के बारे में बताया गया है। गौरतलब है कि खैबर पख्तूंख्वां की प्रांतीय सरकार ने पिछले वर्ष सितंबर में इसकी घोषणा की थी कि वो इन दोनों अभिनेताओं की संपत्ति को अपने हाथों में लेकर इसको संरक्षित करेगी और इसको एक म्यूजियम में तब्दील करेगी। डायरेक्टर (आर्कियोलॉजी) डॉक्टर अब्दुल समद ने पाकिस्तान के अखबार द डॉन को बताया है कि उनके स्वामित्व को प्रांतीय सरकार को ट्रांसफर करने के बाद निदेशालय ने उनके वर्तमान मालिकों से दोनों संपत्तियों का कब्जा ले लिया है। अब ये दोनों हवेली डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजी की संपत्ति हैं।

समद के मुताबिक जल्द ही इन दोनों संपत्तियों को संरक्षित करने और जरूरी सुधार का काम शुरू किया जाएगा। फिलहाल ये दोनों ही हेवलियां बेहद खराब हालत में हैं। इनको ठीक करके इन्हें म्यूजियम के रूप में तब्दील किया जाएगा। डायरेक्ट्रेट ऑफ आर्कियोलॉजी के डायरेक्टर ने इसकी जानकारी दिलीप कुमार और राजकपूर के परिवार को भी दे दी है।

इजराइल में सत्ता परिवर्तनः विपक्षी दलों के बीच गठबंधन पर सहमति

बेनेट होंगे अगले प्रधानमंत्री

12 साल से सत्ता पर काबिज नेतन्याहू का शासन खत्म

यरुशलम। इजराइल में जारी सियासी घमासान के बीच विपक्षी राजनीतिक दलों में गठबंधन को लेकर सहमति बन गई है। इसके बाद 12 साल से सत्ता पर काबिज और मौजूदा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार का जाना तय हो गया है। मार्च में हुए चुनाव में उनकी पार्टी बहुमत के आंकड़े को नहीं छू पाई थी। सबसे बड़ी पार्टी के नेता होने के नाते नेतन्याहू को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। हालांकि वे बहुमत साबित नहीं कर पाए थे। इसके बाद दूसरे नंबर की पार्टी और उनके सहयोगी दल को सरकार बनाने का न्यौता दिया गया था। इसके लिए उन्हें बुधवार यानी 2 जून की आधी रात तक बहुमत साबित करना था।

नेफ्टाली बेनेट | बेंजामिन नेतन्याहू | येर लेपिड

8 दलों का गठबंधन

इस समय-सीमा के खत्म होने से 38 मिनट पहले ही विपक्ष के नेता येर लेपिड ने सरकार बनाने की घोषणा कर दी। उन्होंने बताया कि विपक्ष के आठ दलों के बीच गठबंधन हो गया है। अब वो सरकार बनाएंगे। उन्होंने राष्ट्रपति रुवेन रिवलिन को गठबंधन की सहमति की जानकारी दे दी है। अब सरकार को सदन में वोटिंग के बाद शपथ दिलाई जा सकेगी।

दोनों दलों के नेता बारी- बारी से प्रधानमंत्री बनेंगे

विपक्षी दलों के बीच गठबंधन को लेकर हुए समझौते के मुताबिक, अब दोनों पार्टी के नेता बारी-बारी से प्रधानमंत्री बनेंगे। सबसे पहले दक्षिणपंथी यामिना पार्टी के नेता नेफ्टाली बेनेट प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे 2023 तक इस पद पर रहेंगे। उसके बाद येश एटिड पार्टी के येर लेपिड प्रधानमंत्री बनेंगे।

इजराइल के नागरिकों के लिए काम करेगी सरकार

लेपिड ने कहा कि यह सरकार इजराइल के सभी नागरिकों के लिए काम करेगी। जिन लोगों ने हमें वोट दिया है उनके लिए भी और जिन्होंने नहीं दिया उनके लिए भी। इजराइल में एकजुटता बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है।

दो साल में अब तक 4 बार चुनाव हो चुके

अगर विपक्ष भी सरकार बनाने में नाकाम होता तो तय था कि इजराइल में 5वीं बार चुनाव कराए जाते। यहां पिछले दो साल से राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई थी। मार्च में हुए आम चुनाव में नेतन्याहू की पार्टी बहुमत जुटाने में कामयाब नहीं हो पाई थी और सहयोगी पार्टियों का समर्थन भी उन्हें नहीं मिला था। उन्हें बहुमत साबित करने के लिए 120 में 61 सीट की जरूरत थी। इसके बाद विपक्ष के नेताओं को सरकार बनाने के लिए 28 दिन का समय दिया गया था। लेकिन गाजा में संघर्ष के चलते प्रोसेस में देरी होती रही।

पहली बार गठबंधन की सरकार

हालांकि, इस नए गठबंधन में लेफ्ट विंग की मेरेटज से लेकर बेनेट की दक्षिणपंथी यामिना पार्टी हिस्सा है। साथ ही इसमें इस्लामिस्ट पार्टी यूनाइटेड अरब भी शामिल है। ऐसा पहली बार है, जब अरब इजराइल पार्टी किसी गठबंधन का हिस्सा है।

मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण की उम्मीद बढ़ीः डोमिनिका की सरकार ने कहा- चौकसी को भारत भेजा जाएगा

एंटीगुआ। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी को डोमिनिका की मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया। चौकसी को व्हील चेयर पर कोर्ट के अंदर ले जाया गया। वह नीले रंग की टी-शर्ट और काला शॉर्ट्स पहने हुआ था। पेशी के दौरान यह उसकी सबसे पहली फोटो है। इससे पहले चौकसी के मामले में डोमिनिका के हाईकोर्ट में 3 घंटे हुई सुनवाई हुई था। हाईकोर्ट की जज बर्नी स्टेफेन्सन ने ही चौकसी को मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था और चौकसी के मामले की सुनवाई टाल दी थी। चौकसी के प्रत्यर्पण पर भी फैसला आ सकता है। हालांकि यह साफ नहीं

है कि मेहुल को पहले एंटीगुआ भेजा जाएगा या सीधे भारत प्रत्यर्पण का आदेश दिया जाएगा। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डोमिनिका सरकार ने चौकसी को भारत भेजने की बात कही है। वहीं एंटीगुआ सरकार पहले ही डोमिनिका से कह चुकी है कि चौकसी को सीधे भारत भेज देना चाहिए।

चौकसी पर गैरकानूनी तरीके से डोमिनिका में एंट्री करने का आरोप है। लेकिन उनसे अपनी हिरासत को हाईकोर्ट में चैलेंज किया है।

चौकसी का दावा है कि उसे एंटीगुआ-बारबुडा से अपहरण कर डोमिनिका लाया गया था। लेकिन हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने चौकसी के दावे का विरोध करते हुए कहा कि वह गैरकानूनी तरीके से डोमिनिका में एंटर हुआ है और इसी के चलते उसे हिरासत में लिया गया था।

पाकिस्तान को आशंका, अमेरिकी फौज की वापसी के बाद अफगानिस्तान में छिड़ सकता है गृह युद्ध!

इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने कहा है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद वहां की सुरक्षा को लेकर वो काफी चिंतित है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अफगानिस्तान जिरगा के स्पीकर मीर रहमान रहमानी से वार्ता के दौरान ये बात कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि युद्धरत अफगान समूहों के बीच सुलह की पहले से ही धुंधली संभावनाएं हर गुजरते दिन के साथ और हल्की होती जा रही हैं। दो दिन बाद एक बार फिर से अफगानिस्तान को लेकर सरकार और तालिबान के बीच वार्ता होने वाली है। हालांकि कुरैशी ने साफ कर दिया है कि इससे पाकिस्तान को काफी कम उम्मीद हैं। पाकिस्तान को लगने लगा है कि अमेरिकी फौज की वापसी के बाद अफगानिस्तान में गृह युद्ध छिड़ सकता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है अफगान समूहों के पास एक सुनहरा मौका है कि वो देश के भविष्य के लिए एक व्यापक मजबूत समझौता कर सकें जो वहां की शांति और समृद्धि के लिए कारगर साबित हो। इसमें कहा गया है कि अफगान समूहों को इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए।

साउथ चाइना सी में नया तनावःमलेशिया के एयरस्पेस में कई घंटे तक चक्कर लगाते रहे चीन की एयरफोर्स के 16 जेट फाइटर, दक्षिण चीन सागर में तनाव बढ़ा

एंटीगुआ। चीन ने एक बार फिर दक्षिण चीन सागर में तनाव बढ़ा दिया है। चीनी एयरफोर्स क 16 फाइटर जेट्स ने मलेशिया के कोस्टल एरिया में कई घंटे तक उड़ान भरी। मलेशिया सरकार ने इस पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए ड्रैगन को दो टूक लफ्जों में संदेश दिया। मलेशिया ने कहा- यह हरकत हमारे देश की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश समझी जाएगी।

मलेशिया के तीखे तेवर देखकर बुधवार को चीन ने भी बात संभालने की कोशिश की। उसकी तरफ से एक बयान में कहा गया- हमारे एयरक्राफ्ट एक रूटीन ट्रेनिंग पर थे। मलेशिया के मामलों में दखल देने का कोई इरादा नहीं था।

क्या हुआ था सोमवार को

चीन की एयरफोर्स के 16 फाइटर जेट्स दक्षिण चीन सागर के कोस्टल एरिया में नजर आए। यह एयरक्राफ्ट्स बोर्नेओ इलाके में देखे गए। यहां चीन का मलेशिया के साथ सीमा विवाद कई साल से है। चीन इस क्षेत्र पर अपना दावा करता है। चीनी विमान देखे जाने के बाद मलेशिया की एयरफोर्स भी एक्टिव हो गई। उसके विमानों ने चीनी एयरक्राफ्ट्स का पीछा किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मलेशियाई एयरफोर्स का आक्रामक रुख देखकर चीन के फाइटर जेट्स वापस चले गए।

मलेशिया ने क्या कहा

मलेशिया के विदेश मंत्रालय ने उस पूरी घटना पर एक बयान जारी किया। विदेश मंत्री ने कहा- इस घटना को हमने गंभीरता से लिया है। यह हमारे इलाके में चीन की सीधी घुसपैठ है। यह हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमने चीन के एम्बेसडर को समन किया है।

कुआलालम्पुर में मौजूद चीनी दूतावास ने इस घटना पर सफाई दी। एक बयान में कहा- हम किसी देश को निशाना नहीं बनाना चाहते। जो कुछ हुआ, उसे मलेशियाई सरकार सिर्फ एक रूटीन एक्सरसाइज की तरह ले। इस तरह की एक्सरसाइज पहले भी की जाती रही हैं। हमने किसी कानून को नहीं तोड़ा। हमारे विमान किसी देश की सीमा में नहीं घुसे।

सच क्या है

मलेशिया दावा करता है कि चीन के विमान उसके एयरस्पेस में आए और बार-बार इससे अंदर-बाहर होते रहे। जबकि, चीन का दावा है कि उसके एयरक्राफ्ट मलेशिया के एयरस्पेस से करीब 110 किलोमीटर दूर थे, और कुछ ही देर में वापस चले गए थे। मलेशिया के फॉरेन मिनिस्टर हिशिमाउद्दीन ने बुधवार को कहा- चीन का दावा गलत है। उसके एयरक्राफ्ट हमारी सीमा में घुसे थे। यह सीधे तौर पर घुसपैठ है।

अमेरिका में कोरोना वैक्सीन लेने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने का गजब तरीका, वैक्सीन लो और बीयर ले जाओ

वाशिंगटन। कोरोना वैक्सीन लेने के लिए अमेरिकियों को प्रोत्साहित करने के लिए मुफ्त में बीयर देने की घोषणा की गयी है। लोगों को कोरोना वैक्सीन लेने के प्रति जागरूक करने के लिए यह प्रोत्साहन व्हाइट हाउस की ओर से दिया गया है। राष्ट्रपति जो बिडेन ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि चार जुलाई से पहले अधिक से अधिक लोगों का वैक्सीनेशना कराने के लक्ष्य से यह प्रोत्साहन दिया जा रहा है। व्हाइट हाउस से बोलते हुए जो बिडेन ने कहा कि अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस से पहले कम से कम देश की 70 फीसदी व्यस्क आबादी का कोरोना वैक्सीनेशन कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान उन्हें कम से कम कोरोना का एक डोज जरूर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बार की गर्मियों से पहले, देश में पहले जैसे हालात लाने के लिए वैक्सीनेशन जरूरी है।

अमेरिका में लोगों को वैक्सीनेशन केंद्र

तक लाने के लिए कई प्रकार की सुविधाएं दी जा रही है। उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए नकद उपहार, खेल के टिकट और पेड वैकेशन सहित कई प्रकार की योजनाएं चलायी जा रही है। जो बिडेन ने कहा कि अधिक से अधिक लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र से सहयोग लिया जाएगा। वैक्सीनेशन के प्रचार के लिए सोशल मीडिया प्रभावितों, कॉलेजों, मशहूर हस्तियों और सामुदायिक संगठनों से मदद ली जाएगी, साथ ही उन्हें बताया जाएगा कि कोरोना वैक्सीनेशन के क्या लाभ हैं।

अमेरिका में अब तक 62।8 फीसदी व्यस्क आबादी को कोरोना वैक्सीन का कम से कम एक डोज मिल चुका है। इनमें 133।6 मिलियन लोगों का पूर्ण टीकाकरण हो चुका है, इन्हें दो डोज मिल चुके हैं। फिलहाल टीकाकरण दर एक बार फिर से कम हो गयी है। गौरतलब है कि इससे पहले भी अमेरिका में वैक्सीन लेने के लिए लॉटरी और स्कॉरलशिप जैसे प्रोत्साहन दिये जा रहे थे।

पाकिस्तान में हिंदू व्यापारी की हत्या के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन

खुजदारी। पाकिस्तान के व्यापारियों ने एक हिंदू व्यापारी की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन किया है। इससे खुजदार और कराची के बीच कई घंटों तक ट्रैफिक जाम लगा रहा। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, खुजदार और कराची के बीच कई घंटों तक यातायात बाधित रहा, जबकि व्यापारियों ने सोमवार को एक हिंदू व्यापारी की हत्या के खिलाफ बलूचिस्तान के खुजदार जिले के वाध शहर में पूरी तरह बंद हड़ताल की। पुलिस के अनुसार, मोटरसाइकिल सवार अज्ञात हथियारबंद लोगों ने वाध बाजार में अशोक कुमार नामक एक व्यापारी पर उस समय गोली चला दी जब वह अपनी दुकान पर बैठा था। इससे कुमार को चोटें आई हैं। उन्हें सरकारी अस्पताल वाध ले जाया गया, जहां कई गोलियां लगने के बाद उनकी मौत हो गई। हिंदू व्यापारी की हत्या की सूचना मिलते ही वाध के व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दीं और खुजदार और कराची के बीच यातायात को निलंबित करते हुए बैरिकेड्स लगाकर राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया. समाचार पत्र ने बताया कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी (बीएनपी-मंगल) के सुरक्षाकर्मियों और कार्यकर्ताओं ने स्थानीय प्रशासन और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की।

कोरोना दुनिया में: बीते दिन 4.89 लाख केस आए, 10,952 की मौत; यूएस इस हफ्ते अन्य देशों को 8 करोड़ वैक्सीन डोज देने के प्लान का ऐलान करेगा

वाशिंगटन। दुनिया में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। बीते दिन दुनिया में 4 लाख 89 हजार 890 कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई। इस दौरान 10,952 लोगों की संक्रमण की वजह से मौत हुई। सबसे ज्यादा मामले भारत में सामने आए। यहां 1.33 करोड़ लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई और 2,897 लोगों की मौत हुई।

उधर, अमेरिका इस हफ्ते अन्य देशों को कोरोना वैक्सीन के 8 करोड़ डोज देने के प्लान का ऐलान कर सकता है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन ने बताया कि राष्ट्रपति जो बाइडेन जल्द ही हम सभी के सामने वैक्सीन बांटने के प्लान का

ऐलान करेंगे।

अमेरिका से बाहर भेजने के लिए तीन कंपनियों की वैक्सीन अधिकृत

अमेरिका में फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को अप्रूवल दिया गया है। एस्ट्राजेनेका इस लिस्ट में शामिल नहीं है। जून के आखिर तक खाद्य एवं औषधि प्रशासन से सुरक्षा जांच में सफल पाए जाने पर एस्ट्राजेनेका का भेजने की शुरुआत की जाएगी। अभी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस देश को किस कंपनी की वैक्सीन की खेप भेजी जाएगी। भारत में नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीनेशन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 यानी NEGVAC ने कहा था कि अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, यूरोप और डब्ल्यूएचओ ने जिन वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी दी है, वह पहले से ही करोड़ों लोगों को लगाई जा चुकी हैं। इनको भारत में अप्रूवल मिलने के बाद टेस्ट और हर बैच की सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी में जांच की आवश्यकता नहीं है।

हालांकि इसके लिए जिस देश से वैक्सीन आ रही है, वहां की एजेंसी से बैच को सर्टिफाइड किया जाना जरूरी है। ऐसे में अगर अमेरिका भारत को वैक्सीन मुहैया कराता है, तो टीके के किल्लत से जूझ रहे देश की काफी मदद हो सकती है।

दुनिया में कोरोना के अब तक 17.24 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 37.06 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 15.50 करोड़ लोगों ने कोरोना को मात दी है। फिलहाल 1.36 करोड़ लोगों का इलाज चल रहा है। इनमें 1.35 करोड़ लोगों में कोरोना के हल्के लक्षण हैं और 90,072 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है।

चीन हो सकता है कोरोना का नया हॉट स्पॉट, इन देशों को भी खतरा, चमगादड़ों पर नई स्टडी में हुए चौंकाने वाले खुलासे

कैलिफोर्निया। कोरोना वायरस महामारी की तबाही पूरी दुनिया झेल रही है। इस बीच कई देशों के वैज्ञानिकों की नई शोध ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। नेचर फूड नाम की पत्रिका में छपी खबर के मुताबिक दुनिया के कई देश एक बार फिर कोरोना के हॉटस्पॉट बन सकते हैं। दरअसल, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कले, पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान के शोधकर्ताओं ने शोध के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि, चीन, जापान, थाईलैंड फिलीपींस जैसे देशों में चमगादड़ों के लिए अनुकूल हॉट स्पॉट बन सकता हैं। चीन में हो सकते हैं सबसे ज्यादा हॉटस्पॉटः नई स्टडी में शोधकर्ताओं ने खुलासा किया है कि पश्चिमी यूरोप से दक्षिण-पूर्व एशिया तक का इलाका कोरोना के लिए हॉटस्पॉट बन सकता है। स्टडी में यह भी बताया गया कि किन जगहों पर चमगादड़ों से नए कोरोना वायरस के इंसानों में फैलने का खतरा ज्यादा हो सकता है।

उपमुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी की गंदी राजनीति पर जमकर बोला हमला

केंद्र सरकार दे जबाव, वैक्सीन के लिए 36000 करोड़ का बजट फिर भी देश में वैक्सीन की क्यों है कमी: सिसोदिया

नई दिल्ली (संवाददाता)। भारत में वैक्सीन की इतनी किल्लत होने के बावजूद केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से दूर भाग रही है और भाजपा के बड़े नेता केंद्र की नाकामियों को छुपाने के लिए बयानबाजी करना नहीं छोड़ रहे है। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्र में बैठी भाजपा सरकार को नसीहत दी है कि भाजपा के नेता अब नींद से जागे और गन्दी राजनीति करने के बजाय देश की जनता के लिए वैक्सीन उपलब्ध करवाए।

उपमुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी की गंदी राजनीति पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता आजकल मीडिया में आते हैं तो केवल केजरीवालजी को गाली गलौज करते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो जनता ये टकटकी लगाए बैठी थी कि संबित पात्रा लोगों के लिए वैक्सीन लाने की बात करेंगे। ये बताएंगे कि बच्चों के लिए

बीजेपी के नेता आजकल मीडिया में आते हैं तो केवल केजरीवालजी को गाली गलौज करते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो जनता ये टकटकी लगाए बैठी थी कि संबित पात्रा लोगों के लिए वैक्सीन लाने की बात करेंगे:-मनीष सिसोदिया, उपमुख्यमंत्री, दिल्ली

मोडर्ना, फाइजर की वैक्सीन कब उपलब्ध होगी। लेकिन संबित पात्रा ने जनता के हितों के मुद्दों पर बात करने के बजाए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 15 मिनट तक केवल अरविंद केजरीवाल को बुरा भला कहा गालियां दी। ये साफ दर्शाता है कि केंद्र में बैठी भाजपा और उसके नेताओं को न तो देश के लोगों की चिंता है न ही उनके पास देश के लिए कोरोना मैनेजमेंट का कोई विज़न है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि आजकल भाजपा का ये ट्रेडमार्क बन चुका है। जनता सवाल पूछती है कि वैक्सीन कब आएगी, वैक्सीन के लिए ग्लोबल ऑडर क्यों नहीं दिए, हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेशों में क्यों और कितने में बेची। लेकिन भाजपा के नेता इन सवालों का बस एक जबाव देते है कि केजरीवाल खराब है। जनता भाजपा के नेताओं से सवाल करती है लेकिन जवाब में केजरीवाल के लिए गालियां मिलती है। भाजपा के नेताओं की दिनचर्या बन चुकी है कि जनता के सवालों का जवाब देने के बजाए वे रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर के केजरीवाल को गालियां देते है और वैक्सीन के मुख्य मुद्दे से जनता को गुमराह करते है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अब संबित पात्रा को और भाजपा के बाकी नेताओं को बताना होगा कि भारत के युवाओं के हिस्से की वैक्सीन विदेशों में क्यों बेची? वैक्सीन के लिए जारी किया गया 36 हज़ार करोड़ का बजट कहां गया? भारत में वैक्सीन बने 8 महीने हो चुके है उसके बावजूद देश में वैक्सीन उपलब्ध क्यों नहीं है? उपमुख्यमंत्री ने केंद्र की भाजपा सरकार से सवाल करते हुए कहा कि वो अबतक कहां सो रहे थे। जब। जनता कोरोना से मर रही थी तब वो इमेज मैनेजमेंट और चुनाव मैनेजमेंट में क्यों व्यस्त थे?

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्राइवेट अस्पतालों के पास वैक्सीन मौजूद है। लेकिन किसी भी राज्य सरकार के पास अपने युवाओं को मुफ्त में लगाने के वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को वैक्सीन मुहैय्या नहीं करवा रही है इससे राज्यों को अपने वैक्सीनेशन केंद्रों को बंद करना पड़ रहा है। उन्होंने सवाल किया कि प्राइवेट अस्पतालों के पास इतनी बड़ी मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध क्यों है? क्या केंद्र सरकार उन्हें पिछले दरवाजे से वैक्सीन उपलब्ध करवा रहा है।

दिल्ली सरकार ने निजी हाथों में सौंप दिया है टीकाकरण का काम: आदेश गुप्ता

नई दिल्ली । भाजपा ने दिल्ली सरकार पर दिल्लीवासियों को निजी अस्पतालों के भरोसे छोड़ देने का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि पिछले दिनों कोरोना संक्रमण के मामले बहुत ज्यादा आ रहे थे उस समय सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बेड नहीं मिल रहे थे। मजबूरन लोग निजी अस्पतालों में जा रहे थे, जहां इलाज के नाम पर मनमाना पैसे लिए गए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने टीकाकरण का काम भी निजी हाथों में सौंप दिया है। सरकारी केंद्रों पर टीके नहीं लग रहे हैं। दूसरी ओर नजी अस्पतालों में ज्यादा पैसे लेकर टीके लगाए जा रहे हैं। उन्होंने टीके के लिए शुल्क निर्धारित करने की मांग की। कहा कि कोरोना से लड़ने में नाकाम मुख्यमंत्री को अब अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से राजधानी के सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर 45 वर्ष कम उम्र के लोगों को टीका लगाने का काम बंद है। निजी क्षेत्रों में 12 सौ रुपये से 18 सौ रुपये लेकर टीके लगाए जा रहे हैं। मरीजों को दवा उपलब्ध कराने में भी नाकाम रही है दिल्ली सरकार। आप नेता आक्सीजन व दवा की कालाबाजारी में व्यस्त थे। उन्होंने कहा कि दिल्ली सहित कई राज्य टीकाकरण का काम राज्यों को सौंपने की मांग कर रहे थे।

केंद्र सरकार ने 45 वर्ष से कम आयु वालों को टीका लगाने का काम राज्यों को दिया तो केजरीवाल सरकार जिम्मेदारी संभालने में विफल रही है। यहां टीकाकरण का काम पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। केजरीवाल सरकार एक बार फिर से केंद्र सरकार को जिम्मेदारी लेने की बात कह रहे हैं। उन्होंने का कि दिल्ली सरकार न खुद टीके की व्यवस्था कर सकी और न केंद्र सरकार से मिले टीके को लोगों तक पहुंचा सकी है। उन्होंने कहा कि नगर निगमों के अस्तालों व डिस्पेंसरी में 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए टीकाकरण का काम बेहतर तरीके से चल रहा था। इससे परेशान होकर दिल्ली सरकार ने निगमों के सभी टीकाकरण केंद्र बंद कर दिए।

दिल्ली महिला कांग्रेस ने इंटरनेट मीडिया के जरिए शराब की होम डिलिवरी पर सरकार को घेरा

नई दिल्ली । दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को इंटरनेट मीडिया के जरिए दिल्ली सरकार की शराब की होम डिलीवरी योजना के खिलाफ अभियान की शुरुआत की। इस दौरान केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। दिल्ली महिला कांग्रेस अध्यक्ष अमृता धवन ने कहा कि दिल्ली वासी पिछले साल से ही केजरीवाल सरकार के प्रति खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर करने लगे थे। दिल्ली ने ऐसा बर्बादी का मंजर कभी नहीं सोचा था। परिवार उजड़ गए, बच्चे अनाथ हो गए। ऐसे लोग अपने बचे हुए परिवार के लिए चिंतित हैं। महिलाएं अपने बच्चों के लिए राशन की उम्मीद करती हैं, मुफ्ज वैक्सीन की मांग कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जब घर-घर राशन योजना चाहिए, तब उनके दरवाजों पर व्यसन के लिए शराब थमाई जाएगी।

संक्षिप्त खबर

वर्तमान परिदृश्य में परीक्षा रद्द का निर्णय सही: डॉ. सिंधुरा

नई दिल्ली। सीबीएसई के 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की परीक्षा रद्द किए जाने से अधिकांश अभिभावकों और छात्र छात्राओं ने राहत की सांस ली है तो कुछ अपवाद स्वरूप इस के विपरित भी हैं। शिक्षा मंत्रालय के इस निर्णय पर कई प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। इसी क्रम में नारायणा ग्रुप का मानना है कि बच्चों की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, यह सामूहिक रूप से सभी के हित में लिया गया निर्णय है। नारायणा ग्रुप के एमडी डॉ सिंधुरा ने कहा हमें विश्वास है कि शिक्षा मंत्रालय छात्रों और स्कूलों की भविष्य की भलाई को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई करेगा, और स्पष्ट रूपरेखा तैयार करेगा। परीक्षा स्थगन के बाद छात्र अब प्रतियोगी परीक्षाओं के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जोकि स्नातक प्रवेश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा

ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर कर रहे थे ठगी, बिहार से पकड़े चार जालसाज

नई दिल्ली। कोरोना काल में ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराने के नाम पर ठगी करने वाले एक गैंग को ग्रेटर कैलाश थाना पुलिस ने पकड़ा है। यह गैंग बिहार में बैठकर दिल्ली के लोगों से ठगी कर रहे था। आरोपी दक्षिणी दिल्ली में ही अलग अलग इलाके में चार लोगों को ठग चुके थे। आरोपियों बालेंद्र चौधरी, गोपाल, कामेश्वर व नाबालिग के पास से तेरह फर्जी सिमकार्ड, तीन एटीएम कार्ड, चार फर्जी आधार कार्ड, दो फर्जी पेन कार्ड, पांच बैंक पासबुक पुलिस ने जब्त की है। पुलिस उपायुक्त अतुल कुमार ठाकुर ने बताया ग्रेटर कैलाश निवासी हरलीन कौर ने पुलिस को शिकायत दी थी। अपनी शिकायत में उन्होंने बताया कि उनके दादा कोरोना पॉजिटिव हो गए थे जिन्हें इलाज के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर की जरुरत पड़ी। पीड़िता को सोशल मीडिया पर मोबाइल नंबर मिला था जिससे संपर्क करने पर वह ठगी का शिकार हुई। इस बाबत पुलिस ने ग्रेटर कैलाश थाने में मुकदमा दर्ज किया। जांच के दौरान टैक्नीकल सर्विलांस का सहारा लिया गया।

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री बोले, म्यूकरमाइकोसिस बीमारी महामारी घोषित मगर दवा नहीं है उपलब्ध, रोजाना बढ़ रहे मरीज

नई दिल्ली। राजधानी में म्यूकरमाइकोसिस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए फंगस के संक्रमण का खतरा टला नहीं है। समस्या यह है कि फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं की कमी दूर नहीं हो पा रही है। इस वजह से बीमारी जानलेवा भी साबित हो रही है। दिल्ली में म्यूकरमाइकोसिस के अब तक कुल 1044 मामले सामने आ चुके हैं। जिसमें से अब तक 89 मरीजों की मौत हो चुकी है। बृहस्पतिवार को यह जानकारी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दी।

उन्होंने कहा कि इस म्यूकरमाइकोसिस से पीड़ित 92 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। 863 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। लेकिन मरीजों के इलाज के लिए दवा ना के बराबर है। उल्लेखनीय है कि म्यूकरमाइकोसिस बीमारी दिल्ली में महामारी घोषित कर दी गई है।

इसके तहत अस्पतालों को हर मरीज की स्वास्थ्य विभाग को जानकारी देना

अनिवार्य है। ताकि मरीजों को दवाएं उपलब्ध कराई जा सके लेकिन दवा की कमी से समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है। म्यूकरमाइकोसिस का संक्रमण नाक से शुरू होता है, जो आंख, चेहरे की हड्डियों व मस्तिष्क में पहुंच जाता है। डाक्टर कहते रहे हैं कि यदि शुरुआत में जांच कर एंटीफंगल दवाएं दी जाए जो ज्यादातर मरीज बचाए जा सकते हैं। संक्रमण अधिक फैल जाने पर इस बीमारी में मृत्यु दर अधिक है।

स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में तीन दिन से संक्रमण दर एक फीसद से कम हैं। इसलिए मामले काफी कम हो गए हैं। दूसरी लहर में एक समय कोरोना के मामले 28 हजार से अधिक पहुंच गए थे। जबकि बुधवार को 576 मामले आए थे। फिर भी अभी सतर्कता जरूरी है। क्योंकि दूसरी लहर शुरू होने से पहले कोरोना के 150-200 मामले आ रहे थे। इस लिहाज से अभी मामले अधिक आ रहे हैं। इसलिए घर से बाहर निकलने पर सभी लोग मास्क जरूर लगाएं व शारीरिक दूरी के नियम का पालन करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि दूसरी लहर में ऐसा हो सकता है कि दिल्ली के करीब 80 फीसद लोग संक्रमित होकर ठीक हो चुके हों लेकिन सीरो सर्वे होगा तभी संक्रमण के फैलाव का सही पता चल सकेगा। बहरहाल, नवंबर-दिसंबर के संक्रमण के बाद पांचवें सीरो सर्वे में दिल्ली में 56 फीसद लोगों में एंटीबाडी पाई गई थी। अप्रैल में भी सीरो सर्वे शुरू हुआ था लेकिन संक्रमण अधिक होने के कारण उसे बंद कर दिया गया था।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से टीका नहीं मिलने के कारण कोवैक्सीजन की दूसरी डोज मिलने में भी दिक्कत हो रही है। 10 जून तक टीका आने की उम्मीद है। तब कोवैक्सीन की दूसरी डोज लग पाएगी। केंद्र सरकार ने यह व्यवस्था की है कि कंपनियां 50 फीसद टीका केंद्र को, 25 फीसद टीका राज्य सरकारों को व 25 फीसद टीका निजी अस्पतालों को उपलब्ध कराएंगी। निजी अस्पतालों को टीका उपलब्ध कराने के प्रविधान पर उन्होंने केंद्र सरकार से विचार करने की मांग की और कहा कि टीका राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। दिल्ली सरकार कंपनियों से टीका खरीदकर लोगों को निशुल्क उपलब्ध कराने को तैयार हैं। विभिन्न निजी अस्पतालों में टीके की अलग-अलग शुल्क के मामले पर उन्होंने दिल्ली सरकार का नियंत्रण होने से इंकार किया। उन्होंने कहा कि इस पर भी केंद्र सरकार का नियंत्रण है।

दिल्ली महिला कांग्रेस ने इंटरनेट मीडिया के जरिए शराब की होम डिलिवरी पर सरकार को घेरा

नई दिल्ली । दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को इंटरनेट मीडिया के जरिए दिल्ली सरकार की शराब की होम डिलीवरी योजना के खिलाफ अभियान की शुरुआत की। इस दौरान केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। दिल्ली महिला कांग्रेस अध्यक्ष अमृता धवन ने कहा कि दिल्ली वासी पिछले साल से ही केजरीवाल सरकार के प्रति खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर करने लगे थे। दिल्ली ने ऐसा बर्बादी का मंजर कभी नहीं सोचा था। परिवार उजड़ गए, बच्चे अनाथ हो गए। ऐसे लोग अपने बचे हुए परिवार के लिए चिंतित हैं। महिलाएं अपने बच्चों के लिए राशन की उम्मीद करती हैं, मुफ्ज वैक्सीन की मांग कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जब घर-घर राशन योजना चाहिए, तब उनके दरवाजों पर व्यसन के लिए शराब थमाई जाएगी, जिसे पीकर घरेलू हिंसा और प्रताड़ना के केसों में बेतहाशा वृद्धि होने की पूरी संभावना है। उन्होंने कहा कि बाजार में अलग-अलग दरों पर उपलब्ध टीके की कमी से निपटने के बजाय, राशन की होम डिलीवरी सुगम बनाने के बजाय, ब्लैक फंगस के टीके को मुफ्त में उपलब्ध करने की बजाय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल घर-घर शराब वितरण के बारे में अधिक चिंतित है। उन्होंने कहा कि इन हालातों में शराब डिलीवरी की समय सीमा तय न होने और आसानी से उपलब्ध होने के कारण शराब की खपत अधिक होने वाली है, जिससे केवल सरकारी राजस्व को लाभ होगा। जबकि घरेलू महिलाओं और बच्चों के लिए परिवार में रहना मुश्किल हो जाएगा।

दिल्ली में निगम चुनाव से पहले कांग्रेस नेता इमराम मसूद को मिली नई जिम्मेदारी

नई दिल्ली । अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआइसीसी) ने वरिष्ठ पार्टी नेता इमरान मसूद को दिल्ली कांग्रेस का सह-प्रभारी नियुक्त किया है। दिल्ली में यह पद काफी समय से खाली पड़ा था। पहले यह जिम्मेदारी पंजाब के नेता कुलजीत सिंह नागरा संभाल रहे थे। इमरान मसूद को दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी राज्यसभा सदस्य शक्ति सिंह गोहिल के साथ जोड़ा गया है। बताया जा रहा है कि इनकी नियुक्ति अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और दिल्ली नगर निगम चुनाव में मुस्लिम तबके के मत हासिल करने की मंशा से की गई है।

गौरतलब है कि अभी हाल ही में इमरान मसूद के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की खबर इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुई थी। बाद में इमरान मसूद ने खुद बयान जारी कर इस खबर का खंडन किया था। उन्होंने कहा था कि वह कांग्रेस व प्रियंका वाड्रा के साथ हैं। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी पत्र के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की सहमति से यह नियुक्ति की गई है। बता दें कि दिल्ली में अगले नगर निगम चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियां अभी से ही तैयारी में जुट गई हैं। कांग्रसे भी निगम चुनाव से पहले खुद को मजबूत कर लेना चाहती है।

केंद्र सरकार, युवाओं के फ्री वैक्सीनेशन के लिए डोज नहीं दे रही: आतिशी

(संवाददाता)

नई दिल्ली । आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार की निजी अस्पातलों के साथ कैसी सांठगांठ है कि महंगे दामों पर वैक्सीन लगाने के लिए डोज दिलवा रहे हैं लेकिन दिल्ली सरकार को युवाओं के फ्री वैक्सीनेशन के लिए डोज नहीं मिल रही हैं। दिल्ली में 45 वर्ष से अधिक उम्र की श्रेणी में 50 फीसदी से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, युवाओं का सिर्फ 10 से 12 फीसदी वैक्सीनेशन ही हुआ है। केंद्र सरकार ने 10 दिनों से ज्यादा दिनों से दिल्ली के युवाओं के लिए वैक्सीन

दिल्ली में 2 जून को 37,793 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है, जिसमें से 29,735 लोगों को पहली और 8058 लोगों को दूसरी डोज लगी

नहीं भेजी है, जबकि बड़ी संख्या में युवा वैक्सीन लगवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यदि वैक्सीनेशन की दर को बढ़ाना है तो युवाओं के लिए वैक्सीन उपलब्ध करानी होगी। युवा वैक्सीन को लेकर जागरुक हैं और वैक्सीनेशन को लेकर किसी प्रकार की हिचक नहीं हैं। दिल्ली में 2 जून को 37,793 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है, जिसमें से 29,735 लोगों को पहली और 8058 लोगों को दूसरी डोज लगी है।

आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और विधायक आतिशी ने गुरुवार को वैक्सीनेशन बुलेटिन जारी किया। विधायक आतिशी ने कहा कि दिल्ली में कल 2 जून को 37,793 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है, जिसमें से 29,735 लोगों को पहली डोज और 8058 लोगों को दूसरी डोज लगी है।

घरेलू कलह में युवक ने चाकू से पत्नी का गला रेता, हालत गंभीर

नई दिल्ली । न्यू अशोक नगर इलाके में घरेलू कलह में एक शख्स ने चाकू से पत्नी का गला रेत दिया। आरोपित यहीं नहीं रूका, उसने चाकू से पत्नी पर कई वार किए। शोर सुनकर मकान मालिक कमरे में पहुंचे और किसी तरह युवक से चाकू छिना। इस बीच आरोपित के हाथ की एक उंगली भी कट गई। गंभीर हालत में खुशबू को इलाज के लिए लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है।

पुलिस मामले की जांच कर रही

पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपित पति शैलेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार खुशबू अपने परिवार के साथ पुरानी कोंडली में किराये के मकान में रहती है। उनका सात साल का एक बेटा व पांच साल की बेटी है। आरोपित शैलेंद्र नोएडा में एक निजी कंनी में नौकरी करता है।

चाकू से किए हैं कई वार- वहीं खुशबू ने भी करीब 15 दिन पहले एक निजी कंपनी में नौकरी शुरू की है। बुधवार रात को अचानक से पति-पत्नी के कमरे से चिल्लाने की आवाज आने लगी। मकान मालिक ने ऊपर जाकर उनके कमरे में देखा तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। शैलेंद्र ने चाकू से अपनी पत्नी का गला रेता हुआ था और चाकू से कई वार किए हुए थे।

चाकू छिनते वक्त आरोपित की उंगली कट- मकान मालिक ने किसी तरह आरोपित को पकड़ लिया, चाकू छिनते वक्त आरोपित की उंगली कट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को जांच में पता चला बुधवार को पीड़िता से मायके से लौट रही थी। रास्ते में पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। आरोपित ने रास्ते में से चाकू खरीदा और रात के वक्त पत्नी पर हमला कर दिया।

दिल्ली के 150 से ज्यादा प्रतिष्ठित लोगों ने उपराज्यपाल अनिल बैजल को सौंपा ज्ञापन, हिंसा पर जताई चिंता

नई दिल्ली । दिल्ली के प्रतिष्ठित शख्सियतों के एक समूह ने बंगाल में चुनाव परिणाम बाद जारी हिंसा को लेकर उपराज्यपाल अनिल बैजल को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में 10 सूत्रीय प्रमुख मांगें रखते हुए इस मामले में उनसे मदद की गुहार लगाई गई है। इस ज्ञापन में सैकड़ों लोगों के 169 प्रतिष्ठित लोगों के हस्ताक्षर हैं। इनमें पूर्व न्यायाधीश एसएन ढिंगरा, एमसी गर्ग, मेजर जनरल ध्रुव कटोच, एयर वाइस मार्शल एचपी सिंह, आर्य समाज से विनय आर्य, रविदास मंदिर देव नगर के अध्यक्ष गोपाल किशन व डा. राजीव मित्तल समेत कई पूर्व न्यायाधीश, पूर्व सैन्य अधिकारी, लोक सेवक, पेशेवर, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र से जुड़े हैं।

ज्ञापन में कहा गया है कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल में चुनाव परिणाम के बाद वहां बड़े पैमाने पर हिंसा जारी है। राज्य के 16 जिले हिंसा से बुरी तरह प्रभावित हैं। सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस से जुड़े लोगों द्वारा 15 हजार से अधिक हिंसा की घटनाओं को अंजाम दिया गया है।

इसकी वजह से चार से पांच हजार लोग राज्य छोड़कर पड़ोसी राज्यों में शरण लेने को मजबूर हुए हैं। हिंसा का शिकार होने वालों में बड़ी संख्या गरीब और अनुसूचित जाति वर्ग के लोग शामिल हैं। कई जगहों पर घर और दुकानों को लूट लिया गया है। बावजूद इसके कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज देखने को नहीं मिल रही है। यह साफ संकेत है कि राज्य सरकार की शह पर इसे अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे में जल्द से जल्द संवैधानिक संस्थाओं को इस मामले में दखल देना होगा।

हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्ट मई- 2021 से निरंतर ऑनलाइन निशुल्क योग शिविर का आयोजन

युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मशु, युक्तसोप्नबवोधस्य योगो भवति दुखहा:

हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्ट मई- 2021 से निरंतर बिना एक दिन भी छुट्टी किये संसार के सभी साधक व साधिकाओं को अनलाइन निशुल्क योग व प्राणायाम योग यात्रा नामक कार्यक्रम के माध्यम से सिखा रहा है।

इस कोरोना महामारी के दौरान लोग अपने घरों में क़ैद से हो रहे थे। ऐसे में हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्ट ने यह जो अनलाइन निशुल्क योग शिविर संचालन किया और एक लिंक के माध्यम से लोगों को जोड़ना शुरू किया और इसमें लोग जुड़ते गये। आज हज़ारों लोग इस अनलाइन योग से लाभ ले रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहते हैं कि- इस लकडाउन के समय में हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्ट ने जो अनलाइन निशुल्क योग शिविर का आयोजन कर लोगों का न सिर्फ़ फ़ायदा कराया है बल्कि संसार के सभी लोगों से मिलने, जान-पहचान करने व नयें दोस्त बनाने का मौक़ा भी प्रदान किया है। साथ साथ योग से होने वाले बहुत से फ़ायदे भी बतायें हैं और सभी इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं।

हाम्रो स्वाभिमान के ट्रस्टी एवम योगगुरु श्री शिवलाल ज्ञवाली जी द्वारा प्रतेक दिन योग सिखाया जाता है ! योगगुरु द्वारा अलग अलग बीमारी को ध्यान में रखते हुए योग व प्राणायाम सिखाया जा रहा है और साथ ही आहार और घरेलू उपचार भी बताते हैं।

योग साधकों द्वारा पूछे गए हरेक सवालों का उत्तर भी पूरी प्रामाणिकता के साथ देते हैं।

हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्ट के माध्यम से ट्रस्ट के ही ट्रस्टी और उप महासचिव योगगुरु श्री शिवलाल ज्ञवाली जी ने अपना बहुमूल्य समय देकर योग व प्राणायाम सिखाया है, और साथ में यह भी बताया है कि योग क्यों करना चाहिए- योग करते हैं-

शरीर शुद्ध बनाने के लिए, रोगों से बचाव व उसका उपचार के लिए, मानसिक तनाव को कम करने के लिए, शिथिलता के लिए, रोगप्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए, शरीर के आसन ठीक करने के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए, मोटापा कम करने के लिए, नैतिक व आचारिक मूल्य बढ़ाने के लिए, रक्त प्रवाह सामान्य करने के लिए,हड्डियों व जोड़ों को मज़बूत बनाने के लिए, श्वसन तंत्र को मज़बूत बनाने के लिए, पाचन प्रणाली ठीक करने के लिए, विसर्जन संस्था की कुशलता में वृद्धि लाने के लिए, फेफड़ों को शक्तिशाली बनाने व आक्सीजन पूर्ति में सुधार लाने के लिए तथा आधुनिक जीवन को खुशहाल बनाने के लिए।

दिनांक 02.06.2021 को श्री रिज़वान राजा-वरिष्ठ समाजसेवी प्रमुख अतिथि इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे और हाम्रो स्वाभिमान द्वारा किया जाने वाला इस कार्यक्रम का सहारना किया ! उन्होंने बताया कि वोह हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्ट से 2014 से ही जुड़े और हाम्रो स्वाभिमान के प्रतेक कार्यक्रम में अपना सहयोग भी देते है और आज भी हाम्रो स्वाभिमान के साथ जुड़े हुए है ! श्री रिज़वान राजा जी गोरखा शहीद समिति के संरक्षक है और उन्होंने अपना सारा जीवन समाजसेवा में लगा दिया है !

इस कार्यक्रम का संचालन श्रीमती अनिता क्षेत्री के द्वारा किया गया ! कार्यक्रम के अन्त में श्रीमती अनिता क्षेत्री जी प्रतेक दिन भाँति योग यात्रियों से उनका अनुभव पूछा और योग यात्रियों ने अपना अनुभव साँझा किया !

ट्रस्ट के अध्यक्ष- श्री नारायण श्रेष्ठ जी, महामंत्री श्री प्रेम क्षेत्री जी , उपाध्यक्ष श्री नारायण शर्मा जी, श्री युवराज भट्टराई अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ लगायत सभी पदाधिकारी तथा महिला विभाग की अध्यक्ष श्रीमती अनिता ज्ञवाली जी, अंतरराष्ट्रीय संयोजिका श्रीमती अनिता क्षेत्री जी, महासचिव श्रीमती मीना पांडेय जी, उपाध्यक्ष श्रीमती कमला पोखेल जी, श्रीमती कविता शर्मा जी, श्रीमती कृष्णा भंडारी, श्रीमती बीना जी लगायत महिला समिति के सभी पदाधिकारियों का भरपूर सहयोग से ही यह कार्य सुचारू रूप से चल पा रहा है।

इस अनलाइन निशुल्क योग शिविर का कुशलता से संचालन कर रही हैं इसी ट्रस्ट की ट्रस्टी व अंतरराष्ट्रीय संयोजिका अनिता क्षेत्री जी।

इस संगठन का लक्ष
हाम्रो स्वाभिमान
कोरोना मुक्त अभियान

अभिभावकों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर वार्षिक व विकास शुल्क लेंगे स्कूल

नई दिल्ली । कोरोना महामारी के दौरान छात्रों से वार्षिक और विकास शुल्क लेने पर लगी रोक हटाने के उच्च न्यायालय के आदेश का निजी स्कूल संचालकों ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि वह अभिभावकों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए शुल्क लेंगे। उन्हें बहुत ज्यादा बोझ महसूस नहीं होगा। स्कूल संचालकों ने कहा कि कोरोना के चलते शुल्क वसूली पर लगी रोक के कारण कई निजी स्कूलों की आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। शिक्षकों को वेतन देने से लेकर हाउस टैक्स, बिजली पानी का भुगतान करने में काफी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। ऐसे में कोर्ट का यह फैसला स्कूलों को राहत देने वाला है। कोर्ट ने छात्रों से 10 जून 2020 से छह किस्तों में शुल्कों का भुगतान करने के लिए कहा है।

छह साल से नहीं बढ़ी स्कूल फीस- कोर्ट का फैसला सही है क्योंकि छह साल से दिल्ली में स्कूलों ने फीस भी नहीं बढ़ाई है। स्कूल बिजली व पानी का बिल और हाउस टैक्स भी लगातार दे रहे हैं। स्कूल नहीं चल रहे, लेकिन बिल्डिंग व कंप्यूटर आदि चीजों को रखरखाव में तो खर्चा होता ही है। स्कूल के कर्मचारियों का वेतन तो वार्षिक शुल्क पर ही निर्भर है। हम समझते हैं कि अभिभावकों के लिए भी है कठिन समय है लेकिन सभी को साथ मिलकर चलना होगा।

संपादकीय

खुलेंगी खिड़कियां एक दिन

सन 1947 में भारत का विभाजन एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें सहमतियों से अधिक असहमतियों की गुंजाइश हमेशा बची रहती है। बहुत सारे मिथक हैं, जो हमने अपने नायकों, घटनाओं व नतीजों के इर्द-गिर्द बुन रखे हैं, और जैसे ही कोई बौद्धिक इन्हें 'डीकंस्ट्रक्ट' करने का प्रयास करता है, उसे बहुत से पूर्वाग्रहों और सरलीकृत स्थापनाओं से जूझना पड़ता है। भारत और पाकिस्तान, दोनों जगहों पर विभाजन को लेकर एक ऐसा विमर्श मौजूद है, जिसके केंद्र में हिंदुओं और मुसलमानों के 1,300 वर्षों से अधिक के संग-साथ की तल्खियां और मिठास दिख ही जाती है। दोनों देशों में पढ़ाए जाने वाले इतिहास की पाठ्य पुस्तकें खुद ही एक गंभीर समाजशास्त्रीय अध्ययन का विषय हो सकती हैं। किसी एक ही शख्सियत या घटना के बारे में दोनों के विवरणों और स्थापनाओं में इतना अंतर दिखता है कि विश्वास नहीं होता, वे एक ही विषय-वस्तु के इर्द-गिर्द अपना ताना-बाना बुन रहे हैं।

इस तरह की विभक्त बौद्धिक दुनिया में पिछले कुछ वर्षों से प्रोफेसर इश्तियाक अहमद एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप कर रहे हैं। लाहौर में जन्मे, पले-बढ़े और शुरुआती शिक्षा प्राप्त पाकिस्तानी मूल के स्वीडिश नागरिक प्रो अहमद वहीं इतिहास और राजनीति शास्त्र पढ़ाते रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में अंग्रेजी में छपी उनकी दो पुस्तकें पंजाब ~ लहूलुहान, विभाजित और नस्ली सफाई तथा जिन्ना ~ सफलताएं, असफलताएं और इतिहास में उनकी भूमिका भारतीय उपमहाद्वीप की सांप्रदायिक राजनीति को समझने का प्रयास करने वाले किसी भी गंभीर अध्येता के लिए अनिवार्य पाठ्य सामग्री बन गई हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन की गुत्थियों को सुलझाने के लिए 1,300 वर्षों के उस पड़ोस को समझना जरूरी है, जो आठवीं शताब्दी में मोहम्मद बिन कासिम के सिंध विजय के साथ शुरू हुआ था। यह पड़ोस दुनिया की दो बड़ी जीवन पद्धतियों का था। एक तरफ, धर्म की शास्त्रीय समझ से परे हिंदू थे और दूसरी तरफ, आसमानी किताब और आखिरी पैगंबर में यकीन रखने वाले मुसलमान और स्वाभाविक ही इनकी विश्व दृष्टि एक-दूसरे से बहुत भिन्न थी। इस संग-साथ ने रचनात्मकता की दुनिया में बहुत कुछ श्रेष्ठ निर्मित किया। साहित्य, संगीत, स्थापत्य, मूर्तिकला, पाक शास्त्र- हर क्षेत्र में इन्होंने मिल-जुलकर अद्भुत योगदान किया। पर यह कहना सरलीकरण होगा कि दुनिया के दो बड़े धर्मों के अनुयायी सिर्फ रचनात्मक लेन-देन कर रहे थे, सही बात यह है कि वे हजार साल से अधिक एक-दूसरे से लड़ते भी रहे थे। इसी तरह के दूसरे सरलीकरण हैं कि लड़ते तो सिर्फ शासक थे, प्रजा प्रेम से रहती थी या हिंदुओं और मुसलमानों को ब्रिटिश शासकों ने लड़ाया, अन्यथा वे तो शांति से रहना चाहते थे। विभाजन को लेकर भी सरलीकृत धारणाएं हैं, जो भारतीय समाज के सांप्रदायिक रिश्तों को समझने की कोशिश करने वाले मुझ जैसे जिज्ञासु को उलझन में डालती रही हैं। इन्हीं कुछ गुत्थियों को सुलझाने का मुझे मौका मिला, जब पिछले दिनों मैंने प्रो इश्तियाक से एक लंबी बातचीत की। सभी जानते हैं, विभाजन ने एक करोड़ से भी अधिक परिवारों को प्रभावित किया था। बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए या मारे गए। विभाजन में तो मुख्य रूप से पंजाब और बंगाल का बंटवारा हुआ था और प्रो इश्तियाक ने पंजाब पर बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। दोनों तरफ के दर्जनों विस्थापितों से इंटरव्यू लेकर उन्होंने मौखिक इतिहास का दुर्लभ व मूल्यवान दस्तावेजीकरण किया है। भारत में बहुत से लोग, जिनमें फैजान मुस्तफा जैसे आधुनिक और असदुद्दीन ओवैसी जैसे कट्टरपंथी शरीक हैं, तर्क देते हैं कि हिन्दुस्तान के मुसलमान अपनी मर्जी से भारतीय हैं। उन्हें 1947 में मौका मिला था कि वे पाकिस्तान जा सकते थे, पर वे अपनी धरती से प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने भारत नहीं छोड़ा। मुझे इस स्थापना से हमेशा दिक्कत होती है कि क्या पाकिस्तान से आने वाले सिख और हिंदू अपनी धरती से प्यार नहीं करते थे। इस स्थापना से आजाद भारत के गांधी-नेहरू जैसे रोशन ख्याल नेतृत्व के प्रयासों का अपमान होता है, जिनके कारण भारत से उस तरह से मुसलमानों की नस्ली सफाई नहीं हो सकी, जैसे पाकिस्तान से सिखों और हिंदुओं की हुई। उन्होंने अपनी पंजाब वाली किताब का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने विस्तार से मार्च 1947 में रावलपिंडी में सिखों पर मुसलमानों के हमलों का जिक्र किया है। इसमें कई हजार सिख मारे गए थे और हजारों परिवार उजड़कर पटियाला पहुंचे थे। यह आजादी के पहले की शुरुआती नस्ली सफाई थी। बाद में शेष पाकिस्तान में इसी पैटर्न की दूसरी कार्रवाइयां हुईं और नतीजतन आज एक प्रतिशत से कम हिंदू, सिख वहां हैं। इसके बरक्स भारत में क्या हुआ? मार्च में जब सिख भागकर आए, तब जरूर नस्ली सफाई का एक दौर आया, जिसमें सिखों ने मुसलमानों को मलेरकोटला छोड़कर पूरे पंजाब से खदेड़ दिया। याद रहे कि तब का पंजाब दिल्ली की सीमा तक था। पर जब तक नस्ली सफाई का सिलसिला दिल्ली तक पहुंचा, देश आजाद हो चुका था और बलवाइयों के लिए गांधी और नेहरू एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आए। गांधी तो सांप्रदायिक हिंसा के विरुद्ध अनशन पर बैठ गए और इसे तोड़ने के लिए उनकी एक शर्त यह भी थी कि हिंदू और सिख बलात कब्जा की गई अन्य संपत्तियों के साथ मस्जिदों को भी मुसलमानों को वापस सौंप दें। इस तरह का कोई प्रयास जिन्ना या लियाकत अली खां द्वारा पाकिस्तान में नहीं किया गया। भारत में आजादी के बाद के रोशन ख्याल नेतृत्व को इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए कि उसने नस्ली सफाई नहीं होने दी और अधिसंख्य मुसलमान देश में रुक सके। इसी तरह, कैबिनेट मिशन को लेकर एक मिथ यह है कि यदि कांग्रेस ने उसे मान लिया होता, तो विभाजन टल सकता था। पर प्रो इश्तियाक से बात करके यह मिथ टूटता है। वह मानते हैं कि कैबिनेट मिशन की असफलता का मुख्य कारण जिन्ना की हठधर्मिता ही अधिक थी। प्रो इश्तियाक भारत-पाकिस्तान के उन बुद्धिजीवियों में हैं, जो विश्वास करते हैं कि यद्यपि सन 1947 के पहले की स्थितियां लौटाई नहीं जा सकतीं, पर यूरोपीय यूनियन जैसी व्यवस्था तो हो ही सकती है, जिसमें वीजा खत्म हो सकता है, व्यापार निर्बाध हो जाए या साहित्य और संस्कृति की खिड़कियां खोलकर ताजी हवा के झोंके आने दिए जाएं। हम दोनों ने इसी उम्मीद के साथ बातचीत खत्म की कि हमारे जीवन में ही यह दिन आएगा जरूर।

प्रवीण कुमार सिंह

अफसरशाही के शिकंजे से मुक्त हो स्वास्थ्य तंत्र

वस्तुत~ यह एक तरह का मेडिकल साम्राज्यवाद है। दुर्भाग्य से केंद्र सरकार ने 22 एम्स भी इसी तर्ज पर आरंभ कर दिए हैं। राज्य सरकारें भी हर बड़े शहर में ऐसे ही अस्पताल खोलकर हजारों करोड़ रुपये व्यय कर रही हैं। बेहतर होगा कि निर्माणाधीन सभी एम्स नेशनल रिसर्च संेटर में तब्दील कर दिए जाएं जहां एक या दो बीमारियों पर सांगोपांग शोध का ही काम हो और वे सभी दिल्ली एम्स के अधीन काम करें। इनमें से कुछ को एलाइड सिंवसेज यानी पैरामेडिकल सेवाओं के नवोन्मेषण से भी जोड़ा जा सकता है, क्योंकि देश में इस विधा के लिए अभी तक कोई रिसर्च संेटर नहीं है।

कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से समूचा देश भयभीत है। इसकी तीसरी लहर आने की आशंकाओं के बीच भय की स्थिति कायम है। यदि तीसरी लहर आती है तो उससे बेहतर तरीके से निपटा जा सके, कोई भी इस बारे में आश्वस्त नहीं कर पा रहा। ऐसे में यह स्पष्ट है कि अगले कुछ वर्ष भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। आज की परिस्थितियां किस कारण निर्मित हुई हैं इस बहस में उलझने की जगह उन संभावनाओं को अमल में लाने के लिए समवेत होने का समय है जिनके बलबूते भविष्य का भारत कोरोना जैसी अन्य आपदाओं से सुरक्षित हो सकता है। करीब सवा लाख स्नातक चिकित्सक परीक्षा के लिए प्रतीक्षारत हैं, जिन्हें सीधे कोविड प्रबंधन केंद्रों पर प्रैक्टिशनर के रूप में संलग्न कर दिया जाना चाहिए। हालांकि प्रधानमंत्री द्वारा इस संदर्भ में किए गए आवाहन के बाद इस दिशा में काम शुरू भी हो चुका है, लेकिन आवश्यकता इसमें तेजी लाने की है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2020 के अनुसार हमारे हेल्थ सिस्टम में 78 फीसद चिकित्सकीय एवं पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है। देश भर में करीब ढाई लाख नर्सें पढ़ाई कर अंतिम नतीजों के इंतजार में हैं। इन्हें भी सरकारी सिस्टम का हिस्सा सीधे बनाए जाने में कोई बुराई नहीं है। जाहिर है जब हालात आपातकालीन हों तो निर्णयन भी उसी अनुपात में त्वरित होने चाहिए। सवाल यह भी कि क्या भारत का स्वास्थ्य तंत्र अफसरशाही की जड़ता के आगे दम तोड़ रहा है? आइएमए के अध्यक्ष का कहना है कि कोविड से निबटने में ब्यूरोक्रेसी नहीं चिकित्सक ही सक्षम है और अब अखिल भारतीय चिकित्सा संवर्ग के गठन का समय आ गया है। वस्तुत~ हमारा स्वास्थ्य ढांचा इतनी उलटबांसियों से भरा हुआ है कि कोई विशेषज्ञ डॉक्टर सरकारी तंत्र का हिस्सा नहीं बनना चाहता।

प्रधानमंत्री केयर फंड से जारी हुई

वेंटीलेटर मद की राशि लगभग एक साल में अगर खर्च नहीं हो पाई है तो इसके लिए हम डॉक्टरों को नहीं उस प्रशासनिक व्यवस्था को दोषी मानेंगे जिसके पास हर मामले में अपरिमित अधिकार है। आक्सीजन प्लांट लगाने का काम एक प्राइवेट अस्पताल सात दिन में पूरा कर लेता है, लेकिन सरकारी अस्पताल में इसके लिए प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति से लेकर निविदा और वर्क आर्डर की प्रक्रिया में महीनों लग रहे हैं। सिविल कार्य के कांट्रेक्टर अलग हैं, उपकरणों की खरीदी की प्रक्रिया अलग है, फिर परिचालन और रखरखाव की एजेंसियां अलग। मतलब महामारी जैसे हालातों में भी हमारा सिस्टम अपनी जड़ता, दुरूहता और सुस्ती त्यागने को तैयार नहीं है। ऐसे में भविष्य का स्वास्थ्य क्षेत्र नागरिकों के लिए आरोग्य सुनिश्चित कर पाएगा? कहते हैं हर संकट एक सबक देकर जाता है, इसलिए इस कोविड संकट के साथ हमें स्वास्थ्य के बुनियादी अधिकार और 'वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम' पर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। यह मानकर चला ही जाना चाहिए कि अगले दो वर्ष ऐसे ही चुनौतियों से भरे होंगे, इसलिए सबसे पहले हमें निर्णयन की प्रक्रिया को युद्धकालीन मोड पर लाना होगा।

बेहतर होगा देश का स्वास्थ्य तंत्र अफसरों के नियंत्रण से बाहर किया जाए और केंद्रीय सूची में इसे शामिल कर केंद्र सरकार हर नागरिक का आरोग्य सुनिश्चित करने का दायित्व अपने ऊपर ले। अभी राज्य और केंद्र के बीच भारतीय नागरिकों का स्वास्थ्य अधर में झूलता रहता है। हर नागरिक को अमेरिका की तर्ज पर स्वास्थ्य बीमा का कवर आसानी से उपलब्ध कराने का यह बेहतर वक्त है। आयुष्मान के दायरे में पहले ही 65 करोड़ आबादी आ चुकी है, शेष सक्षम या संगठित क्षेत्र को नियोक्ताओं के जरिये बीमा से जोड़ा जा सकता है। यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि एक भी बीमारी बीमा कवरेज से बाहर न हो। अफसरशाही के जड़तामूलक दखल को समाप्त किए बिना भारत का स्वास्थ्य ढांचा भविष्य की चुनौतियों से निपटने में सक्षम नहीं हो सकता है। यह एक अनुभवजन्य तथ्य भी है कि डॉक्टरों एवं नौकरशाही में एक स्थाई टकराव भाव है। एक कलेक्टर या सचिव जिस तरह राजस्व या अन्य मामलों को निबटाते हैं, कमोबेश वे डॉक्टरों की दक्षता का मूल्यांकन भी इसी भाव से करते हैं। आगामी कार्ययोजना में इस स्थाई टकराव भाव को तभी समाप्त किया जा सकता है जब स्वास्थ्य क्षेत्र का विनियमन पूरी तरह से चिकित्सकों के हवाले किया जाए। क्या यह संभव नहीं कि एम्स दिल्ली के पदेन डायरेक्टर भारत के स्वास्थ्य सचिव हों और संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी भी लेटरल भर्ती के माध्यम से विशेषज्ञ पूल से नियुक्त किए जाएं।

सरकारी अस्पतालों के अलावा सभी ख्यातिनाम निजी अस्पतालों को एक निर्धारित मानक के मुताबिक मेडिकल कॉलेज के रूप में काम करने की नीतिगत अनुमति से चिकित्सा सुविधाओं का असंतुलन दूर होगा। इंग्लैंड में सीएचसी, पीएचसी स्तर के अस्पतालों में चार साल की पदस्थापना के साथ पीजी डिग्री देने का चलन है। इसे भारत में अपनाने का यह सबसे उपयुक्त समय है। इस नवाचार से शहरी अस्पतालों में भीड़ नहीं होगी, क्योंकि चार साल तक पीजी के लिए डॉक्टर गांव/कस्बों में उपलब्ध होंगे जो अध्ययन के साथ प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आवश्यक उपचार भी लोगों को उपलब्ध करा सकते हैं। फिलहाल देश की कस्बाई-ग्रामीण आबादी में केवल 30 फीसद डॉक्टर ही सेवारत हैं। इस स्थिति के लिए मेडिकल शिक्षा का दोषपूर्ण ढांचा जिम्मेदार है, क्योंकि स्नातक डॉक्टर्स को पीजी डिग्री के लिए बड़े शहरों में ही आना पड़ता है। ब्रिटेन की तरह 'मेंबर ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ फिजीशियन एंड सर्जन' अपनाकर बड़े शहरों एवं अस्पताल के इस बोझ को आसानी से खत्म किया जा सकता है। इस मॉडल में पीजी की डिग्री चार साल स्थानीय अस्पतालों में सेवा करने के बाद त्रिस्तरीय परीक्षा पास कर मिलती है। हमारे देश में ठीक उलट सिस्टम है।

बेशक मोदी सरकार ने 135 से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेज खोले हैं, लेकिन ये कॉलेज डॉक्टरों की स्थानीय मांग को पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्नातक के बाद अधिकांश डॉक्टर पीजी करने या फिर अच्छे प्रैक्टिस के लिए बड़े शहरों का रुख करेंगे। फिर कोरोना जैसी आपदाओं में शहरी अस्पताल आक्सीजन या बिस्तरों के लिए जंग का मैदान नहीं बनेंगे। अभी महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे राज्यों का मेडिकल शिक्षा में दबदबा है। यदि सरकार हर जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज बनाकर पीजी व्यवस्था की नीति लागू कर दे तो यह कदम विशेषज्ञ सुविधाओं को समावेशी बनाने का काम करेगा। सुपर स्पेशियलिटी के नाम से देश में एक नई विधा मेडिकल क्षेत्र में फल-फूल रही है। वस्तुत~ यह एक तरह का मेडिकल साम्राज्यवाद है। दुर्भाग्य से केंद्र सरकार ने 22 एम्स भी इसी तर्ज पर आरंभ कर दिए हैं। राज्य सरकारें भी हर बड़े शहर में ऐसे ही अस्पताल खोलकर हजारों करोड़ रुपये व्यय कर रही हैं। बेहतर होगा कि निर्माणाधीन सभी एम्स नेशनल रिसर्च सेंटर में तब्दील कर दिए जाएं जहां एक या दो बीमारियों पर सांगोपांग शोध का ही काम हो और वे सभी दिल्ली एम्स के अधीन काम करें। इनमें से कुछ को एलाइड सिंवसेज यानी पैरामेडिकल सेवाओं के नवोन्मेषण से भी जोड़ा जा सकता है, क्योंकि देश में इस विधा के लिए अभी तक कोई रिसर्च सेंटर नहीं है।

आखिर इजरायल की तरह हमें कोरोना महामारी से कब तक मिलेगी मुक्ति ?

इजरायल आजकल कई कारणों से सुर्खियों में है। महामारी के संदर्भ में इस देश को देखें तो यहां अब सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना अनिवार्य नहीं रहा। इजरायल विश्व का पहला ऐसा देश बन चुका है, जिसने खुद को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया है। वहां बड़े स्तर पर टीका अभियान के बाद एक बार फिर लोगों की जिंदगी पटरी पर लौट रही है। इजरायल द्वारा स्वयं को कोरोना मुक्त देश घोषित करना भारत के लोगों को लालायित कर रहा है। भारतवासी यह सोचने लगे हैं कि क्या हम भी इजरायल की तरह कोरोना से छुटकारा पा सकेंगे?

आज हमारे यहां कोरोना संक्रमण की स्थिति भयावह है। एक ओर लोगों को अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ मन में यह भाव भी उठ रहे हैं कि किसी तरह इस महामारी का कोई स्थायी इलाज हो, ताकि लोग पहले की भांति रोजमर्रा की जिंदगी जी सकें। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए ऐसी उम्मीद करना बहुत कठिन है। आखिर इजरायल की तरह हमें कोरोना से कब तक मुक्ति मिलेगी? वैसे इजरायल जैसा कोरोना मुक्त होने के लिए हमें उसके विषय में जानना अत्यंत आवश्यक है कि कैसे इस छोटे से देश ने अपने परिश्रम, अनुशासन, दृढ़ संकल्प के साथ ऐसा करने में कामयाबी हासिल की है। कोरोना के मामले में इस देश ने बहुत ही अनुशासन दिखाया है। एक बार मास्क लगाने की घोषणा हो गई, तो फिर किसी ने प्रश्न नहीं उठाया है। लोगों ने शारीरिक दूरी का पूरा ध्यान रखा, इसके लिए वहां की पुलिस को हमारे देश की तरह कसरत नहीं करनी पड़ी। इसी तरह की मुस्तैदी और लोगों का अनुशासन टीकाकरण अभियान में भी दिखा। इस देश में 16 से 80 वर्ष तक 81 प्रतिशत से अधिक लोगों का टीकाकरण हो चुका है।

संबंधित परिस्थितियों का मूल्यांकन करने के बाद यह स्पष्ट किया गया कि देश कोरोना संकट से बाहर है और उसके बाद ही मास्क पहनने की अनिवार्यता से छूट दी गई। दूसरी ओर हमारे देश में लोग मास्क लगाने के लिए सड़क पर पुलिस कर्मियों से झगड़ने लगते हैं। हाल में ही इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो में दिख रहा था कि किस तरह दिल्ली में कार से जा रहे एक दंपति को जब पुलिसकर्मियों ने मास्क नहीं होने के कारण रोका तो उन्होंने किस तरह से बदतमीजी की थी। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि इजरायल की आबादी की तुलना भारत से नहीं की जा सकती, क्योंकि वहां की कुल आबादी एक करोड़ से भी कम है। ऐसे में अनुशासन का पालन और टीकाकरण का कार्य उतना मुश्किल नहीं है। इन सभी बातों के लिए जनसंख्या एक अहम कारक है, लेकिन मूल बात राष्ट्र के प्रति संकल्प और अनुशासन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

ऐसा भी नहीं है कि भारत में कोरोना महामारी पर विजय पाने की क्षमता नहीं है। यह बात अलग है कि हम वैसा दृढ़ संकल्प और अनुशासन नहीं अपना रहे हैं जैसा इजरायल और वहां के लोगों में है। हमारे देश में बहुत सारे नागरिक ऐसे हैं जो सरकारी निर्देशों को न मानने की जिद को अपना अधिकार मान बैठते हैं। निश्चित रूप से राज्य सरकारों के कोरोना प्रबंधन कार्यक्रम में कमियां दिखती रही हैं, क्योंकि कोरोना के नए वैरियंट को लेकर देश को आगाह भी किया गया था, परंतु उस दिशा में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया।

इस संबंध में हमें इजरायल से सीख लेनी चाहिए कि आपदा के समय में कैसा आचरण करना चाहिए। अगर सभी देशवासी इस समस्या को निपटाने में अपना सहयोग दें, तो निश्चित तौर पर जल्द ही इस महामारी को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके लिए केवल हमें अनुशासित जीवनशैली को व्यवहार में लाना ही होगा। इस बात को हम जितनी जल्दी समझेंगे, उतना अच्छा होगा।

मान-अपमान से बड़ी त्रासदी

पश्चिम बंगाल में हालिया विधानसभा चुनावों के दौरान दोनों प्रबल प्रतिद्वंद्वी पक्षों के बीच दिखी कड़वाहट चुनावों के बाद धीरे-धीरे खत्म होने के बजाय अप्रत्याशित ढंग से खिंचती चली जा रही है। चुनाव नतीजों के ठीक बाद यह हिंसा की घटनाओं के रूप में सामने आई। फिर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के रिश्तों में तनाव भरने लगी। केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच राज्य के मुख्य सचिव के डेप्युटेशन को लेकर बना ताजा टकराव भी इसी कड़वाहट के लगातार विस्तार का नतीजा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस हालिया टकराव के केंद्र में वह बैठक है, जो यास तूफान से राज्य में हुई तबाही के मद्देनजर पीड़ितों को राहत पहुंचाने के उपायों पर विचार करने के लिए बुलाई गई थी। प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई गई उस बैठक में बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी को आमंत्रित करने के पक्ष और विपक्ष में दी जा रही दलीलें अपनी जगह हैं, पर इस तथ्य से कोई कैसे इनकार कर सकता है कि वह नंदीग्राम से बीजेपी के टिकट पर जीत कर आए हैं। बीजेपी उन्हें नेता प्रतिपक्ष का पद दे रही है तो विधानसभा के इस पूरे कार्यकाल के दौरान वह सदन के अंदर और बाहर इस भूमिका में बने रहेंगे।

ममता बनर्जी की लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार उनकी मौजूदगी पर कहां-कहां आपत्ति करेगी। बेहतर होता, तृणमूल कांग्रेस की सरकार किसी खास व्यक्ति की मौजूदगी को अपने मान-अपमान से जोड़ने के बजाय राज्य के तूफान पीड़ितों के हितों को तरजीह देते हुए पूरी गंभीरता से उस बैठक में शामिल होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और केंद्र सरकार के सामने राज्य के तूफान पीड़ितों का पक्ष ढंग से रखने का एक मौका हाथ से चला गया। लेकिन इसके बाद केंद्र सरकार ने इस मामले पर जिस तरह से रिएक्ट किया, उसे भी परिपक्वतापूर्ण नहीं कहा जा सकता। किसी राज्य के मुख्य सचिव को केंद्र में डेप्युटेशन पर बुलाने के इस तरीके के कानूनी पहलू अपनी जगह हैं, प्रशासनिक और राजनीतिक लिहाज से भी यह कोई अच्छा कदम नहीं कहा जाएगा। मुख्य सचिव किसी राज्य के पूरे प्रशासनिक तंत्र का अगुआ होता है। उसके साथ अपमानजनक व्यवहार न केवल आईएएस अधिकारियों के बल्कि पूरे प्रशासन तंत्र के मनोबल पर असर डाल सकता है। फिर कहना होगा कि यह सब ऐसे समय हो रहा है, जब राज्य का प्रशासन कोरोना और तूफान की दोहरी चुनौती से जूझ रहा है। इन्हीं चुनौतियों के मद्देनजर मुख्य सचिव को तीन महीने का सेवा विस्तार इन्हीं सरकारों ने चंद दिनों पहले दिया है। साफ है कि केंद्र और राज्य की निर्वाचित सरकारें इस संकट काल में जिस तरह का रुख दिखा रही हैं, उससे कहीं बेहतर आचरण की उनसे उम्मीद की जाती है। और निश्चित रूप से वे आम देशवासियों की इस उम्मीद पर खरा उतरने की काबिलियत रखती हैं।

अफवाहों से जूझता 5 जी नेटवर्क, जानिए मोबाइल रेडिएशन कितना खतरनाक

वैसे तो हमारे शरीर का एनर्जी कंट्रोल मैकेनिज्म आरएफ एनर्जी के कारण पैदा गर्मी को बाहर निकालता रहता है, पर कुछ शोधों में साबित हुआ कि मोबाइल फोन से निकलने वाली ऊर्जा ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, आर्थराइटिस, अल्झाइमर और हार्ट डिजीज जैसे रोगों का कारक हो सकती है। ठीक उसी तरह जैसे माइक्रोवेव में पकाए जाने वाले भोजन में मौजूद पानी इसके विकिरण के असर से सूख जाता है, उसी तरह मोबाइल रेडिएशन हमारे खून की गुणवत्ता और दिमाग की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। पर दूसरी बड़ी समस्या है इनके ट्रांसमिशन टावर, जो शहरों में तकरीबन हर गली-मोहल्ले में घरों की छतों पर कुकुरमुत्तों की तरह उग आए हैं।

मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों के टावरों से होने वाले रेडिएशन को पहले ही काफी संदेह से देखा जाता रहा है, इसलिए कोरोना काल में इन आशंकाओं ने और जोर पकड़ा। जहां तक मौजूदा स्थितियों में कोरोना वायरस के प्रसार और 5जी नेटवर्क में किसी सीधे संबंध की बात है, तो इसको लेकर दावों का कोई ठोस आधार नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर को 5जी मोबाइल टावरों के परीक्षण का नतीजा बताने वाले दावों का जवाब देते हुए हाल में दूरसंचार विभाग ने कहा है कि ये कोरी अफवाहें हैं। उल्लेखनीय है कि इन संदेशों में कहा जा रहा है कि 5जी टावरों की टेस्टिंग से निकलने वाला रेडिएशन हवा को जहरीला बना रहा है, इसलिए लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मोबाइल और दूरसंचार सेवा कंपनियों के संगठन सेल्यूलर आपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआइ) ने भी साफ कहा है कि ये दावे पूरी तरह गलत हैं। सीओएआइ के मुताबिक दुनिया में पहले ही कई देशों में 5जी नेटवर्क शुरू हो चुका है और वहां ऐसी कोई समस्या सामने नहीं आई है। यहां तक कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने भी सफाई दी है कि 5जी तकनीक का कोविड से कोई लेना देना नहीं है। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि कोरोना वायरस मोबाइल नेटवर्क और रेडियो तरंगों पर सवार होकर एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं पहुंच सकता। हालांकि कोरोना की मार उन देशों पर भी पड़ रही है जहां 5जी मोबाइल नेटवर्क नहीं है। लेकिन क्या मोबाइल रेडिएशन वास्तव में कोई समस्या नहीं है। क्या इससे हम पर (इंसान समेत सभी जीवों पर) कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।

यह बहस पिछले एक दशक में हमारे देश में होती

रही है कि क्या मोबाइल फोन की बदौलत लोगों तक पहुंचने वाली तरंगें स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह भी हो सकती हैं। इस बहस के केंद्र में उन मोबाइल टावरों को रखा गया है जो इंसानी आबादी के नजदीक या उनके बीच स्थापित किए जाते हैं। ज्यादातर मौकों पर ऐसी मांगों को प्रशासन और अदालत ने अस्वीकार ही किया है। हालांकि पहली बार अप्रैल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति की इस बारे में दलील मंजूर की थी और उसने कैंसर की आशंका को देखते हुए मोबाइल टावर को बंद करने का आदेश दिया था। असल में सुप्रीम कोर्ट ने ग्वालियर निवासी हरीश चंद तिवारी की यह बात मानी थी कि मोबाइल फोन टावर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से उन्हें कैंसर हुआ है। अपनी शिकायत में हरीश चंद ने कहा था कि सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने 50 मीटर से भी कम दूरी पर स्थित उनके पड़ोसी के घर की छत पर 2002 में अवैध रूप से मोबाइल टावर लगाया था, जिस कारण लगातार 14 साल तक वह उससे निकलने वाले हानिकारक रेडिएशन के शिकार बन गए। तिवारी ने दावा किया था कि लंबे समय तक रेडिएशन के संपर्क में रहने की वजह से उन्हें हॉजकिंस लिंफोमा (एक तरह का कैंसर) हो गया। इस याचिका की सुनवाई के बाद वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन जस्टिस रंजन गोगोई और नवीन सिन्हा की बेंच ने बीएसएनएल को सात दिनों के भीतर उस टावर को बंद करने का आदेश दे दिया। यही नहीं, कोर्ट ने मोबाइल रेडिएशन का इंसानों और पशुओं पर क्या असर पड़ रहा, इससे संबंधित अन्य सबूत और दस्तावेज जमा करने को कहा। इससे पहले वर्ष 2016 में भी मोबाइल फोन और टावरों से निकलने वाले रेडिएशन से जनता को बचाने की एक अन्य व्यक्ति नरेश चंद गुप्ता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और टावर लगाने वाली कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। नरेश चंद गुप्ता ने भी अपनी याचिका में कहा था कि मोबाइल रेडिएशन लोगों और जानवरों के लिए खतरनाक है। याचिका में कहा गया था कि केंद्र सरकार इसके लिए विदेशों की तरह विज्ञान शोध के आधार पर नियम तय करे और कालोनियों, स्कूलों, अस्पतालों और बाजारों से 500 मीटर दूर ही टावर लगाए जाएं।

जब कभी भी मोबाइल रेडिएशन से जुड़ी याचिकाएं कोर्ट में पहुंची हैं या फिर दूरसंचार कंपनियों व सरकार से इसकी शिकायत की गई है, वे ज्यादातर अनसुनी ही रही हैं। जैसे 10 सितंबर, 2015 को जब ऐसा ही एक मामला दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचा था तो अदालत ने याचिका को ही खारिज करते हुए सलाह दे डाली थी कि अगर किसी व्यक्ति को मोबाइल टावर से होने वाले रेडिएशन का इतना ही भय है तो वह मोबाइल फोन का ही इस्तेमाल क्यों कर रहा है। यही नहीं, मई 2016 में केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में कहा था कि मोबाइल टावर के रेडिएशन से मानव जीवन पर किसी तरह के दुष्प्रभाव की बातें बेबुनियाद हैं और इसका कोई प्रमाण नहीं है। सरकार और अदालतों की ऐसी टिप्पणियों के बाद सवाल यह पैदा हुआ था कि क्या ये टावर वास्तव में घातक हैं या फिर टेलीकॉम कंपनियां समस्या का समाधान देने से कतरा रही हैं? चूंकि मोबाइल रेडिएशन की आशंकाएं दुनिया भर में रही हैं, इसलिए इस मामले में एक पहल खुद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने की थी। इस संगठन ने वर्ष 2010 में एक रिपोर्ट जारी कर कहा था कि मोबाइल फोन से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तक के शोध इसे साफ तौर पर सेहत का दुश्मन साबित नहीं कर पाए हैं। हालांकि इस रिपोर्ट में टिप्पणी सेलफोन पर की गई थी, न कि मोबाइल टावरों पर। लेकिन 2011 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की राय बदल गई। उसने अपनी एक अन्य रिपोर्ट में दावा किया कि मोबाइल फोन के इस्तेमाल से एक विशेष प्रकार के कैंसर होने की आशंका हो सकती है। संगठन की कैंसर रोधी एजेंसी ने कहा था कि सबूतों की समीक्षा करने पर पता चला कि मोबाइल फोन के कारण कैंसर होने से इन्कार नहीं किया जा सकता। हालांकि इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि 'यह स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं हो पाया है कि मोबाइल फोन से कैंसर होता है।' जहां तक हमारे देश की बात है, तो वर्ष 2011 में संचार तथा सूचना तकनीक मंत्रालय की ओर से बनाई गई हाई लेवल कमिटी ने अपनी रिसर्च के आधार पर नतीजा निकाला था कि मोबाइल फोन और टावर, दोनों ही सच में हमारी सेहत के बड़े विलेन हैं। इस कमिटी ने सेलफोन और उनके टावरों से रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी के रूप में निकलने वाले रेडिएशन को तितलियों, मधुमक्खियों और गौरैया के विलुप्त होने के लिए भी जिम्मेदार माना था। ये शोध कहते हैं कि मोबाइल फोन का रेडियो-फ्रीक्वेंसी (आरएफ) फील्ड शरीर के टिश्यूज (उतकों) को प्रभावित करता है।

वैसे तो हमारे शरीर का एनर्जी कंट्रोल मैकेनिज्म आरएफ एनर्जी के कारण पैदा गर्मी को बाहर निकालता रहता है, पर कुछ शोधों में साबित हुआ कि मोबाइल फोन से निकलने वाली ऊर्जा ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, आर्थराइटिस, अल्झाइमर और हार्ट डिजीज जैसे रोगों का कारक हो सकती है। ठीक उसी तरह जैसे माइक्रोवेव में पकाए जाने वाले भोजन में मौजूद पानी इसके विकिरण के असर से सूख जाता है, उसी तरह मोबाइल रेडिएशन हमारे खून की गुणवत्ता और दिमाग की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। पर दूसरी बड़ी समस्या है इनके ट्रांसमिशन टावर, जो शहरों में तकरीबन हर गली-मोहल्ले में घरों की छतों पर कुकुरमुत्तों की तरह उग आए हैं। आप किसी तरह खुद को मोबाइल फोन से दूर कर लें, उसे रेडिएशन-मुक्त बनाने वाले किसी खोल से ढक दें, पर इनके टावरों से पैदा होने वाले रेडिएशन से कैसे बचेंगे?

गौरवशाली भारत के स्वामी प्रकाशक एवं मुद्रक प्रवीण कुमार सिंह द्वारा आला प्रिंटिंग प्रेस 3636 कटारा दिना बेग लाल कुआं, दिल्ली.... से मुद्रित एवं, ब्लॉक नं. 23 मकान नं. 399 त्रिलोकपुरी दिल्ली....91 से प्रकाशित संपादक -प्रवीण कुमार सिंह टेलीफोन नं. 011.22786172 फैक्स नं. 011.22786172
RNI, No. DELHIN383334, E-mail: gauravashalibarat@gmail.com इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के पीआरबी एट के तहत

यूपी बोर्ड की इंटर की भी परीक्षा रद, 12वीं के विद्यार्थी भी होंगे प्रोन्नत

लखनऊ । कोरोना वायरस संक्रमण की सेकेंड स्ट्रेन के कारण पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देश के बाद सीबीएसई तथा सीआइएससीई के कक्षा 12 की परीक्षा के रद करने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इंटरमीडिएट की परीक्षा को रद कर दिया है। अब 12वीं के विद्यार्थियों को भी प्रोन्नत किया जाएगा। गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। हाईस्कूल की परीक्षा पहले ही निरस्त की जा चुकी है।

यूपी बोर्ड के सौ साल के इतिहास में यह पहला मौका है, जब हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा निरस्त की गई है। विद्यार्थी बिना इम्तिहान दिए ही अगली कक्षा में प्रोन्नत किए जाएंगे। इंटरमीडिएट के 26.1 लाख और हाईस्कूल के 29.4 लाख विद्यार्थियों को प्रोन्नत किया जाएगा। इस तरह प्रदेश के कुल 56 लाख से अधिक विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे। उप मुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार ने हाई स्कूल के बाद इंटरमीडिएट की परीक्षा भी निरस्त कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोविड महामारी की वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से हमने कक्षा 12वीं की परीक्षा को रद करने का यह निर्णय लिया है। वर्तमान शैक्षिक सत्र में माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा।

सीएम योगी के साथ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा समेत शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों के साथ करीब 30 मिनट बैठक चली। 10:30 बजे शुरू हुई बैठक 11:00 बजे समाप्त हुई। शिक्षा बोर्ड की कमेटी ने रिपोर्ट मुख्यमंत्री के सामने पेश की। इसमें परीक्षा रद करने के बाद परीक्षार्थियों के अन्य विकल्प के सुझाव दिए गए हैं। डिप्टी सीएम डॉ. दिनेश शर्मा की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ करीब आधा घंटा की बैठक के बाद प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक परिषद यानी यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट की परीक्षा को भी रद कर दिया। इस बैठक में अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा अराधना शुक्ला तथा शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा के साथ अन्य अधिकारी भी मौजूद थीं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के करीब सौ वर्ष के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कक्षा 10 तथा कक्षा 12 की परीक्षा को रद किया गया। अब यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट के

विद्यार्थी भी अगली कक्षाओं में प्रोन्नत होंगे। औपचारिक घोषणा शाम तक की जाएगी लेकिन विद्यार्थियों की प्रोन्नति का रास्ता साफ हो गया है।

क्या बोले डिप्टी सीएम डॉ. दिनेश शर्मा

डिप्टी सीएम डॉ. दिनेश शर्मा ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीबीएसई की परीक्षा के रद करने के ऐलान के बाद हम भी तैयारी कर रहे थे। पीएम मोदी के लिए हमेशा से ही बच्चों का भविष्य और स्वास्थ्य पहली प्राथमिकता रही है। कोरोना काल की परिस्थितियों को देखते हुए बच्चों के हित में लिए गए इस निर्णय से न केवल बच्चों को बल्कि उनके अभिभावकों को भी राहत मिलेगी। यह निर्णय भी उसी दिशा में लिया गया कदम है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार पहले ही कक्षा 6 से लेकर कक्षा 11 की परीक्षा को रद कर चुकी थी। स्टूडेंट्स को प्रमोट किया है। अब जल्द ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 व कक्षा 12 के बच्चों के बारे में फैसला लेंगे। बोर्ड ने कक्षा 12 की फरवरी में हुई प्रीबोर्ड परीक्षा का रिकॉर्ड मांगा है। बोर्ड सचिव ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षक से 28 मई की शाम तक वेबसाइट पर अंक अपलोड करने का निर्देश दिया था

हाई स्कूल के बाद इंटर के विद्यार्थी भी प्रोन्नत- यूपी बोर्ड हाईस्कूल के 29.9 लाख विद्यार्थियों की परीक्षा निरस्त कर उन्हें पहले ही प्रोन्नति देने का फैसला किया है। अब इंटरमीडिएट के 26.1 लाख विद्यार्थियों को भी प्रोन्नति दी जाएगी। यूपी बोर्ड ने इसकी तैयारी पहले से ही कर ली थी। यूपी बोर्ड के सचिव ने 22 मई को ही सभी कालेजों से कक्षा 12 की प्रीबोर्ड और 11 की छमाही व वार्षिक परीक्षा के अंक मांगे थे। इस निर्देश पर 28 मई तक अधिकांश स्कूल छात्र-छात्राओं के अंक का ब्योरा भेज चुके हैं। बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने 22 मई को ही सभी स्कूलों से क्लास 12 के प्री-बोर्ड और 11वीं के छमाही व वार्षिक परीक्षा के अंक मांगे थे, 28 मई तक अधिकांश स्कूल छात्र-छात्राओं के अंक डाटा भी ऑनलाइन पोर्टल पर फीड कर दिया।

इंटर में 26 लाख से अधिक परीक्षार्थी

यूपी बोर्ड 12वीं की परीक्षा के लिए 26,09,501 स्टूडेंट्स पंजीकृत हैं। बोर्ड की हाईस्कूल की परीक्षाएं पहले ही रद कर दी गई हैं। सीबीएसई के बाद आईसीएसई ने भी 12वीं की परीक्षाएं रद करने की घोषणा की थी। इस वर्ष यूपी बोर्ड में करीब 56 लाख छात्र-छात्राएं (29,94,312 छात्र हाईस्कूल में पंजीकृत, 26,09,501 छात्र इंटरमीडिएट में पंजीकृत) हैं। हाईस्कूल की परीक्षा पहले रद कर दी गई थी। अब 12वीं की परीक्षा भी रद कर दी गई है। छात्र संख्या के हिसाब से यूपी बोर्ड देश का सबसे बड़ा परीक्षा बोर्ड है।

मूल्यांकन के दो विकल्प- यूपी बोर्ड के 12वीं के छात्र-छात्रा का मूल्यांकन पिछली दो कक्षाओं (10वीं और 11वीं) की अंतिम परीक्षाओं और 12वीं की आंतरिक परीक्षाओं में प्रदर्शन के आधार पर हो सकता है। या फिर कक्षा 10वीं के बोर्ड के परिणाम को कुछ वेटेज दिया जा सकता है और कुछ वेटेज कक्षा 12वीं के आंतरिक मूल्यांकन को दिया जाएगा।

संक्षिप्त खबर

मेरठ में युवती से छेड़छाड़ कर रहे युवकों को कार सवार महिला ने सिखाया सबक, भाग निकले तीनों

मेरठ । मेरठ में सड़क पर पैदल जा रही युवती से स्कूटी सवार तीन युवकों ने छेड़छाड़ कर दी। विरोध करने पर उससे हाथापाई शुरू कर दी। तभी कार सवार महिला आरोपितों पर टूट पड़ी। शोर सुनकर आसपास के लोगों ने भी मनचलों को धुन दिया। हालांकि हंगामे के दौरान तीनों आरोपित स्कूटी छोड़कर भाग गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर स्कूटी को कब्जे में ले लिया है।

यह है मामला- नौचंदी थाना क्षेत्र के सेक्टर तीन गुरुद्वारा रोड पर एक युवती पैदल जा रही थी। तभी स्कूटी सवार तीन युवक पहुंचे और छेड़छाड़ करने लगे। विरोध करने पर हाथापाई शुरू कर दी। इस दौरान एल ब्लाक निवासी मुकेश त्यागी पत्नी मनोज के साथ कार से जा रहे थे। मामला देखते ही मनोज गाड़ी रुकवाकर मनचलों पर टूटी पड़ी। शोर शराबा होने पर आसपास के लोग भी एकत्र हो गए और आरोपितों की पिटाई शुरू कर दी।

आरोपित भाग निकले- हालांकि हंगामे के दौरान तीनों आरोपित भाग गए। सूचना पर पुलिसकर्मी भी पहुंच गए थे। थाना प्रभारी प्रेमचंद शर्मा ने बताया कि पुलिस ने स्कूटी को कब्जे में ले लिया है। राहगीर निखिल गोयल की तहरीर पर तीन अज्ञात युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। स्कूटी से मिले कागजात और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर आरोपितों की तलाश की जा रही है। जल्द ही उनको दबोच लिया जाएगा। बताया कि इस मामले में ना तो युवती तहरीर देने आई थी और ना ही अन्य कोई थाने आया।

पिता के दोस्त पर छेड़छाड़ का आरोप- मेरठ के परतापुर थाना क्षेत्र के एक ग्राम निवासी किशोरी के मुताबिक एक सप्ताह पहले वह अपने कमरे में लेटी हुई थी। उसी दौरान उसके पिता का मित्र घर आ गया। किशोरी की मां उसके लिए चाय बनाने लगी। आरोप है कि इसी बीच आरोपित कमरे में घुसकर किशोरी से छेड़छाड़ करने लगा। शोर सुनकर उसकी मां भी आ गई। विरोध करने पर आरोपित ने किशोरी व उसकी मां को जान से मारने की धमकी दी। एक सप्ताह बाद भी थाने में आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। गुरुवार को किशोरी ने एसपी क्राइम से मामले की शिकायत की है। परतापुर थाना प्रभारी नजीर अली खान का कहना है कि किशोरी की मां और उसके पिता में विवाद चल रहा है। मामले की जांच की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे। उसी के अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।

नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने वाले की काट लेंगे अंगुली, बिहार में आमने-सामने बीजेपी और जदयू

पटना । कोरोना संक्रमण का प्रसार रोकने को बिहार में लॉकडाउन है पर राजनीति में उबाल आ गया है। अब एनडीए में साथी बीजेपी और जदयू आमने सामने हैं। बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडेय के बयान ने गुरुवार को तूल पकड़ लिया है। सिवान में एंबुलेंस घोटाले से शुरू हुई राजनीति के थमने से पहले अब जदयू ने बीजेपी पर बड़ा हमला किया है। जदयू प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा है कि जो नीतीश कुमार पर सवाल करेगा उसकी अंगुली काट लेंगे।

गौरतलब है कि बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडेय ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि मैं नीतीश कुमार जिंदाबाद नहीं कहूंगा। नीतीश परिस्थितियों के सीएम हैं। टुन्ना ने कहा कि नीतीश हमारे नेता नहीं हैं, हां वह एनडीए का हिस्सा हैं और बिहार के मुख्यमंत्री जरूर हैं। मेरे लिए सिवान की जनता ही सबकुछ है। टुन्ना ने कहा था कि पिछले साल संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव में जनता ने तेजस्वी यादव को सबसे अधिक मत देकर चुना था, लेकिन नीतीश कुमार ने सरकार तंत्र का इस्तेमाल करते हुए सत्ता पा ली।

बीजेपी ने आपत्ति जता मांगा स्पष्टीकरण- हालांकि टुन्ना के बयान पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई है। भाजपा ने नोटिस जारी करते हुए टुन्ना से स्पष्टीकरण मांगा है। टुन्ना के नीतीश पर दिए बयान को लेकर गुरुवार को जदयू ने पलटवार किया है। एक टीवी चैनल से बात करते हुए जदयू प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि टुन्ना पांडेय क्या करते हैं, यह सब जानते हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी नीतीश कुमार के खिलाफ बोलेगा उसकी अंगुली काट ली जाएगी। नीतीश हमारे नेता हैं, उनके खिलाफ किसी भी तरह का आपत्तिजनक बयान सहन नहीं किया जाएगा। संजय ने कहा कि बीजेपी अपने नेताओं को संभाल ले।

जालंधर के एकता नगर के 35 परिवार आप में शामिल, पार्टी नेताओं ने माला पहना किया स्वागत

जालंधर । विधानसभा हलका जालंधर सेंट्रल के अंतर्गत आते एकता नगर, रमा मंडी के 35 परिवार आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। आप पंजाब डॉक्टर विंग के राज्य सह अध्यक्ष डॉ. संजीव शर्मा और आप की खेल शाखा के प्रदेश अध्यक्ष करतार सिंह पहलवान ने लोगों को माला पहनाकर पार्टी में शामिल कराया। डॉक्टर संजीव शर्मा ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विकास कार्यों और दिल्ली मॉडल से प्रेरित होकर लो पार्टी में शामिल हो रहे हैं। डॉ. संजीव ने कहा कि कैप्टन सभी मोर्चों पर विफल रहे हैं और बेरोजगारी केवल आम लोगों के लिए है, जबकि विधायकों और सांसदों के परिजनों को रोजगार दिया जाता है।

पार्टी में शामिल होने वालों में सेवानिवृत्त निरीक्षक सतर्कता प्रेम कुमार, विक्रम शर्मा, परमिंदर सिंह, भूपिंदर, गुरमीत, गुरदीप सिंह और अन्य शामिल थे। इस मौके पर पार्टी की तरफ से वरिष्ठ सदस्य सुभाष प्रभाकर, गुरप्रीत कौर, परितोष शर्मा, तेजपाल सिंह, संजय गिल, राजीव आनंद आदि उपस्थित थे।

जालंधर। भाजपा महिला मोर्चा पंजाब की प्रधान मोना जैसवाल ने किसान आंदोलन के समर्थन में इस्तीफा देने वाली महिलाओं के भाजपा कार्यकर्ता होने से इंकार किया है। मोना जैसवाल ने कहा कि भाजपा को बदनाम करने के लिए विपक्षी दल अपनी महिला कार्यकर्ताओं को भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता बताकर घटिया राजनीति पर उतर आई है। उधर मंगलवार को किसान आंदोलन के समर्थन में इस्तीफा देने वाली पदाधिकारियों ने भाजपा महिला मोर्चा की जिला प्रधान मीनू शर्मा के साथ एक कार्यक्रम की संयुक्त फोटो जारी कर मोना जैसवाल के दावे को खारिज किया। इस्तीफा देने वाली महिलाएं पार्टी कार्यक्रम में मीनू शर्मा के साथ नजर आ रही हैं। इस कार्यक्रम में पूर्व प्रधान सुखराज कौर भी हैं तो पहले ही किसानों के मुद्दे पर पार्टी छोड़ चुकी हैं।

जमशेदपुर में हैं तो अपने सामान का रखें खास ख्याल, यहां पुलिस से नहीं डरते चोर

जमशेदपुर । झारखंड के जमशेदपुर शहर में एक बार फिर चोर गिरोह सक्रिय हो गए हैं। लगातार चोरी को अंजाम दे रहे हैं। गिरोह ने स्कूल और दो घरों को निशाना बनाया। चार बाइक भी अलग-अलग स्थानों से एक जून को चुरा ले गए। पुलिस की कार्रवाई प्राथमिकी दर्ज किए तक सीमित रह गई। पटमदा के बामनी उत्क्रमित मध्य विद्यालय का ताला तोड़ चोरों ने चावल, बच्चों की खेल सामग्री, वाद्ययंत्र, बिजली स्टेबलाइजर चुरा लिया। विद्यालय के प्रधानाध्यापक मानगो डिमना रोड निवासी विनय कुमार पांडेय की शिकायत पर पटमदा थाना में चोरी की प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। एक जून को भाजपा नेता अप्पा राव की गोलमुरी टिनप्लेट चौक के सामने जनरल स्टोर में चोरी की घटना हुई थी। **दो थाना इलाके में भी चोरी-** आजादनगर थाना क्षेत्र रोड नंबर एक वेस्ट गोलघर के पास मो. अफजल की फर्नीचर दुकान में घुसकर चोरों ने 50 हजार मूल्य का सामान चुरा लिया। इस मामले में आजादनगर थाना में सिकंदर, बिट्टू अंसारी, मो. चांद उर्फ नौशाद अख्तर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। सभी आरोपित कदमा शास्त्रीनगर ब्लाक संख्या दो के निवासी है। पुलिस ने मामले में बिट्टू अंसारी को गिरफ्तार किया है। उसे पास से एक पेपर मशीन और एक कटर मशीन बरामद किया गया। अन्य आरोपितों की तलाश पुलिस कर रही है। मानगो थाना क्षेत्र गुरुद्वारा रोड में मनोज किराना स्टोर के संचालक ऋषि कुमार की घर में घुसकर अज्ञात ने नगद समेत अन्य सामान चुरा लिया। उलीडीह थाना क्षेत्र डिमना बस्ती साधु कालोनी निवासी परितोष प्रधान की घर में घुसकर चोर ने लैपटॉप चुरा लिया।

यहां भी बइक की चोरी- परसुडीह थाना क्षेत्र हलुदबनी सिद्धार्थ अपार्टमेंट निवासी संतोष राय के घर के सामने से अज्ञात ने बाइक चुरा ली। परसुडीह थाना में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र एलआइसी बिल्डिंग पार्किंग स्टैंड से बागबेड़ा हरहरगुट्टू निवासी नागेंद्र बच्चन की बाइक की चोरी एक जून को हो गई। सिदगोड़ा थाना क्षेत्र पदमा रोड निवासी विनोद मुखी की बाइक टिनप्लेट टाउन सर्विस के सामने से और कदमा कागलनगर रोड एफ रोड से एक व्यक्ति की बाइक दो जून को चोरी हो गई।

प्रियंका गांधी के प्रयासों से हुआ रास्ता साफ, पंजाब में सुखपाल खैहरा सहित आप के तीन बागी विधायक कांग्रेस में शामिल

चंडीगढ़ । आम आदमी पार्टी के तीन बागी विधायक सुखपाल खैहरा, पिरमल सिंह (भदौड़ से) और जगदेव सिंह कमालू (मौड़ से) कांग्रेस में शामिल हो गए। वीरवार को दिल्ली रवाना होने से पूर्व कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन्हें पार्टी में शामिल करवाया। कैप्टन ने कहा कि तीनों विधायकों को कांग्रेस में शामिल करने की पार्टी प्रधान सोनिया गांधी से स्वीकृति पहले ही ले ली गई थी।

तीनों विधायकों की कांग्रेस पार्टी में उस समय एंट्री हुई है जब कांग्रेस में क्लेश चल रहा है। इस क्लेश को शांत करने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने तीन सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया हुआ है। कमेटी के सामने पेश होने के लिए जाने से पहले मुख्यमंत्री ने तीनों विधायकों को पार्टी ज्वाइन करवा कर आम आदमी पार्टी को झटका दिया है। तीनों विधायकों ने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने स्पीकर को इस्तीफा भेज दिया है।

सुखपाल खैहरा, पहले भी भुलत्थ विधान सभा क्षेत्र से कांग्रेस के एमएलए रह चुके हैं, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह से सुर न मिलने के कारण उन्होंने दिसंबर 2015 में पार्टी को अलविदा कहकर आम आदमी पार्टी का झाड़ू थाम लिया था। यह वह दौर था जब पंजाब में आम आदमी पार्टी राजनीतिक रूप से ऊंचाइयां छू रही थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में खैहरा आप के विधायक बने। आप ने एचएस फूलका को नेता प्रतिपक्ष बनाया लेकिन महज 4 महीने के बाद ही फूलका ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जिसके बाद पार्टी ने सुखपाल खैहरा को नेता विपक्ष बना दिया। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल द्वारा अकाली दल के विधायक व पूर्व मंत्री बिक्रम मजीठिया से ड्रग्स वाले मामले में माफी मांगने के चलते खैहरा नाराज हो गए।

उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने उन्हें विश्वास में नहीं लिया। उनके साथ लगभग आठ विधायक भी बागी होकर अलग ग्रुप चलाने लगे। इस बीच आप ने इन विधायकों को निलंबित कर दिया। इसी ग्रुप में कमालू और पिरमल सिंह भी थे। खैहरा ने 2019 में आप से इस्तीफा देकर पंजाबी एकता पार्टी बनाई और बठिंडा से लोक सभा चुनाव लड़े। जहां उनकी जमानत तक जब्त हो गई। सुखपाल खैहरा के दो अन्य विधायकों के साथ कांग्रेस में शामिल होने के पीछे प्रियंका गांधी का हाथ है। किसान आंदोलन में मारे गए युवा किसान नवरीत सिंह डिबडिबा के भोग अवसर पर रूदरपुर में सुखपाल खैहरा प्रियंका गांधी से मिले थे। असल में जब वह भोग के अवसर पर भाषण दे रहे थे उस समय प्रियंका गांधी और रणदीप सुरजेवाला भी समारोह में थे।

सुरजेवाला ने ही प्रियंका गांधी को बताया कि यह पहले कांग्रेस में ही थे, लेकिन नाराज होकर आप में शामिल हो गए। इस पर प्रियंका गांधी ने सुरजेवाला से खैहरा को उनसे मिलवाने को कहा। उसी मुलाकात में खैहरा के कांग्रेस में वापसी का रास्ता साफ हो गया। इसके लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी विश्वास में लिया गया। चूंकि खैहरा के बहनोई रि. जस्टिस रणजीत सिंह मुख्यमंत्री के खासे करीबी है। अतः मुख्यमंत्री ने भी खैहरा की घर वापसी को हरी झंडी दे दी। कई दिनों से चर्चाएं थी कि आप के बागी नेता सुखपाल खैहरा दो अन्य विधायकों पिरमल सिंह व जगदेव सिंह के साथ कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। यह तीनों विधायक आज कैप्टन के साथ रवाना हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये विधायक आज ही कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा कर सकते हैं। हालांकि इससे पहले खैहरा का कहना था कि उनके कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा विरोधी फैला रहे हैं। बता दें, सुखपाल सिंह खैहरा आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के बिक्रम मजीठिया से माफी मांगने से खफा हो गए थे। उन्होंने आप के खिलाफ बगावत कर दी और आधा दर्जन के करीब विधायक आप से बागी होकर उनके साथ आ गए थे। इन सभी ने मिलकर एक नया ग्रुप बना लिया था। आप ने जुलाई 2018 में सुखपाल सिंह खैहरा को विपक्ष के नेता से हटा दिया था।

इससे पहले आप के बागी विधायक जगदेव सिंह कमालू ने माना था कि कांग्रेस नेताओं ने उनसे संपर्क जरूर किया है, लेकिन अभी वह किसी पार्टी में शामिल होने का मन नहीं बना पाए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि शिअद ने भी उन्हें पेशकश दी है, लेकिन बेअदबी के मुद्दे पर हलके में अकाली दल का विरोध हो रहा है, इसलिए उन्होंने अकाली नेताओं को साफ मना कर दिया है। विधायक पिरमल सिंह का कहना था कि वह लंबे समय से लाइनमैन की मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वह दावा करते हैं कि उन्होंने कई लाइनमैन की नौकरी पक्की करवा दी है। 59 का मामला उनकी आयु ज्यादा होने के कारण लटका है। सरकार के पास काफी पावर होती है। यदि मुख्यमंत्री चाहें तो वह इन्हें पक्का कर सकते हैं। इसके बाद ही वह कुछ विचार करेंगे।

झांसी को भी कोरोना कर्फ्यू से छूट, अब यूपी के 10 जिलों में पाबंदिया

लखनऊ । कोरोना संक्रमण की भयावह स्थिति की वजह से करीब एक माह तक प्रतिबंधों में जकड़े रहे उत्तर प्रदेश की स्थिति काफी हद तक सुधर चुकी है। इसे देखते हुए ही सरकार ने व्यवस्था बना दी है कि जिन जिलों में कोरोना के 600 से कम सक्रिय मामले होंगे, वहां आंशिक कोरोना कर्फ्यू से छूट दे दी जाएगी। अब तक 64 जिले इस श्रेणी में थे और गुरुवार को जारी रिपोर्ट के आधार पर झांसी को भी प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया गया। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात पर चिंता जताई है कि कुछ जिलों में लापरवाही की जा रही है। बाजारों में कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लोकभवन स्थित अपने कार्यालय में की। उन्होंने कहा कि कोरोना की कम होती संक्रमण दर को देखते हुए पिछले दिनों 600 एक्टिव केस से कम संख्या वाले 64 जिलों को आंशिक कोरोना कर्फ्यू से छूट दी गई थी।

ताजा स्थिति के अनुसार झांसी में भी सक्रिय मामले 600 से कम हो गए हैं। अब यहां भी सप्ताह में पांच दिन सुबह सात से शाम सात बजे तक कोरोना कर्फ्यू से छूट दी जाए। साप्ताहिक व रात्रिकालीन बंदी सहित अन्य सभी संबंधित नियम इन जिलों में लागू होंगे। इसके बाद अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी की ओर से इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया।

पुलिस-प्रशासन को सक्रियता बढ़ाने की जरूरत : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा के दौरान कहा कि कई जिलों में लोगों के मास्क न लगाने, बाजारों में अनावश्यक भीड़, शारीरिक दूरी का पालन न करने जैसी जानकारी मिली है। यह स्थिति किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई जीतने के लिए हर एक नागरिक का सहयोग जरूरी है। पुलिस-प्रशासन को सक्रियता बढ़ाने की जरूरत है।

टीकाकरण में शरारत बर्दाश्त नहीं : सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोविड प्रोटोकाल के पालन के साथ ही टीकाकरण को लेकर भी आगाह किया। उन्होंने कहा कि देश के कुछ क्षेत्रों के साथ-साथ प्रदेश के कुछ जिलों से टीकाकरण में लापरवाही या शरारतपूर्ण गतिविधियों की जानकारी आई है। यह कतई उचित नहीं है और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन घटनाओं को आपराधिक मानते हुए दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ रही कोरोना वायरस संक्रमण से रिकवरी दर, अब एक्टिव केस 25,546

लखनऊ । वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ ट्रैक, टेस्ट तथा ट्रीट फॉर्मूला पर बेहद असरदार अमल का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या दिन पर दिन कम होती जा रही है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में तीन लाख 40,411 सैंपल में से 1268 नए संक्रमित मिले हैं। इस दौरान 108 लोगों की मौत भी हुई है।

प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 25,546 रह गई है। प्रदेश में रिकवरी दर 97.30 प्रतिशत हो गई है। पॉजिटिविटी दर इस वक्त 3.4 प्रतिशत हो गई है। कोविड की दूसरी लहर में भी प्रदेश पटरी पर आ रहा है। प्रदेश में कोविड के एक्टिव केस की संख्या अब महज 25,546 रह गई है। नए संक्रमितों की संख्या अब दहाई तक सिमट गई है। बीते 24 घंटे में लखनऊ में सर्वाधिक 75 तथा मेरठ में 55 नए मामले आए हैं। कानपुर में 15 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि दस की मौत हुई है। लखनऊ में छह की मौत हुई है। प्रदेश में महीने भर में 13 प्रतिशत पॉजिटिविटी रेट घटा है। एक महीने पहले यह 14.1 प्रतिशत था और अब यह घटकर 0.4 फीसद रह गया है। अब हर दिन 30 से ज्यादा जिलों में 10 से कम नए संक्रमित मिल रहे हैं। अब तक 1,55,01,696 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज़ दे चुके हैं और 35,32,960 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज़ भी दे चुके हैं। अब तक कुल मिलाकर 1,90,34,656 डोज़ दिए जा चुके हैं। कल 18-45 आयु वर्ग के 1,96,337 लोगों ने वैक्सीन की डोज़ ली।

प्रदेश में एक्टिव केस के मामले में अब मेरठ में 1625, सहारनपुर में 1601, लखनऊ में 1465, वाराणसी में 1458, मुजफ्फरनगर में 1267, गोरखपुर में 995, गौतमबुद्धनगर में 730, गाजियाबाद में 727, बरेली में 719 एक्टिव केस हैं।

लालू ने मुख्यमंत्री नीतीश को अपने अंदाज में दी व्यंग्य भरी बधाई, पहले भी कर चुके हैं नोबेल पुरस्कार की मांग

पटना । नीति आयोग द्वारा गुरुवार को जारी सतत विकास लक्ष्यों के लिए सूचकांक के मुताबिक केरल टॉप पर है तो बिहार पहले की ही तरह सबसे नीचे है। सीधे-सीधे कहें तो रिपोर्ट में बिहार का प्रदर्शन बेहद खराब है। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में बिहार के साथ असम और झारखंड भी हैं। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने इसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को व्यंग्य भरी बधाई दी है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि 16 वर्षों की बिहारनाशक मेहनत से नीतीश कुमार ने बिहार को नीचे से टॉप करा ही दिया। इसके पहले हाल ही में लालू ने एक और व्यंग्य में नीतीश कुमार को बिहार की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए नोबेल पुरस्कार देने की मांग की थी।

लालू ने नीतीश कुमार को दी व्यंग्यपूर्ण बधाई- गुरुवार को नीति आयोग ने एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 जारी किया। इसमें केरल अव्वल तो बिहार सबसे नीचे है। लालू प्रसाद यादव ने इसपर प्रकशित एक मीडिया रिपोर्ट को का संदर्भ लेते हुए अपने ट्वीट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसके लिए व्यंग्यपूर्ण बधाई दी है। ट्वीट के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 16 वर्षों की बिहारनाशक मेहनत के कारण नीति आोग की रिपोर्ट में राज्य सबसे नीचे रहा है।

पहले भी कर चुके हैं नाबोल पुरस्कार की मांग- लालू ने नीतीश पर हाल ही में एक और व्यंग्य वाण छोड़ते हुए उनके लिए नोबेल पुरस्कार की मांग की थी। बिहार के मधुबनी जिले के हरलाखी प्रखंड के उपस्वास्थ्य केंद्र की बदहाल स्थिति की तस्वीर के साथ अपने ट्वीट में लालू ने लिखा था कि ऐसे सैकड़ों स्वास्थ्य केंद्र बंद कराने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया जाना चाहिए। इस ट्वीट में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय के लिए भी नोबेल पुरस्कार की मांग की थी।

चुटीले अंदाज में विरोधियों पर करते रहे हैं हमला- लालू प्रसाद यादव अपने चुटीले अंदाज से विरोधियों पर हमला के लिए जाने जाते हैं। बिहार की राजनीति में जमीनी पकड़ के कारण उनके विरोणी भी उन्हें नजरअंदाज नहीं करते हैं। लालू के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर वैसे सभी नेता रहते आए हैं, जो उनकी राजनीति के विरोधी रहे हैं।

गोरखपुर में हार से खीझे पूर्व प्रधान प्रतिनिधि ने ग्रामीणों से किया विवाद, रिश्तेदार ने की फायरिंग

गोरखपुर । चुनावी हार से खीझे खोराबार थाना क्षेत्र के ग्राम हक्काबाद पूर्व प्रधान प्रतिनिधि व उनके भाई ने दोपहर गांव में ट्रांसफार्मर लगने का जमकर विरोध किया। ग्रामीणों को गालियां दी। एक सेवानिवृत्त सिपाही ने इसका विरोध किया तो फोन करके अपने रिश्तेदारों को भी मौके पर बुला लिया। इसमें एक रिश्तेदार ने सिपाही पर फायरिंग भी की, लेकिन गोली मिस होने से उनकी जान बच गई। पुलिस पूर्व प्रधान प्रतिनिधि व उनके भाई को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, जबकि गोली चलाने वाला व्यक्ति मौके से फरार हो गया है।

हक्काबाद गांव में बीते 3 दिन से बिजली नहीं थी। दोपहर करीब एक बजे बिजली विभाग के कर्मचारी ट्रांसफार्मर लगाने पहुंचे थे। कई ग्रामीण भी ट्रांसफार्मर को पोल पर चढ़ाने के लिए मदद कर रहे थे। इस दौरान पूर्व प्रधान प्रतिनिधि लाल बहादुर यादव का भाई कुंवर बहादुर यादव ने ट्रांसफार्मर लगने का विरोध शुरू कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व प्रधान प्रतिनिधि लाल बहादुर व उसका भाई कुंवर बहादुर गांव वालों पर वोट न देने की बात कहते हुए ट्रांसफार्मर लगाने का विरोध कर रहा था। ग्रामीणों ने उनका जवाब दिया तो वह गाली गलौज करने लगे। उनके बीच हाथापाई की नौबत आ गई। इस दौरान कुंवर बहादुर ने गायघाट स्थित अपने बहनोई शत्रुघ्न व देश दीपक को भी मौके पर बुला लिया।

ग्रामवासी व सेवानिवृत्त सिपाही देव मन यादव ने आरोप लगाया कि शत्रुघ्न ने पिस्टल निकालकर उन पर फायर कर दिया । गनीमत रही कि फायर मिस हो गया । देव मन ने बताया कि उन्होंने शत्रुघ्न को पकडने की भी कोशिश की, लेकिन वह हाथ छुड़ाकर मौके से भाग निकला। उन्होंने कहा कि छीना झपटी के दौरान पिस्टल की दो गोलियां मौके पर ही ही गिर गईं। देश दीपक भी भागने में सफल रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूर्व प्रधान प्रतिनिधि व उनके भाई को हिरासत में ले लिया है। देवमन ने इस मामले में लालबहादुर यादव, उनके भाई कुंवर बहादुर, पिता रामाश्रे यादव व बहनोई शत्रुघ्न तथा देशदीपक के खिलाफ हत्या के प्रयास की नामजद तहरीर दी है। मौके से मिली दो कारतूसों को भी पुलिस को सौंपा है। प्रभारी निरीक्षक खोराबार राहुल ड्क्षसह का कहना है कि लाल बहादुर व कुंवर बहादुर को हिरासत में लेकर मामले की जांच की जा रही है।

वैक्सीन की अलग-अलग कीमत पर झामुमो बोला, यह पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का तरीका

रांची । झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आरोप लगाया है कि देश में वैक्सीन की अलग-अलग कीमत पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का तरीका है। इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन की चार से आठ गुना कीमत चुका वैक्सीन लगाने को मजबूर किए जा रहे देशवासी भी टैक्स भरते हैं। इसके बावजूद चुनिंदा कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए देशवासियों के साथ अन्याय क्यों किया जा रहा है। ये संगठित लूट नहीं तो फिर क्या है यह बात झारखंड प्रदेश भाजपा के नेताओं को समझ में नहीं आती।

जनता के टैक्स से आने वाले पैसा का लाभ हम क्यों वैक्सीन निर्माताओं को पहुंचाएं। प्रतीत होता है कि यह इलेक्टोरल बांड के जरिए कमाई का प्लान है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक रोज कोस रहा है। झारखंड सरकार 175 करोड़ रुपये की लागत से 25 लाख कोविशिल्ड और 25 लाख कोवैक्सीन ले रही है। अगर केंद्र क्रय करती तो 175 करोड़ में दोनों के 50-50 लाख वैक्सीन आ जाते। भाजपा नेताओं पर तंज कसते हुए पार्टी ने कहा कि निश्शुल्क वैक्सीन की राज्य सरकार की मांग पर ये ऐसे प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, जैसे इन्हें अपनी जेब से पैसे भरने पड़ रहे हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कहा है कि निश्शुल्क वैक्सीन पर जल्द फैसला लेंगे। राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के पत्र के जवाब में उन्होंने यह भरोसा दिलाया है। मंत्री ने केंद्र सरकार से पूरे फ्री वैक्सीन देने का आग्रह किया है। मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि जब केंद्र सरकार ने बजट में 35 हजार करोड़ रुपये खर्च करने के लिए आवंटित किया था तो फिर आज क्यों तीन तरह की दर वैक्सीन के लिए लाए गए हैं। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने और भाजपा नेताओं ने पांच राज्यों के चुनाव में मुफ्त वैक्सीन देने का चुनावी नारा बुलंद किया।

जब वैक्सीन देने की बारी आई तो केंद्र सरकार के लिए अलग, राज्य सरकार के लिए अलग और प्राइवेट संस्थाओं के लिए अलग रेट लागू कर दिए। गौरतलब है कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन को पत्र लिखकर पूरे देश में वैक्सीन के तीन रेट का विरोध किया था।

बीकानेर सीमा पर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के अधिकारियों ने 3 करोड़ रुपये के ड्रग्स को पकड़ा।

हैदराबाद के चिलकुर गांव में ग्रामीणों ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की 9 फीट ऊंची प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए।

द्रमुक पार्टी के सदस्यों ने कोयंबटूर के पोलाची में अपनी पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री कलैग्नर करुणानिधि की 98वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी।

गरीबों व वंचितों के लिए चलेगा मोदी सरकार का विशेष अभियान, बनेंगे दो करोड़ राशन कार्ड

नई दिल्ली । जिनके राशन कार्ड न बन पाएं हों, वे जरूर बनवा लें। विशेष अभियान चलाकर समाज के गरीब, कमजोर और वंचित वर्ग के लोगों का राशन कार्ड बनाया जाएगा, ताकि उन्हें रियायती दर पर अनाज मुहैया हो सके। केंद्र सरकार ने इस बाबत सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी कर राशन कार्ड बनाने का अभियान शुरू करने को कहा है। निचले तबके के ऐसे लोगों को राशन कार्ड देकर उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में लाया जाएगा। केंद्रीय खाद्य सचिव सुधांशु पांडेय ने बताया कि देश के लगभग दो करोड़ लोगों को नया राशन कार्ड दिया जा सकता है। वे गुरुवार को पत्रकारों से वर्चुअल वार्ता कर रहे थे।

कूड़ा बीनने वालों, फेरीवालों, रिक्शा चालकों, प्रवासी श्रमिकों व बेघरों के बनेंगे कार्ड- उन्होंने बताया कि शहरी व ग्रामीण गरीबों, कूड़ा बीनने वाले, फेरीवाले, रिक्शा चालक, प्रवासी मजदूरों, बेघर लोग और घूमंतू परिवारों के राशन कार्ड बनाए जा सकते हैं। कोरोना संक्रमण के दौरान समाज के गरीब, कमजोर और वंचित वर्ग के लोगों को राशन न मिलने की खबरें सामने आई। स्थायी पता न होने की वजह से इन लोगों के राशन कार्ड ही नहीं बनाए जा सके हैं। राज्यों से कहा गया है कि वे समाज के निचले तबके के ऐसे लोगों को चिह्नित करने के लिए विशेष अभियान चलाकर उनके राशन कार्ड बनाएं।

4.39 करोड़ बोगस राशन कार्डों को रद कर उनकी जगह नए राशन कार्ड बनाए गए- खाद्य सचिव पांडेय ने बताया कि पूरे देश में 4.39 करोड़ बोगस राशन कार्डों को रद कर उनकी जगह नए राशन कार्ड बनाए गए हैं। इस प्रक्रिया में समाज के निचले तबके के लोगों को शामिल करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। खाद्य मंत्रालय की एडवाइजरी में 15 दिन में रिपोर्ट मांगी गई है।

गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना- कोरोना की दूसरी लहर के मद्देनजर केंद्र ने गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना घोषित की है। इसके तहत सभी राशन कार्ड धारकों को मई और जून महीने में प्रति व्यक्ति पांच किग्रा अतिरिक्त अनाज मुफ्त में दिया जा रहा है।

कोरोना की दूसरी लहर में 2 जून तक गई 624 डॉक्टर्स की जान, IMA ने दी जानकारी

नई दिल्ली । कोरोना की दूसरी लहर में डॉक्टर्स भी अछूते नहीं रह पाए हैं। संक्रमण की दूसरी लहर में 2 जून, 2021 तक 624 डॉक्टरों की जान गई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ताजा जानकारी दी है। बता दें इस संक्रमण की रफ्तार से धीरे-धीरे सभी क्षेत्र के लोग चेपट में आ चुके हैं। मंत्री, विधायक से लेकर मुख्यमंत्री तक इस भयंकर वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि कोरोना की दूसरी लहर का सामने कर रहे देश में फिलहाल मामलों में थोड़ी गिरवाट जरूर आई है। क्योंकि इससे पहले मई महीने में तो एक दिन 4 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले दर्ज किए जा चुके हैं।

देश में कोरोना वायरस की ताजा स्थिति - स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए ताजा आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में 1,34,154 नए संक्रमित मामलों को मिलाकर देश में 2,84,41,986 मामले हो गए हैं और मरनेवालों की संख्या 3,37,989 हो गई है। अब सक्रिय मामलों का आंकड़ो 17,13,413 पहुंच गया है। इतना ही नहीं अगर देश में प्रत्येक दिन नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं तो मरीज इस बीमारी को मात भी दे रहे हैं।

सीबीएसई के बाद यूपी और महाराष्ट्र ने भी 12 वीं की परीक्षा रद की

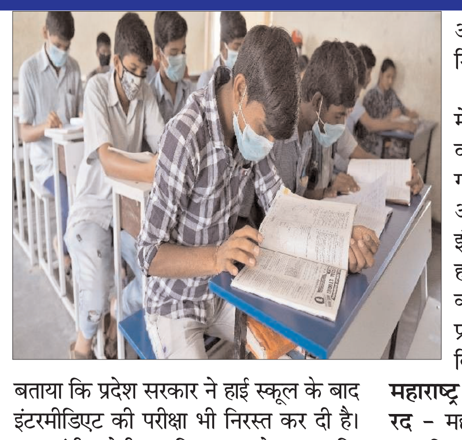

नई दिल्ली । केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के बाद कई राज्यों ने 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद करने का निर्णय लिया है। गुरुवार को उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ने भी 12 वीं बोर्ड की परीक्षा को रद करने का फैसला किया है। इससे पहले बुधवार को मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान और गोवा ने भी 12 वीं बोर्ड की परीक्षा को रद कर दिया है। गौरतलब है कि मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक में सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद करने का निर्णय लिया गया था। इसके एक दिन बाद गुरुवार को मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिम) की हायर सेकंडरी की परीक्षा रद कर दी है।

बता दें कि मंगलवार को परीक्षा रद करने की जानकारी देते हुए केंद्र सरकार ने कहा कि अब राज्यों के पास भी 12वीं परीक्षा रद करने का विकल्प होगा।। हालांकि 12वीं परीक्षा रद किए जाने को लेकर राज्यों पर कोई बाध्यता नहीं होगी। ऐसे में अब कई स्टेट बोर्डों द्वारा परीक्षाए रद किए जा रहे हैं।

यूपी में 12 की इंटरमीडिएट की परीक्षा रद की - उप मुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार ने हाई स्कूल के बाद इंटरमीडिएट की परीक्षा भी निरस्त कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोविड महामारी की वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से हमने कक्षा 12वीं की परीक्षा को रद करने का यह निर्णय लिया है। वर्तमान शैक्षिक सत्र में माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। सीएम योगी के साथ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा समेत शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों के साथ करीब 30 मिनट बैठक चली।

यूपी बोर्ड के सौ साल के इतिहास में यह पहला मौका है, जब हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा निरस्त की गई है। विद्यार्थी बिना इम्तिहान दिए ही अगली कक्षा में प्रोन्नत किए जाएंगे। इंटरमीडिएट के 26.1 लाख और हाईस्कूल के 29.4 लाख विद्यार्थियों को प्रोन्नत किया जाएगा। इस तरह प्रदेश के कुल 56 लाख से अधिक विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे।

महाराष्ट्र में 10 और 12 वीं की परीक्षा रद - महाराष्ट्र के मंत्री विजय वडेट्टीवार ने कहा कि महाराष्ट्र बोर्ड कक्षा 10 और 12 की परीक्षाएं रद कर दी गई हैं।

एमपी में 12वीं बोर्ड परीक्षा रद

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की राज्य बोर्ड ने भी 12वीं की परीक्षा को रद कर दिया है। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं इस वर्ष आयोजित नहीं की जाएंगी। बच्चों की ज़िंदगी हमारे लिए अनमोल है। करियर की चिंता हम लोग बाद में कर लेंगे। उन्होंने कहा कि 12वीं बोर्ड के रिजल्ट किस आधार पर तैयार किए जाएंगे ये तय करने के लिए मंत्रियों का एक समूह बनाया गया है। जो विशेषज्ञों से चर्चा करने के बाद आंतरिक मूल्यांकन या अन्य आधारों पर विचार करेंगे और रिजल्ट का तरीका तय करेंगे। सीएम शिवराज ने कहा कि हमने 10वीं बोर्ड की परीक्षा को न कराने का फैसला लिया था।

गुजरात बोर्ड ने भी 12वीं की परीक्षा रद की - सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के बाद अब गुजरात बोर्ड ने भी 12वीं की परीक्षा रद कर दी है। गुजरात सरकार ने बुधवार को 12वीं की परीक्षा रद करने का आदेश जारी किया। इससे पहले गुजरात कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें परीक्षा को रद करने पर आम सहमति बनी। कैबिनेट बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए हालात अभी भी ऐसे नहीं हैं कि बच्चों की सेहत को खतरे में डालने का जोखिम उठाया जा सके।

उत्तराखंड बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं रद - उत्तराखंड में अब 12वीं की परीक्षाएं भी रद हो गई। राज्य के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के मुताबिक देश में सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा को लेकर जो निर्णय हुआ है। राज्य सरकार उस फैसले से बाहर नहीं हैं। परिस्थितियों को देखते हुए परीक्षा रद करने का फैसला किया गया।

राजस्थान बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद - राजस्थान में बुधवार को अशोक गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला किया है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद कर दी गई है। शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने कहा कि कोरोना संकट के बीच परीक्षा ना कराने का फैसला लिया गया है। छात्रों के हित को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। इधर, गोवा में भी 12वीं की परीक्षाओं को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद करने की घोषणा की है।

ऐलान होना बाकी- खास बात यह है कि बोर्ड परीक्षाओं को रद किए जाने का लगातार समर्थन करने वाली झारखंड सरकार ने अभी तक 10वीं की परीक्षा रद नहीं की और न ही 12वीं परीक्षा पर कोई फैसला किया है, लेकिन सीबीएसई परीक्षा पर फैसला आने के बाद उम्मीद है कि अगले एक-दो दिन में झारखंड सरकार भी अपना फैसला बता सकती है।

ऐसे कम किया जा सकता है तीसरी लहर का कहर, एसबीआई इकोरैप ने अपनी रिपोर्ट में दिए ये सुझाव

नई दिल्ली । कोरोना की तीसरी लहर का प्रकोप बच्चों पर होने की आशंका के बीच ही एसबीआइ इकोरैप ने 12 से 18 साल के बच्चों के टीकाकरण पर जोर लगाने का सुझाव दिया है। रिपोर्ट का मानना है कि इस वर्ग समूह में 17 करोड़ लोगों को टीका लग जाए तो तीसरी लहर पर काफी हद तक लगाम लगाई जा सकेगी। एसबीआई इकोरैप ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कोरोना से लड़ाई में अगर हमारी तैयारी बेहतर रही तो दूसरी लहर की तुलना में गंभीर मरीजों की संख्या काफी कम हो सकती है।

20 फीसद मरीज गंभीर- दूसरी लहर में 20 फीसद मरीज गंभीर थे। तीसरी लहर में पांच फीसद ही गंभीर मरीज रह सकते हैं। इससे कोरोना की वजह से होने वाली मौतें सिमटकर 40,000 रह सकती हैं। कोरोना की दूसरी लहर में अब तक 1.7 लाख लोगों की मौत हो चुकी है।

मृत्यु दर 0.2 फीसद रहने की आशंका- रिपोर्ट के मुताबिक तीसरी लहर में मृत्यु दर 0.2 फीसद रहने की आशंका है जबकि दूसरी लहर में मृत्यु दर एक फीसद रही। तीसरी लहर में गंभीर मरीजों की मृत्यु दर 20 फीसद रह सकती है जबकि दूसरी लहर में 25 फीसद गंभीर मरीजों की मौत हो गई।

बच्चों के संक्रमित होने की आशंका- रिपोर्ट में कहा गया कि देश में 12-18 साल के बच्चों की संख्या 15-17 करोड़ है। तीसरी लहर के दौरान बच्चों के संक्रमित होने की प्रबल आशंका जताई जा रही है। इसे देखते हुए भारत को विकसित देशों की तरह बच्चों के सौ फीसद टीकाकरण के लिए टीके की अग्रिम खरीदारी की रणनीति अपनाने की जरूरत है।

ज्यादा दिन रही दूसरी लहर- रिपोर्ट में कहा गया है कि विकसित देशों में तीसरी लहर की औसत अवधि 98 दिनों की रही जबकि दूसरी लहर की औसत अवधि 108 दिनों की।

रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर के दौरान टियर-तीन और टियर-चार शहरों में कोरोना की पहली लहर के मुकाबले मरने वालों की संख्या अधिक रही। दूसरी लहर में ग्रामीण और अर्धग्रामीण इलाके पहली लहर की तुलना में अधिक प्रभावित हुए।

जीडीपी में कम नुकसान- इस कारण कोरोना की दूसरी लहर के कारण पहली लहर के मुकाबले सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कम नुकसान होगा। कोरोना की पहली लहर में शहरी इलाके अधिक प्रभावित हुए थे जिससे आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से प्रभावित हुई थीं। रिपोर्ट के मुताबिक दूसरी लहर से जीडीपी को होने वाले नुकसान में इस बार गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरल, राजस्थान व उत्तराखंड जैसे राज्यों की हिस्सेदारी अधिक होगी।

चुनाव आयोग ने कहा, ईवीएम और वीवीपैट के बीच का डेटा सौ फीसद है एकदम सटीक

नई दिल्ली । देश में चुनावी प्रक्रिया पर हमेशा ही सवाल खड़े होते रहें हैं। चुनाव जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से कराएं जा रहे हों तो विपक्ष उसमें सवाल खड़ा करता ही है। वहीं, चुनाव आयोग ने एक बार फिर साफ कहा है कि एवीएम और वीवीपैट द्वारा कराए गए चुनावों में गड़बड़ियां नहीं हो सकती हैं। चार राज्यों के हुए विधानसभा चुनाव में इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और वोटर वेरिफाइड पेपर ट्रेल मशीन (वीवीपैट) के बीच का डेटा सौ फीसद एकदम सटीक है।

भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के एक अधिकारी ने कहा कि डेटा ईवीएम और वीवीपैट के बीच 100 प्रतिशत मिलान दिखाता है, जो इसकी सटीकता और प्रामाणिकता साबित करता है। इन पिछले विधानसभा चुनावों में इन दो मशीनों का परिणाम पहले की तरह इसकी वास्तविकता की पुष्टि करता है।

चार राज्यों केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम और एक केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी में इस साल की शुरुआत में चुनाव हुए थे। पश्चिम बंगाल में 1,492 वीवीपैट, तमिलनाडु में 1,183, केरल में 728, असम में 647 और पुडुचेरी में 156 वीवीपैट लगाए गए थे। ।

बता दें कि वीवीपैट से निकलने वाली पर्ची यह बता देती है कि आपका वोट किस उम्मीदवार को गया है। अप्रैल 2019 में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि चुनाव आयोग के लिए 2019 के आम चुनाव में प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में पांच ईवीएम में वीवीपैट पर्चियों की भौतिक गणना करना अनिवार्य है।

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर ईवीएम की गिनती के साथ वीवीपैट पर्चियों को मिलान करने का आग्रह किया था। उसी पर चुनाव आयोग ने कहा कि दोनों की सत्यता सौ फीसद एकदम सटीक है।

मस्तिष्क जैसा कृत्रिम नेटवर्क का विकास, दिमाग के क्रियाओं की नकल करने में है सक्षम

नई दिल्ली । मस्तिष्क हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जो हमारे शरीर को नियंत्रण में रखता है। हाल ही में भारतीय विज्ञानियों ने आर्टिफिशिएल इंटेलीजेंस की मदद से एक ऐसा उपकरण विकसित किया है, जो मानव मस्तिष्क की क्रियाओं की नकल करने में सक्षम है। यह आर्टिफिशिएल इंटेलीजेंस आधारित एक न्यूरोमॉर्फिक उपकरण है, जो मस्तिष्क से कुशल कंप्यूटिंग क्षमता प्राप्त कर मानव मस्तिष्क के ढांचे की नकल कर सकता है।

विज्ञानी लंबे समय से एक ऐसा उपकरण विकसित करने का प्रयास कर रहे थे, जो बाहरी सपोर्टिंग सर्किट की सहायता के बिना जटिल मनोवैज्ञानिक व्यवहारों की नकल करने में सक्षम हो। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च , बेंगलुरु के विज्ञानियों ने एक सरल स्व-निर्माण विधि के माध्यम से जैविक तंत्रिका नेटवर्क जैसा एक आर्टिफिशियल सिनैप्टिक नेटवर्क (एएसएन) बनाने का तरीका खोज निकाला है।

इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने सिल्वर धातु को शाखा युक्त द्वीपों और नैनो कणों को नैनोगैप पृथक्कीकरण के साथ जैव-न्यूरॉन्स और न्यूरोट्रांसमीटर के समान बनाने के लिए तैयार किया है, जहां गोलाकार कणों में फिल्म के टूटने की प्रक्रिया निरंतर होती है। ऐसे आर्किटेक्चर के साथ उच्च किस्म की अनेक बौद्धिक गतिविधियों का अनुकरण किया जाता है। फैब्रिकेटेड आर्टिफिशियल सिनैप्टिक नेटवर्क (एएसएन) में सिल्वर एग्लोमेरेट्स नेटवर्क शामिल हैं, जो अलग-अलग नैनो कणों से भरे नैनोगैप्स द्वारा पृथक किया गया है। उन्होंने पाया कि उच्च तापमान पर सिल्वर फिल्म को गीला करने से जैव-तंत्रिका नेटवर्क से मिलते-जुलते नैनोगैप्स द्वारा अलग किए गए द्वीप संरचनाओं का निर्माण होता है।

प्रोग्राम किए गए विद्युत संकेतों का एक रियल व?र्ल्ड स्टिमुलस के रूप में उपयोग करते हुए इस वर्गीकृत संरचना ने सीखने की विभिन्न गतिविधियों जैसे कि अल्पकालिक स्मृति, दीर्घकालिक स्मृति (एलटीएम), क्षमता, अवसाद, सहयोगी शिक्षा, रुचि-आधारित शिक्षा, पर्यवेक्षण का अनुकरण किया गया। सिनैप्टिक थकान और इसमें होने वाले आत्म-सुधार की भी नकल की गई। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने बताया कि प्रकृति के पास विकास के माध्यम से नए रूपों और कार्यो को करने के लिए असाधारण समय और विविधता है। प्रकृति और जीव विज्ञान से नई प्रक्रियाओं, प्रौद्योगिकियों, सामग्रियों और उपकरणों को सीखना और अनुकरण करना भविष्य की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है, जो मानव निर्मित प्रौद्योगिकियों के साथ जीवन से भरी दुनिया को तेजी से एकीकृत करेंगे।

भारत के खिलाफ दुष्प्रचार में बीबीसी शीर्ष पर, कोरोना पर पश्चिमी मीडिया की असलियत..

नई दिल्ली । इसमें कोई शक नहीं है कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने भारत को बुरी तरह प्रभावित किया है। हालांकि इस दौरान संक्रमित मरीजों और होने वाली मौतों को लेकर पश्चिमी मीडिया ने जिस तरह हाय-तौबा मचाई, उसने उनके भारत विरोधी एजेंडे की पोल खोलकर रख दी। लेखक और पॉलिसी कमेंटेटर शांतनु गुप्ता के मुताबिक बीबीसी, वाशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स अपनी खबरों में भारत और देश के बड़े शहरों में संक्रमित मरीजों और होने वाली मौतों की बड़ी संख्या का बार-बार उल्लेख करते हैं, ताकि बाकी दुनिया को यह बताया जा सके कि भारत महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित है। हालांकि पश्चिमी मीडिया प्रति दस लाख जनसंख्या पर ना तो कोरोना मरीजों की बात करता है और ना ही मृतकों का सही आंकड़ा बताता है, क्योंकि अगर इन आंकड़ों की बात करें तो भारत की स्थिति पश्चिमी देशों के मुकाबले बहुत बेहतर है। कोरोना महामारी को लेकर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार की बात करें तो बीबीसी शीर्ष पर है।

समाचारों में दुर्भावनापूर्ण शीर्षक की बात करें तो बीबीसी शीर्ष पर है। पिछले 14 महीनों के दौरान उसने लोगों को डराने वाले, संदेहास्पद और सुर्खियां बटोरने वाले 176 शीर्षकों का प्रयोग किया। पक्षपातपूर्ण सुर्खियां लगाने में ब्रिटेन का गार्जियन अखबार भी पीछे नहीं रहा है। उसने भारत में कोरोना महामारी को लेकर जो लेख लिखे, उसमें 96 फीसद के शीर्षक भय पैदा करने वाले थे। वहीं, अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स की बात करें तो दोनों के ही 88 फीसद शीर्षक (समाचारों की हेडिंग) दुर्भावनापूर्ण थे। तथ्यात्मक रिपोर्टिंग में रुचि नहीं रखता पश्चिमी मीडिया शांतनु गुप्ता के मुताबिक पश्चिमी मीडिया भारत को लेकर तथ्यात्मक रिपोर्टिंग में बहुत रुचि नहीं रखता है। उसकी कोशिश भारत सरकार के विरुद्ध एक विमर्श स्थापित करने की होती है। यही वजह है कि हमारे देश को लेकर वे लोग जो खबरें प्रकाशित करते हैं, उसमें से सिर्फ 22 फीसद समाचार ही तटस्थ रिपोर्टिंग पर आधारित होते हैं।

550 से ज्यादा लेखों का विश्लेषण पिछले चौदह महीनों के दौरान भारत में कोरोना महामारी को लेकर पश्चिमी मीडिया की भूमिका का पता लगाने के लिए शांतनु गुप्ता ने एक विश्लेषण किया है। उन्होंने ब्रिटिश और अमेरिकी मीडिया से जुड़े शीर्ष समाचार पत्रों और चैनलों द्वारा लिखे और टीवी पर चलाए गए 550 से ज्यादा लेखों का अध्ययन किया, जिसमें चौंकाने वाली बातें सामने आई। खास बात यह रही कि इन समाचारों का एक बड़ा हिस्सा ना सिर्फ लोगों में डर पैदा करता है, बल्कि भ्रामक भी है।

पचास फीसद समाचार अकेले बीबीसी ने प्रसारित किए- शांतनु ने चौदह महीनों की अवधि को दो हिस्सों में बांटा। एक हिस्सा संक्रमण की दूसरी लहर से पहले का था। वहीं दूसरा हिस्सा अप्रैल 2021 से आज तक का है। बीबीसी, द इकोनॉमिस्ट, द गार्जियन, वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयार्क टाइम्स और सीएनएन ने मार्च 2020 से 30 अप्रैल 2021 के बीच 553 समाचार लेख लिखे और दिखाए। अकेले बीबीसी ने 275 समाचार दिखाए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने जहां इस दौरान 91 आर्टिकल लिखे। वहीं, वाशिंगटन पोस्ट ने 69 समाचार और विचार संपादकीय के माध्यम से भारत में कोरोना महामारी को वीभत्स रूप में दिखाया।

केरल में दस्तक देते ही आगे बढ़ा मानसून, जानें- यूपी-बिहार सहित अन्य राज्यों में कब पहुंचेगा

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आइएमडी) ने बताया कि दो दिन की देरी के बाद दक्षिण-पश्चिम मानसून ने गुरुवार को केरल में दस्तक देकर देश में चार महीने के बारिश के मौसम की शुरुआत कर दी है। आइएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा, दक्षिण-पश्चिम मानसून केरल के दक्षिणी हिस्सों में पहुंच गया है। केरल में मानसून की शुरुआत सामान्यतः एक जून को होती है। मौसम विभाग ने कहा कि मानसून अगले दो दिनों में दक्षिण अरब सागर और मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों, केरल के शेष हिस्सों, लक्षद्वीप, तमिलनाडु के कुछ भागों, पुडुचेरी, तटीय एवं कर्नाटक के अंदरूनी दक्षिणी हिस्सों, रायलसीमा और दक्षिण एवं मध्य बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ेगा।

पिछले छह वर्षों में यह तीसरी बार है जब मानसून देर से आया है। 2016 और 2019 में मानसून ने केरल में आठ जून को दस्तक दी थी। मौसम विभाग ने इससे पहले केरल में 31 मई के आस-पास मानसून के दस्तक देने का अनुमान जताया था।

निजी मौसम पूर्वानुमान केंद्र, स्काईमेट ने कहा कि दक्षिण-पश्चिम मानसून ने केरल में 30 मई को दस्तक दी थी। हालांकि, आइएमडी ने कहा कि मानसून की शुरुआत की घोषणा करने के लिए स्थितियां पूर्ण नहीं थीं। मौसम विभाग ने दक्षिण-पश्चिम मानसून 2021 के लिए अपने दूसरे पूर्वानुमान में कहा कि यह उत्तर और दक्षिण भारत में सामान्य रह सकता है। मध्य भारत में इसके सामान्य से ऊपर और पूर्व एवं पूर्वोत्तर भारत में सामान्य से नीचे रहने का अनुमान है।

आज इन इलाकों में आगे बढ़ा मानसून- मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिण अरब सागर के कुछ हिस्सों, लक्षद्वीप क्षेत्र, दक्षिण केरल, दक्षिण तमिलनाडु, कोमोरिन के शेष हिस्सों-मालदीव क्षेत्र और दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों में आज आगे बढ़ गया है। आईएमडी के डीजीएम डॉ एम महापात्र ने बताया की सेकेंड स्टेज में दक्षिण पश्चिम मॉनसून सीजन

(जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर) 2021 के दौरान देश भर में सामान्य, सामान्य से कम और सामान्य से अधिक वर्षा की संभावना है।

अगले दो दिन में जानें कहां-कहां देगा दस्तक- मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिण और मध्य अरब सागर के शेष हिस्सों, केरल और लक्षद्वीप के शेष हिस्सों, तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ हिस्सों, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों, रायलसीमा और दक्षिण और मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है।

जून के मध्य तक आधा देश होगा कवर- केरल में आमतौर पर दक्षिण पश्चिम मॉनसून 1 जून तक पहुंचता है। पिछले साल के आधार पर यह दस्तक देने के एक दिन बाद ही यह तेजी से पूर्वोत्तर भारत को कवर कर लेता है। जून के मध्य तक जैसे-जैसे दक्षिण-पश्चिम मानसून आगे बढ़ेगा यह पूरे महाराष्ट्र, दक्षिण गुजरात, मध्य और दक्षिण मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से और दक्षिण ओडिशा बारिश में को कवर कर लेगा। इसके साथ ही उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल में भी मॉनसून की बारिश होगी। जुलाई के मध्य तक यह पूरे देश में पहुंच जाता है।

बिहार-यूपी-दिल्ली में कब पहुंचेगा मानसून- बता दें कि बिहार में किशनगंज और पूर्णिया के इलाके से होते हुए यह 12 जून के आसपास प्रवेश करता है। वहीं उत्तर प्रदेश में मॉनसून जून के तीसरे हफ्ते में दाखिल होता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां पर मॉनसून 25 जून के आसपास आता है, लेकिन इस बार देरी हो सकती है और जून अंत या जुलाई के शुरुआत में मॉनसून पहुंच जाएगा।

इस बार कहां- कितनी बारिश होगी मौसम विभाग के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि स्टैस्टिकल एन्सेंबल्ड फॉरकास्टिंग सिस्टम में मानसून के चार महीनों के दौरान औसत के 96 से 104 फीसद बारिश यानी सामान्य मानसून होने की 40 फीसद संभावना पाई गई। सामान्य से अधिक की 22 फीसद और सामान्य से कम होने की 18 फीसद संभावना है। इसी मॉडल के आधार पर उत्तर पश्चिम भारत (कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश) में मानसून के सामान्य (92-108 फीसद), मध्य भारत (मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा, गुजरात) में सामान्य से अधिक (106 फीसद), दक्षिणी पठार (केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी) में सामान्य (93 से 107 फीसद) बारिश होगी। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वोत्तर (पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, प. बंगाल, असम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम) और मानसून कोर जोन (मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तरी कर्नाटक, झारखंड) में 106 फीसद बारिश होने की संभावना बन रही है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मानसून अहम- अच्छा मानसून भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अहम है जो अब भी बहुत हद तक कृषि एवं संबंधित गतिविधियों पर आधारित है। मौसम विभाग ने कहा कि देश के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से लेकर सामान्य से अधिक बारिश होने का अनुमान है।

इन इलाकों में कम बारिश का अनुमान- आइएमडी ने कहा कि पूर्व और पूर्वोत्तर भारत जैसे बिहार के पूर्वी हिस्सों, बंगाल के कुछ हिस्सों, असम, मेघालय, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, दक्षिण पश्चिम प्रायद्वीपीय भारत, केरल के कुछ हिस्से, तटीय कर्नाटक और महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु के कुछ अंदरूनी इलाकों में सामान्य से कम बारिश का अनुमान है।

बेस्ट फ्रेंड निशा रावल के सपोर्ट में आईं कश्मीरा शाह

'ये रिश्ता क्या कहलाता है' फेम एक्टर करण मेहरा और उनकी पत्नी निशा रावल के रिश्ते में दरार आ गई है। निशा रावल ने करण मेहरा पर मारपीट का मुकदमा दर्ज किया, जिसके बाद उन्हें जेल भी जाना पड़ा। हालांकि कुछ समय बाद ही करण को जमानत मिल गई। करण मेहरा और निशा रावल का विवाद तूल पकड़ जा रहा है। दोनों ने अपनी-अपनी सफाई भी दी है। जहां करण मेहरा ने दावा किया की निशा की दीमागी हालत ठीक नहीं है और वह बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार हैं। वहीं निशा ने पति करण मेहरा पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाया है। वहीं अब एक्ट्रेस कश्मीरा शाह ने करण और निशा के बीच चल रहे विवाद पर अपना रिएक्शन दिया है। कश्मीरा शाह ने अपनी दोस्त निशा का साथ दिया है। एक इंटरव्यू के दौरान कश्मीरा ने कहा,मैं निशा की तरफ हूं क्योंकि वाकई में करण ने निशा को मारा है। कश्मीरा ने कहा, पैसे को लेकर उनके रिश्ते में काफी कुछ उलझा हुआ है और पहले भी करण उनके साथ मारपीट कर चुके हैं। जब मैं निशा के घर गई तब मुझे इस बारे में पता चला। निशा इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोल रही थी क्योंकि ये बहुत पर्सनल मामला था। हमें पता था कि दोनों के बीच परेशानियां चल रही हैं मगर ये नहीं पता था कि परेशानियां किस हद तक हैं। मैं उनकी बेस्ट फ्रेंड होने के नाते उनके साथ हूं। वहीं करण मेहरा की सफाई पर कश्मीरा ने कहा, करण जो कुछ भी कह रहे हैं सिर्फ अपने बचाव में कह रहे हैं। उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि निशा ऐसा कुछ करे। लॉकडाउन चल रहा है। जरा सोचिए कि अगर निशा को ज्यादा चोट लग जाती तो उसका उपचार कैसे होता। कश्मीरा ने कहा, करण मेहरा को समझना चाहिए कि वह एक मां है, जो बच्चे का ख्याल रखती है। जितना मुझे पता चला है, करण की वजह से घर की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। इस कारण भी दोनों के रिश्ते में दरार आ गई। हालांकि मुझे लगता है कि परेशानी चाहें कोई भी हो लेकिन आप हाथ नहीं उठा सकते हैं। बता दें कि, करण मेहरा के खिलाफ निशा ने घरेलू हिंसा का केस दर्ज करवाया था। शिकायत के बाद करण को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। हालांकि, पूछताछ के बाद करण को उसी दिन जमानत पर रिहा भी कर दिया गया था।

माता-पिता को सताई जैकलीन फर्नांडिस की चिंता

कोरोना काल में कई बॉलीवुड सेलेब्स मदद के लिए आगे आए हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस भी लोगों की हरसंभव मदद कर रही हैं। लॉकडाउन का आदेश आने से पहले जैकलीन एक खूबसूरत जिंदगी जी रही थीं। वह एक सेट से दूसरे सेट का रुख करते हुए अपने शूटिंग शेड्यूल को पूरा करने में व्यस्त थीं। बीते साल, परिवार के साथ दिवाली और क्रिसमस सेलिब्रेट न करने के बाद, अब जैकलीन ने ऐसी इच्छा जाहिर की है जो उनके माता-पिता उनसे चाहते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान जैकलीन ने कहा, मेरे माता-पिता मेरे लिए चिंतित हैं और चाहते है कि मैं उनके साथ बहरीन में रहूं। मुझे लगता है कि 2020 में, वायरस के प्रकोप ने सभी को झकझोर दिया है। इस बार, जबकि हम दूसरी लहर के लिए तैयार नहीं थे, तब लोग बड़ी संख्या में संकट में पड़े लोगों की सक्रिय रूप से मदद करने के लिए सामने आ रहे है। जैकलीन आगे कहती हैं, श्रीलंका से मेरे मित्र और मेरे माता-पिता, जो बहरीन में रहते हैं, समाचार देखते हैं और जब वे भारत की स्थिति देखते हैं तो घबरा जाते हैं। मेरे माता-पिता चाहते हैं कि मैं उनके साथ बहरीन में रहूं... यहां तक कि श्रीलंका से मेरे चाचा और चचेरे भाई मुझसे वहां आने और उनके साथ रहने के लिए कह रहे हैं। हालांकि, मैं यहां रहने और अपने काम को जारी रखने के लिए काफी इच्छुक हूं। जैकलीन इन दिनों काफी सोशल वर्क कर रही हैं। उन्होंने YOLO नामक अपनी खुद की फाउंडेशन शुरू की है, जहां विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है और एक महीने में 1 लाख भोजन उपलब्ध करवाने, स्ट्रीट एनिमल्स को खाना खिलाने और लोगों को मास्क और सैनिटाइज़र दान करने का लक्ष्य रखा है। एक बार जब महामारी खत्म हो जाएगी तो यह फाउंडेशन अन्य मुद्दों से भी निपटने में मदद करेगा। इसके साथ ही जैकलीन खुद को फिट रखने में भी व्यस्त हैं, वह योगा प्रैक्टिस करती हैं और अपने प्रशंसकों के लिए नियमित पोस्ट करती रहती हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो जैकलीन के पास किक 2, भूत पुलिस, बच्चन पांडे और राम सेतु जैसे प्रोजेक्ट्स हैं।

'गबरू' की शूटिंग थी एक रोड ट्रिप

प्रणति राय प्रकाश को कमाल खान के पंजाबी ट्रैक 'गबरू' के यूजिक वीडियो की शूटिंग के लिए पसंद करने के कारणों में से एक यह है कि इसके लिए उन्हें एक मिनी रोड ट्रिप पर जाना पड़ा। वह याद करती हैं, ''मैंने शूटिंग के लिए गुड़गांव से चंडीगढ़ की यात्रा की। यह एक रोड ट्रिप था। मुझे रोड ट्रिप बहुत पसंद हैं। हम स्वादिष्ट दाल मखनी और आलू परांठे के लिए ढाबों पर रुके थे। हर कोई मेरे लिए नया था लेकिन मैंने दोस्तों की तरह महसूस किया, इसलिए इसकी शूटिंग मजेदार थी।
''अभिनेत्री का कहना है कि वीडियो उनके पहले किए गए काम से बहुत अलग था। फिल्म से अपनी शुरूआत करने वाली प्रणति कहती हैं, ''मुझे लगता है कि मेरे हर प्रोजेक्ट का एक अलग सार है। गबरू में एक प्यारा सा मजा है और मुझे 'पंजाब के खेत में चल रहे सलवार कुर्ते में' सीक्वेंस बहुत पसंद आया। 2019 में 'फैमिली ऑफ ठाकुरगंज' और अर्जुन रामपाल के साथ 'पेंटहाउस' में और साथ ही वेब श्रृंखला 'कार्टेल' में देखा जाएगा।' 'गबरू' के बारे में, वह आगे कहती हैं, ''यह एक सीक्वेंस है कि कैसे एक लड़का एक लड़की के प्यार में पड़ जाता है और चुपके से उसकी प्रशंसा करता है और आखिर वे प्यार में पड़ जाते हैं। कहानी एक क्लब से पंजाब के खेतों तक जाती है। मुझे अपने दोनों लुक पसंद आए। - पश्चिमी और देसी। मुझे इसकी शूटिंग में बहुत मजा आया।''

विद्या बालन की 'शेरनी' का ट्रेलर आया सामने

बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन अपनी फिल्म 'शेरनी' को लेकर चर्चा में बनी हुई है। इस फिल्म में विद्या एक फॉरेस्ट ऑफिसर का किरदार निभाती नजर आएंगी। बीते दिनों इस फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था। अब अमेजन प्राइम वीडियो ने विद्या बालन स्टारर बहुप्रतीक्षित फिल्म 'शेरनी' का ट्रेलर जारी कर दिया है। फिल्म में विद्या बालन एक ईमानदार महिला फॉरेस्ट ऑफीसर- विद्या के किरदार में मुख्य भूमिका निभाती नजर आएंगी, जो पितृसत्तात्मक समाज द्वारा सामाजिक अवरोधों का अड़ंगा लगाने के लिए छुट्टा छोड़े गए क्रूर पशुओं तथा अपने ही विभाग में व्याप्त ढुलमुल रवैये पर शिकंजा कसती है। इस रोमांचक ट्रेलर में विद्या की अद्भुत यात्रा को दिखाया गया है, जो विचित्र किंतु खुद से जोड़ कर देखे जा सकने वाले किरदारों से भरी दुनिया में संपन्न होती है। मनुष्यों और पशुओं के बीच के संघर्ष को सुलझाने की कोशिश करते हुए इस यात्रा में विद्या को अपनी असामान्य ड्यूटी तथा वैवाहिक जीवन के बीच बार-बार आवाजाही करनी पड़ती है। टी-सीरीज एवं एबंडेंशिया एंटरटेनमेंट द्वारा प्रोड्यूज की गई इस मस्ट-वाच ड्रामा फिल्म के कर्ताधर्ता न्यूटन-फेम डाइरेक्टर अमित मासुरकर हैं, जो उनके ट्रेडमार्क व्यंग्य से सजी हुई है। फिल्म में शरद सक्सेना, मुकुल चड्ढा, विजय राज, इला अरुण, बृजेंद्र काला और नीरज काबी जैसे कलाकारों का जोरदार मिश्रण भी मौजूद है। ट्रेलर के लॉन्च होने पर विद्या बालन ने कहा, जब मैंने पहली बार शेरनी की कहानी सुनी थी, तभी से मुझे दुनिया बेहद लुभावनी और दिलचस्प लगने लगी। मैं अपनी सुध-बुध ही भूल गई! इसके साथ-साथ मैं जिस विद्या का किरदार निभा रही हूं, वह बहुत कम बोलने वाली किंतु एक बहु-आयामी महिला है। फिल्म एक संवेदनशील विषय को उठाती है जो न केवल मनुष्यों और पशुओं के बीच, बल्कि इंसान और इंसान के बीच भी सम्मान, आपसी समझ और सह-अस्तित्व पर आधारित है। इस बेमिसाल किरदार और अद्भुत कहानी को अमेज़न प्राइम वीडियो के माध्यम से ग्लोबल ऑडियंस के सामने पेश करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है और उम्मीद करती हूं कि दुनिया भर के दर्शक इस फिल्म के साथ अप्रत्याशित ढंग से जुड़ेंगे। फिल्म में विद्या बालन के अलावा शरद सक्सेना, मुकुल चड्ढा, विजय राज, इला अरुण, नीरज काबी और ब्रिजेंद्र काला जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म 'शेरनी' का निर्देशन अमित मासुरकर ने किया है। यह फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर 18 जून 2021 को रिलीज होगी।

महामारी के दौरान एक शार्ट फिल्म की शूटिंग करना आसान

हाल ही में शार्ट फिल्म 'ब्लाइंड लव' में नजर आईं अभिनेत्री अलीशा पंवर का कहना है कि वह इस प्रारूप में और फिल्मों का हिस्सा बनना चाहेंगी क्योंकि इनकी शूटिंग में ज्यादा समय नहीं लगता है। उन्होंने को बताया ''मैंने टीवी शो, विज्ञापन और संगीत वीडियो किए हैं, लेकिन यह मेरी पहली शार्ट फिल्म थी और मुझे यह बहुत पसंद आई। मुझे लगता है कि महामारी के दौरान टीवी शो की शूटिंग की तुलना में एक शार्ट फिल्म की शूटिंग करना आसान है क्योंकि शूटिंग दो से तीन दिन में समाप्त हो जाती है। और आप इन दिनों में अधिकतम एहतियात बरत सकते हैं।'' अभिनेत्री का कहना है कि वह फिल्म की शूटिंग के दौरान बहुत सहज थीं, क्योंकि सेट पर सभी सावधानियां बरती जाती थीं।

'कुमकुम भाग्य' एक्ट्रेस लीना जुमानी ने तोड़ी सगाई

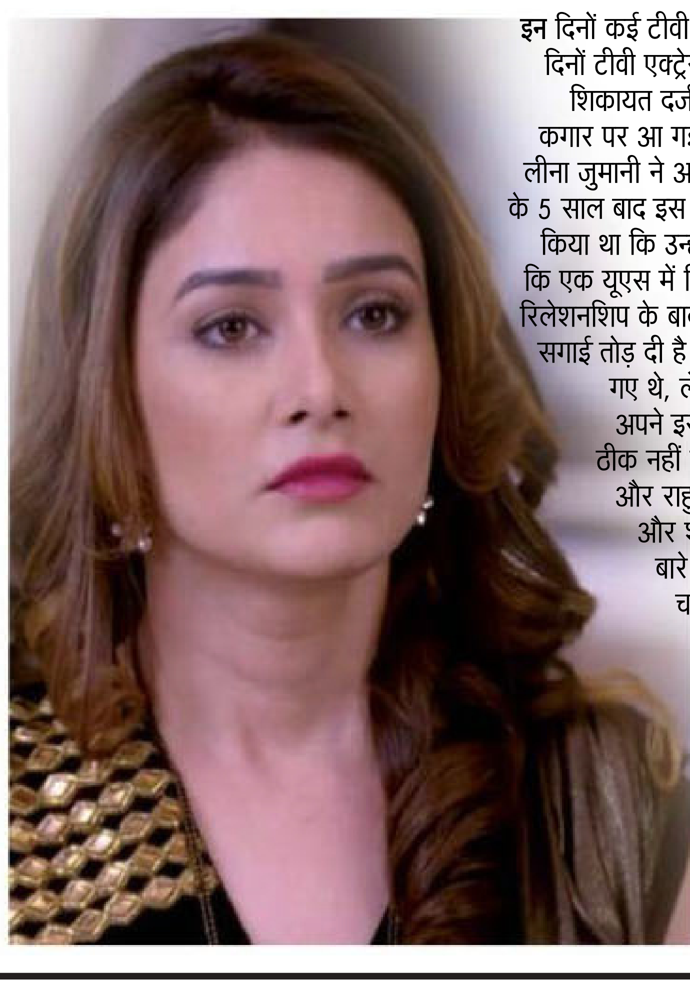

इन दिनों कई टीवी सेलेब्स की पर्सनल लाइफ में भूचाल आया हुआ है। बीते दिनों टीवी एक्ट्रेस निशा रावल ने अपने पति करण मेहरा पर मारपीट की शिकायत दर्ज करवाई है। टीवी के इस क्यूट कपल की शादी टूटने के कगार पर आ गई है। अब खबर आ रही की 'कुमकुम भाग्य' की एक्ट्रेस लीना जुमानी ने अपनी सगाई तोड़ दी है। खबरों के अनुसार लीना ने सगाई के 5 साल बाद इस रिश्ते को तोड़ दिया है। साल 2015 में लीना ने अनाउंस किया था कि उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड राहुल सचदेव से सगाई कर ली है जो कि एक यूएस में बिजनेसमैन हैं। लीना ने बताया था कि दोनों ने 3 साल के रिलेशनशिप के बाद साल 2014 में सगाई कर ली थी। अब लीना ने अपनी सगाई तोड़ दी है। खबरों के अनुसार दोनों वैसे 1 साल पहले ही अलग हो गए थे, लेकिन अब फाइनली एक्ट्रेस ने सगाई तोड़ दी है। लीना ने अपने इस फैसले की वजह बताते हुए कहा कि दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा था। एक इंटरव्यू के दौरान लीना ने कहा, हां, मैं और राहुल अब साथ नहीं हैं। साल 2014 में हमने सगाई की थी और शादी करना चाहते थे, लेकिन चीजें ठीक नहीं हुईं। मैं इस बारे में नहीं बताना चाहती कि हमारे बीच क्या गलत हुआ। मैं चाहती हूं कि वह जहां भी रहें खुश रहें। लीना ने कहा, मेरे पैरेंट्स चाहते हैं कि मैं सैटल हो जाऊं, लेकिन मैं अभी अपना सिंगल स्पेस एंजॉय कर रही हूं। हम सभी अभी महामारी से परेशान हैं और अगर कोविड नहीं होता तो मैं जल्दी अपने लिए किसी को देखती। बता दें कि लीना को एकता कपूर के शो 'कुमकुम भाग्य' से जबरदस्त पहचान मिली। इस शो में उन्होंने वैम्प का किरदार निभाया। लीना हाल ही में वेब सीरीज पारो में नजर आई थीं। यह सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म उल्लू पर रिलीज हुई थी।

इंग्लैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड मजबूत:कॉनवे का पहला टेस्ट शतक, डेब्यू मैच में लॉर्ड्स में सबसे ज्यादा रन बनाने का गांगुली का रिकॉर्ड भी तोड़ा रन बना कर क्रीज पर हैं

लॉर्ड्स। लॉर्ड्स में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच बुधवार से खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे 136 रन बनाकर क्रीज पर टिके हुए हैं। दिन की समाप्ति तक न्यूजीलैंड का स्कोर 3 विकेट के नुकसान के बाद 246 रन है। वहीं डेवोन कॉनवे ने डेब्यू मैच में लॉर्ड्स पर सबसे ज्यादा रन बनाने के सौरव गांगुली के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। कॉनवे का डेब्यू मैच है। वे लॉर्ड्स पर डेब्यू मैच में शतक बनाने वाले दुनिया के छठे क्रिकेटर हैं। वहीं वे तीसरे गैर ब्रिटिश खिलाड़ी भी हैं, जिन्होंने लॉर्ड्स पर शतक जमाया है। उन्होंने डेब्यू मैच में लॉर्ड्स पर सबसे ज्यादा रन बनाने के सौरव गांगुली के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। गांगुली ने 1996 में लॉर्ड्स में अपने डेब्यू मैच में 131 रन बनाए थे। कॉनवे 136 रन बनाकर क्रीज पर टिके हुए हैं। अभी चार दिनों का खेल बाकी है। गांगुली से पहले लॉर्ड्स में डेब्यू मैच में शतक बनाने वाले गैर ब्रिटिश खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के हैरी ग्राहम थे। उन्होंने 1893 में इंग्लैंड के खिलाफ 107 रन बनाए थे।

सौरव गांगुली और कॉनवे का जन्म एक ही दिन

सौरव गांगुली और कॉनवे का जन्मदिन एक ही दिन है। दोनों का जन्मदिन 8 जुलाई है। गांगुली का जन्म 8 जुलाई 1972 को कोलकाता में हुआ था। जबकि डेवोन कॉनवे का जन्म साउथ अफ्रीका की राजधानी जोहान्सबर्ग में साल 1991 में हुआ था।

कॉनवे और हेनरी निकोल्स क्रीज पर

न्यूजीलैंड ने पहले टेस्ट में पहले दिन की समाप्ति तक तीन विकेट के नुकसान पर 246 रन बना लिए हैं। कॉनवे और हेनरी निकोल्स क्रीज पर हैं। न्यूजीलैंड का पहला विकेट 58 रन पर गिरा। ओपनर टॉम लाथम 57 गेंदों पर 23 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं केन विलियम्सन भी 31 गेदों पर 13 रन बनाकर आउट हो गए। जबकि रोस टेलर ने 38 गेंदों पर 14 रन बनाए। कॉनवे 240 गेंदों पर 136 रन और निकोल्स 149 गेंदों पर 46 रन बना कर क्रीज पर हैं।

भारत का इंग्लैंड दौरा:भारतीय पुरुष और महिला टीम चार्टर्ड फ्लाइट से इंग्लैंड के लिए रवाना

मुंबई। भारतीय पुरुष टीम और महिला टीम गुरुवार सुबह को चार्टर्ड फ्लाइट से इंग्लैंड के लिए रवाना होगी। विराट कोहली की कप्तानी वाली टीम को 18 से 22 जून के बीच साउथैम्पटन में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना है। उसके बाद पुरुष टीम को अगस्त-सितंबर में इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज भी खेलना है। भारतीय पुरुष टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के बाद इंग्लैंड में ही रूक कर सीरीज की तैयारी करेगी। वहीं महिला टीम को इंग्लैंड के खिलाफ 16 जून से एकमात्र टेस्ट और 3-3 मैचों की वनडे और टी-20 सीरीज खेलनी है। खिलाड़ियों को अपने साथ परिवार ले जाने की भी इजाजत BCCI ने दी है।

महिला और पुरुष क्रिकेट टीम अलग-अलग स्थानों पर रुकेंगी

दोनों टीमें 19 मई से मुंबई के एक होटल में सख्त क्वारैंटाइन के नियमों का पालन कर रही थीं, जो कि मंगलवार को खत्म हो गया। गुरुवार को दोनों टीमें लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर उतरेंगी। इसके बाद विराट की टीम साउथैंप्टन और मिताली की टीम ब्रिस्टल के लिए रवाना हो जाएगी।

मेन्स टीम लंदन से साउथैंप्टन बस से 3 घंटे के सफर के बाद पहुंचेगी। वहां टीम अगले 10 दिन तक क्वारैंटाइन रहेगी। ICC के मुताबिक, पहले 3 दिन यानी 5 जून तक खिलाड़ियों की 3 बार कोरोना जांच भी की जाएगी। हर निगेटिव रिपोर्ट के बाद उन्हें आइसोलेशन में ही एक्सरसाइज करने की इजाजत होगी। पहले 3 दिन तक किसी भी खिलाड़ी को उनके होटल रूम से नहीं निकलने दिया जाएगा। 6 जून से टीम के खिलाड़ी छोटे-छोटे ग्रुप में मैदान में ट्रेनिंग कर सकेंगे। हालांकि, उन्हें सिर्फ होटल से मैदान और मैदान से होटल जाने की ही इजाजत होगी। होटल में भी वे कमरे से सिर्फ वर्क आउट के लिए निकल सकेंगे। 10 दिन का क्वारैंटाइन 12 जून को समाप्त हो जाएगा।

फ्रेंच ओपन 2021 : पुरुष डबल्स के दो खिलाड़ी कोरोना संक्रमित; मैच के बीच में ही दर्शकों को बाहर किया गया

नई दिल्ली। फ्रेंच ओपन 2021 में भाग लेने वाले पुरुष डबल्स के दो खिलाड़ी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इन दोनों खिलाड़ियों को ड्रॉ से बाहर कर दिया गया है। वहीं मैच के बीच में ही दर्शकों को बाहर कर दिया गया। दरअसल फ्रेंच ओपन में दर्शकों को एंट्री दी गई थी, लेकिन फ्रांस सरकार ने देर रात कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए कर्फ्यू लगाने की घोषणा की। जिसके बाद दर्शकों को बाहर निकाल दिया गया।

अब तक 2,446 कोरोना टेस्ट कराए गए हैं

फ्रेंच टेनिस फेडरेशन की ओर से कहा गया है कि क्वॉलिफायर्स शुरू होने के बाद से अब तक 2,446 टेस्ट कराए जा चुके हैं। वहीं डबल्स के दो खिलाड़ी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। दोनों खिलाड़ी ही एक ही टीम के हैं। उन्हें ड्रॉ से बाहर कर दिया गया है। हालांकि FFT की ओर से खिलाड़ियों के नाम नहीं बताए गए। वहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक निकोला मेटकिक और मेट पाविक कोरोना संक्रमित हैं। वहीं डबल्स जोड़ी जैम मुनार और फेलिसियानो लोपेज़ ने भी नाम वापस ले लिया है। वर्ल्ड नंबर-2 महिला टेनिस खिलाड़ी नाआमी ओसाका ने पहले मैच के बाद फ्रेंच ओपन से हटने का फैसला लिया है। उन पर रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं होने पर करीब 10 लाख रुपए (15 हजार रु डॉलर) का जुर्माना लगाया गया था।

टोक्यो ओलंपिक: उलझन में फुआद मिर्जा जापान में प्रिय घोड़े पर लगाएं दांव या नए पर

नई दिल्ली। ओलंपिक का कुछ दिन पहले ही टिकट हासिल करने वाले घुड़सवार फुआद मिर्जा अब तक यह तय नहीं कर पाए हैं कि टोक्यो में वह किस घोड़े पर दांव लगाएंगे। उन्होंने 2019 में चोटिल हुए अपने प्रिय घोड़े सिग्न्यूर मेडिकॉट और दूसरे दयारा दोनों के साथ क्वालिफाई किया है। लेकिन मेडिकॉट ही था जिस पर सवार होकर उन्होंने जकार्ता एशियाई खेलों में रजत समेत दो पदक हासिल किए।

एक जुलाई तक भेजनी है एंट्री, किस घोड़े के साथ उतरेंगे ओलंपिक में

फुआद कहते हैं कि माह के अंतिम सप्ताह में फैसला लेंगे कि टोक्यो में वह मेडिकॉट के साथ उतरेंगे या फिर दयारा के साथ। अगर पिछले वर्ष ओलंपिक होते तो यह तय था कि फुआद मेडिकॉट के साथ नहीं उतर सकते थे। उसके चोटिल होने से

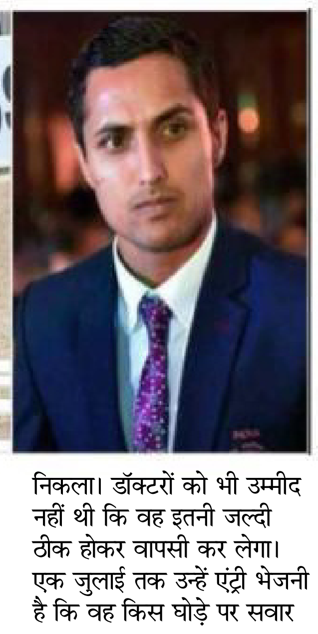

वह काफी निराश थे। उनका इसके साथ समन्वय और लगाव शानदार है। मेडिकॉट की गैरमौजूदगी में उन्होंने दयारा को अपनाया।

फुआद के मुताबिक मेडिकॉट वाकई में योद्धा निकला। डॉक्टरों को भी उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी ठीक होकर वापसी कर लेगा। एक जुलाई तक उन्हें एंट्री भेजनी है कि वह किस घोड़े पर सवार होंगे। यह कठिन फैसला होगा। घोड़े को भी टोक्यो में सात दिन के एकांतवास में भेजना होगा।

खुद करते हैं घोड़ों की मालिशः फुआद अभी जर्मनी में ओलंपिक की तैयारियां कर रहे हैं। वह वहीं से सीधे टोक्यो जाएंगे। वह कहते हैं कि उनका पूरा दिन घोड़ों के साथ बीतता है। वह सुबह सात बजे अस्तबल पहुंच जाते हैं और शाम छह बजे तक वहीं रहते हैं। अस्तबल में वह घोड़ों को खुद खाना खिलाते हैं। उनके साथ काम करते हैं। उनके पैरों पर बर्फ मलते हैं। घुड़सवारी खर्चीला खेल है। वह खुशनसीब हैं कि उनके पास एंब्रेसिया के रूप में प्रायोजक है। लेकिन पिछले दो वर्षों की तैयारियों को ध्यान में रखें तो दो करोड़ रुपये से अधिक का खर्च आ चुका है।

बैडमिंटन: सिंधु ने की मारिन के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना, कहा- टोक्यो ओलंपिक में उसकी कमी खलेगी

नई दिल्ली। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने स्पेन की कैरोलिना मारिन के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए कहा कि ओलंपिक खेलों में गत चैंपियन की कमी खलेगी। मारिन को घुटने की चोट के कारण ओलंपिक से नाम वापिस लेना पड़ा है। टोक्यो ओलंपिक में पदक की सबसे प्रबल दावेदार मारिन को अभ्यास के दौरान घुटने में चोट लगी और उन्होंने मंगलवार को खेलों से नाम वापिस ले लिया। रियो ओलंपिक फाइनल में मारिन से हारी सिंधु ने ट्विटर पर एक वीडियो संदेश में कहा, 'आपकी चोट के बारे में सुनकर दुख हुआ। उम्मीद है कि आप जल्दी स्वस्थ होकर मजबूती से वापसी करोगी।' सिंधु ने कहा, 'मुझे पिछले ओलंपिक याद है जब हम फाइनल खेले थे। तुम्हारे खिलाफ खेलना अच्छा लगा और इस बार कोर्ट पर तुम्हारी कमी खलेगी।'

कोरोना का असर: सैर-सपाटे पर ओलंपिक नहीं जा सकेंगे संघ पदाधिकारी

नई दिल्ली। पिछले खेल आयोजनों की तरह इस बार ओलंपिक में खेल संघों के पदाधिकारी सैर-सपाटे पर नहीं जा पाएंगे। आयोजन समिति की गुजारिश के बाद भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) ने खेल संघों के पदाधिकारियों के टोक्यो में प्रवेश को सीमित कर दिया है। आईओए ने साफ कर दिया है कि इस बार कोरोना के चलते पनपी विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सिर्फ एक प्रतिनिधि को ही जाने की इजाजत होगी। लंदन व रियो ओलंपिक और जकार्ता एशियाई

खेलों की तरह इस बार खेल संघों, आईओए और खेल मंत्रालय के पदाधिकारियों और अधिकारियों की भीड़ टोक्यो में नहीं दिखाई देगी। आयोजन समिति ने आईओए को साफ किया है कि ओलंपिक के दौरान जरूरी और संचालन करने वाले स्टाफ को प्रवेश की अनुमति होगी। जो भी व्यक्ति टोक्यो जाएगा उसे चार सप्ताह पहले अपनी गतिविधियों की जानकारी देनी होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के प्रयोग की भी अनुमति नहीं होगी। शॉपिंग पर पाबंदी और रेस्टोरेंट में प्रवेश निषेध होगा। कोरोना संक्रमित पाए जाने की स्थिति में अपने खर्च पर 14 दिन के एकांतवास में रहना होगा। साथ ही आयोजकों की ओर से तय होटल में रहने की अनुमति होगी। अब तक 12 खेल संघों के खिलाड़ी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। बैडमिंटन, वेटलिफ्टिंग और जूडो के अलावा कुछ अन्य खेलों के खिलाड़ियों के क्वालिफिकेशन की घोषणा होनी बाकी है।

ओलंपिक में खेल मंत्रालय का दल भी काफी छोटा होगा। अब तक खेल मंत्री किरेन रिजिजू के जाने की योजना है। वैसे खेलों में खेल मंत्री अपनी पत्नी को भी ले जाते हैं, लेकिन सूत्र बताते हैं कि खेल मंत्री टोक्यो अकेले जा रहे हैं। अब तक खेल सचिव के जाने का भी कोई कार्यक्रम नहीं है।

फ्रेंच ओपन: नडाल की रोलां गैरां में 101वीं जीत, लगातार 17वीं बार दूसरे दौर में पहुंचे राफेल

नई दिल्ली। रिकॉर्ड 14वें फ्रेंच ओपन के लिए खेल रहे स्पेनिश स्टार राफेल नडाल ने जीत के साथ आगाज किया। दुनिया के तीसरे नंबर के खिलाड़ी नडाल ने ऑस्ट्रेलिया के 21 वर्षीय एलेक्सी पोपीरिन को 6-3, 6-2, 7-6 से हराकर लगातार 17वीं बार रोलां गैरां के दूसरे दौर में प्रवेश किया। नडाल ने पेरिस की लाल बजरी पर लगातार 31वीं जबकि कुल 101वीं जीत दर्ज की।

वह 2015 के बाद से यहां हारे नहीं हैं तब क्वार्टर फाइनल में नोवाक जोकोविच ने मात दी थी। हालांकि अगले साल तीसरे दौर में चोट के चलते वह हट गए थे यही नहीं 2016 के बाद सिर्फ तीन खिलाड़ी (डिएगो, डेविन गॉफिन, डोमिनिक थिएम) ही यहां उनसे कोई सेट जीत पाए हैं। अब बृहस्पतिवार को नडाल का सामना रिचर्ड गास्केट से होगा, जिन्होंने हुगो गैस्टन को 6-1, 6-4, 6-2 से हराया। उसी दिन नडाल अपना 35वां जन्मदिन भी मनाएंगे तो वह इसका जश्न जीत से मनाना चाहेंगे। नडाल अगर खिताब जीत जाते हैं तो यह उनकी 21वीं ट्रॉफी होगी और वह सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले खिलाड़ी बन

जाएंगे। अभी उनके और रोजर फेडरर के नाम 20-20 खिताब हैं।

असलान और यामेर भी आगे बढ़े

पहली बार रोलां गैरां और दूसरी बार किसी ग्रैंड स्लैम में खेल रहे रूस के असलान करात्सेव ने जेनसन ब्रूकसबे को 6-3, 6-4, 6-4 से, यामेर ने रॉबर्टो कारबलेस को 6-4, 0-6, 4-6, 6-2,6-2 से, मैटियो बेरेटिनी ने टारो डेनियल को 6-0,6-4, 4-6, 6-4 से, डिएगो ने लू येन को 6-2, 6-2, 6-3 से, फिलिप ने फर्नांडो वर्दास्को को 7-6, 6-2, 2-6, 6-4 से, आंद्रेस सेप्पी ने फेलिस को 6-3, 7-6, 4-6, 6-4 से, जॉन लेनार्ड स्ट्रप ने आंद्रे रूबलेव को 6-3,7-6, 4-6, 3-6, 6-4 से, गेल मोनफिल्स ने अल्बर्ट रमोस को 1-6, 7-6, 6-4, 6-4 से, अल्जाज बेडेने ने एड्रियन मान्नरिनो को 7-5, 3-6, 7-5, 6-2 से, मार्को चेचिनातो ने यसुत्का यचियामा को 3-6, 6-1, 6-2, 6-4 से और एलेक्स डि मिनौर ने स्टेफनो को 6-2, 6-4, 7-6 से हराया।

बोपन्ना-कुगोर की विजयी शुरुआत

भारत के रोहन बोपन्ना और क्रोएशिया के उनके जोड़ीदार फ्रेंको कुगोर की जोड़ी ने जीत से शुरुआत की। बोपन्ना-कुगोर की जोड़ी ने जॉर्जिया के निकोलोज बासिलाश्विली और जर्मनी के आंद्रे बेजेमैन को एक घंटे और एक मिनट तक चले मुकाबले में 6-4, 6-2 से मात दी। बोपन्ना और कुगोर ने पहले सेट में प्रतिद्वंद्वी की सर्विस एक बार और दूसरे में दो बार तोड़ी। अब उनका सामना अमेरिका के निकोलस मुनरो व फ्रांसिस टियाफो और आठवीं वरीयता प्राप्त ब्राजील के मार्शेलो मेलो और पोलैंड के लुकाज कुबोत के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा।

इंग्लैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड मजबूत:कॉनवे का पहला टेस्ट शतक, डेब्यू मैच में लॉर्ड्स में सबसे ज्यादा रन बनाने का गांगुली का रिकॉर्ड भी तोड़ा

नई दिल्ली। लॉर्ड्स में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे 136 रन बनाकर क्रीज पर टिके हुए हैं। दिन की समाप्ति तक न्यूजीलैंड का स्कोर 3 विकेट के नुकसान के बाद 246 रन है। वहीं डेवोन कॉनवे ने डेब्यू मैच में लॉर्ड्स पर सबसे ज्यादा रन बनाने के सौरव गांगुली के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है।

कॉनवे का डेब्यू मैच है। वे लॉर्ड्स पर डेब्यू मैच में शतक बनाने वाले दुनिया के छठे क्रिकेटर हैं। वहीं वे तीसरे गैर ब्रिटिश खिलाड़ी भी हैं, जिन्होंने लॉर्ड्स पर शतक जमाया है। उन्होंने डेब्यू मैच में लॉर्ड्स पर सबसे ज्यादा रन बनाने के सौरव गांगुली के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। गांगुली ने 1996 में लॉर्ड्स में अपने डेब्यू मैच में 131 रन बनाए थे। कॉनवे 136 रन बनाकर क्रीज पर टिके हुए हैं। अभी चार दिनों का खेल बाकी है। गांगुली से पहले लॉर्ड्स में डेब्यू मैच में शतक बनाने वाले गैर ब्रिटिश खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के हैरी ग्राहम थे। उन्होंने 1893 में इंग्लैंड के खिलाफ 107 रन बनाए थे।

सौरव गांगुली और कॉनवे का जन्म एक ही दिन

सौरव गांगुली और कॉनवे का जन्मदिन एक ही दिन है। दोनों का जन्मदिन 8 जुलाई है। गांगुली का जन्म 8 जुलाई 1972 को कोलकाता में हुआ था। जबकि डेवोन कॉनवे का जन्म साउथ अफ्रीका की राजधानी जोहान्सबर्ग में साल 1991 में हुआ था।

कॉनवे और हेनरी निकोल्स क्रीज पर

न्यूजीलैंड ने पहले टेस्ट में पहले दिन की समाप्ति तक तीन विकेट के नुकसान पर 246 रन बना लिए हैं। कॉनवे और हेनरी निकोल्स क्रीज पर हैं। न्यूजीलैंड का पहला विकेट 58 रन पर गिरा। ओपनर टॉम लाथम 57 गेंदों पर 23 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं केन विलियम्सन भी 31 गेदों पर 13 रन बनाकर आउट हो गए। जबकि रोस टेलर ने 38 गेंदों पर 14 रन बनाए। कॉनवे 240 गेंदों पर 136 रन और निकोल्स 149 गेंदों पर 46 रन बना कर क्रीज पर हैं।

एक बार फिर साथ दिखेगी बोपन्ना-कुरैशी की जोड़ी, इस टूर्नामेंट में एक साथ खेलेगा भारत और पाकिस्तान

नई दिल्ली। 'भारत-पाक एक्सप्रेस' के नाम से मशहूर रोहन बोपन्ना और ऐसाम-उल-हक कुरैशी की जोड़ी छह साल के बाद एक बार फिर से 15 मार्च से मेक्सिको में खेले जाने वाले अकापुल्को एटीपी 500 में टेनिस कोर्ट पर एक साथ दिखेगी। इससे पहले यह जोड़ी 2014 शेनजेन एटीपी 250 प्रतियोगिता में एक साथ खेली थी। फिलहाल यह एक टूर्नामेंट के लिए ही फिर साथ आये हैं क्योंकि इनकी संयुक्त रैंकिंग इतनी नहीं है कि इन्हें बड़े टूर्नामेंटों में साथ खेलने का मौका मिल सके। ऐसाम रैंकिंग में 49वें और बोपन्ना 40वें स्थान पर है। उनकी संयुक्त रैंकिंग 89 है। इस जोड़ी की सबसे बड़ी सफलता 2010 में यूएस ओपन के फाइनल में पहुंचना था, जहां उन्हें ब्रायन बंधुओं की जोड़ी से हार का सामना करना पड़ा था। बोपन्ना उस समय अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग तीसरे स्थान तक पहुंचे थे बोपन्ना ने इसके बाद 2012 ओलंपिक की तैयारियों के लिए दिग्गज महेश भूपति के साथ जोड़ी बनाकर खेलने का फैसला किया।

भारत और पाकिस्तान के 40 बरस के इन खिलाड़ियों की जोड़ी फिलहास सिर्फ एक टूर्नामेंट में साथ खेलेगी। कुरैशी ने पीटीआई-भाषा से कहा, 'अभी हम सिर्फ मैक्सिको में खेलने के लिए एक साथ आ रहे हैं। अभी तक हमने भविष्य के बारे में बात नहीं की है। यह पूछे जाने पर कि क्या यह एक लंबी अवधि की व्यवस्था हो सकती है, कुरैशी ने कहा, 'उम्मीद है, अगर यह अच्छी तरह से चलता है तो हम भविष्य में साथ में और अधिक टूर्नामेंट खेल सकते हैं। पाकिस्तान के इस टेनिस दिग्गज ने कहा कि वे वास्तव में दुबई ड्यूटी फ्री चैंपियनशिप में एक साथ प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी योजना सफल नहीं हुई। उन्होंने कहा, 'हमने ऑस्ट्रेलिया में एक साथ बहुत समय बिताया। हम दुबई में खेलने की योजना बना रहे थे।

फ्रेंच ओपन: ज्वेरेव पांचवीं बार तीसरे दौर में, रूस के सेफुलिन को किया पराजित

पेरिस। दुनिया के छठे नंबर के खिलाड़ी जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने लगातार चौथी और कुल पांचवीं बार साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन के तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया। पहले ग्रैंड स्लैम खिताब के लिए खेल रहे ज्वेरेव ने रूस के क्वालिफायर रोमन सेफुलिन को 7-6, 6-3, 7-6 से पराजित किया। अगले दौर में ज्वेरेव की टक्कर सर्बिया के लास्लो जेरे से होगी, जिन्होंने दो सेट गंवाने के बाद हमवतन मिओमिर को 4-6, 4-6, 6-3, 6-2, 6-3 से हराया। ग्रीस के स्टेफानोस सितसिपास ने पेड्रो मार्टिनेज को 6-3, 6-4, 6-3 से और जापान के कई निशिकोरी ने कारेन खाचानोव को 4-6, 6-2, 2-6, 6-4, 6-4 से मात दी।

रेली ओपेल्का ने जैम मुनारी को 6-3, 6-2, 3-6, 7-5 से, जॉन इस्नेर ने फिलिप को 7-6, 6-1, 7-6 से, फैबियो फोगनिनी ने मार्टिन फूकोविक्स को 7-6, 6-1, 6-2 से, कैस्पर रूड ने कैमिल को 6-3, 6-2, 6-4 से, एलेजांद्रो डेविडोविच फोकिना ने बॉटिक वान को 6-4, 6-4, 5-7, 2-6, 6-4 से और फेडरिको डेलबोनिस ने पाब्लो अंदुजार को 4-6, 6-1, 3-6, 6-3, 6-2 से शिकस्त देकर तीसरे दौर में जगह बनाई।

क्वालिफायर हेनरी ने किया बतिस्ता को बाहर

स्विट्जरलैंड के क्वालिफायर हेनरी लाकसोनेन ने दुनिया के 11वें नंबर के खिलाड़ी रॉबर्टो बुतिस्ता अगुत को 6-3, 2-6, 6-3, 6-2 से हराकर पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के तीसरे दौर का टिकट कटाया। हेनरी की यह शीर्ष बीस में शुमार किसी खिलाड़ी पर पहली जीत है।

जोकोविच लगातार 17वीं बार दूसरे दौर में

दुनिया के नंबर एक टेनिस खिलाड़ी और गत उपविजेता नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन में जीत के साथ आगाज किया।

सर्बियाई खिलाड़ी जोकोविच ने अमेरिका के टेनिस सैंडग्रेन को 6-2, 6-4, 6-2 से हराकर लगातार 17वीं बार रौलां गैरां के दूसरे दौर में प्रवेश किया। जोकोविच ने और सैंडग्रेन के बीच यह मुकाबला रात को खेला गया।इस तरह से वह पेरिस की लाल बजरी पर रात्रि मुकाबला जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बने। अब अगले दौर में 18 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन जोकोविच का सामना पाब्लो क्यूवास से होगा।

जोकोविच की यह इस सत्र की 24 मैचों में 21वीं जीत है। जोकोविच ने 2016 में यहां खिताब जीता था अगर वह इस बार भी ट्रॉफी जीत लेते हैं तो ओपन युग (1968 के बाद) में चारों ग्रैंड स्लैम खिताब दो-दो बार जीतने वाले दुनिया के पहले पुरुष खिलाड़ी बन जाएंगे।

दारिया ने 76 मिनट में की बेलिंडा की छुट्टी

दुनिया की दसवें नंबर की खिलाड़ी स्विट्जरलैंड की बेलिंडा बेसिंस दूसरे दौर में ही उलटफेर का शिकार होकर बाहर हो गईं। बेलिंडा को रूस की दारिया कास्तकिना के हाथों 76 मिनट तक चले मुकाबले में 6-2, 6-2 से हार मिली। दारिया का सामना अब सोराना क्रिस्टिया से होगा, जिन्होंने मार्टिना को 6-4, 3-6, 6-4 से हराया।

रोमानियाई खिलाड़ी सोराना सात साल बाद रोलां गैरां के तीसरे दौर में पहुंचीं। अन्य मैचों में विक्टोरिया अजारेंका ने क्लारा टोसन को 7-5, 6-4 से, मेडिसन कीज ने लिलाह एनी फर्नांडिज को 6-1, 7-5 से, डेनिएल रोज कोलिंस ने अनहेलीना कलिनिना को 6-0, 6-2 से, पोउला बडोसा ने डंका कोविनिक को 6-2, 6-0 से, मार्केटा ने हरमोनी टन को 6-1, 6-3 से, पोलोना हर्काज ने कैरोलिन गार्सिया को 7-5, 6-4 से, कैटरीना सिनिकोवा ने वेरोनिका को 7-6, 5-7, 7-5 से और तमारा ने मेडिसन ब्रेगले को 6-4, 6-1 से मात देकर तीसरे दौर में जगह बनाई।

अंकिता और शरण हारे

भारत की अंकिता रैना और दिविज शरण युगल में अपने-अपने जोड़ीदारों के साथ पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए। अंकिता व अमेरिका की लॉरेन डेविस को लॉरा सिगमुंड व लूसी की जोड़ी से 4-6, 4-6 से शिकस्त मिली। शरण व अर्जेंटीना के फेडरिको डेलबोनिस की जोड़ी को ऑस्ट्रेलिया के मैट रीड व एलेक्स डि मिनौर के हाथों 6-3, 6-7, 4-6 से हार मिली।